हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

19.03.2026/1100/RKS/YK-1

अध्यक्ष : आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। आज प्रथम नवरात्र है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब प्रश्नकाल शुरू करते हैं।

स्थगित **प्रश्न संख्या : 3698**

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्थगित प्रश्न है। यह प्रश्न मैंने लगभग एक वर्ष पूर्व पूछा था किन्तु आज तक मुझे इस प्रश्न की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। यदि सरकार के पास अभी तक इस प्रश्न की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है तो कम-से-कम यह अवश्य बताया जाए कि अब तक कितने आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया है। मुझे यह भी बताया जाए कि इस प्रश्न की पूर्ण सूचना मुझे कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जल्द ही सूचना एकत्रित करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये लोग जवाब देने से कब तक और कहां-कहां बचेंगे? आपने वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी लेकिन इसके विपरीत 15 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा से बाहर कर दिया गया। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आउटसोर्स के तहत कार्यरत कर्मचारियों में से कितनों को सेवा से हटाया गया है। सेवा से हटाए जाने के बाद जो कर्मचारी शेष हैं, क्या उन्हें प्रत्येक माह वेतन दिया जा रहा है? क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि इन कर्मचारियों को 6-6 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। आउटसोर्स की सारी एजेंसियां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से संबंधित हैं। कुछ जगह आप भर्ती के लिए जो इंटरव्यू करवा रहे हैं उन इंटरव्यूज से पहले अभ्यर्थियों से पैसा लिया जा रहा है। क्या यह तथ्य आपकी जानकारी में है? अभ्यर्थियों का चयन होगा या नहीं लेकिन इंटरव्यू से पहले एजेंसी वाले

उनसे पैसे मांग रहे हैं। अगर यह बात आपकी जानकारी में है तो आप कृपया इसकी सूचना हमें दें।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1105/बी.एस./वाई.के.-1

प्रश्न संख्याः 3698 जारी...

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी वैसे तो आपने माननीय सदन को बता दिया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है फिर भी there are certain aspersions which is causing, you can deny that.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष के पास कोई ऐसी जानकारी है तो कृपया मुझे आप बता दीजिए और जो पैसा ले रहे हैं उनकी जानकारी भी दे दीजिए नहीं तो सदन में झूठ बोलने के लिए आपके खिलाफ प्रिविलेज बनेगा। लेकिन यह सब विधान सभा पटल की बातें हैं। परंतु मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास इस बारे में कोई जानकारी है तो मुझे बताइए।

श्री जय राम ठाकुर : क्या मुख्य मंत्री जी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे?

मुख्य मंत्री : बिल्कुल करेंगे, हम तो हर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आप हद कर रहे हैं।

स्थगित प्रश्न संख्याः 3733

मुख्य मंत्री : सूचना एकत्रित की जा रही है।

19.03.2025/1105/बी.एस./वाई.के.-2

प्रश्न संख्याः 3906

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो जवाब आया है उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजिज में चमियाना से लेकर स्वास्थ्य संस्थानों में मैं जो टोटल कर रहा था 5161 पद स्वीकृत है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के 2337 पद स्वीकृत हैं और उनमें 2159 भरे हुए हैं। इसमें जो स्वीकृत विशेषज्ञ के पद 683 है और भरे हुए 447 हैं। बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो आंकड़ा पेश किया उसके मुताबिक मैं देख रहा था कि 2337 चिकित्सकों के, फिर 683 पद विशेषज्ञों के, उनके बाद इन्होंने अलग से कहा कि चमियाना में 81 और उसके बाद इन्होंने कहा कि एम0डी0एम0एस0 और डी0एम0बी0 संकाय के 2,060 पद स्वीकृत हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर टोटल आंकड़ा जोड़ा जाए तो यह 5161 बन रहा है। क्या इतने पद वर्तमान में खाली हैं? दूसरा सरकार ने कहा है कि हम प्रदेश में रोजगार की ओर विशेष ध्यान देंगे लेकिन मैंने प्रश्न पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में कितने डॉक्टर्ज बेरोजगार हैं? जिनका नाम पंजीकृत है। लेकिन सरकार की ओर से जो मुझे जवाब आया उसमें कहा गया कि इस संदर्भ में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास यही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने डॉक्टर्ज बेरोजगार हैं? मैं इस पर भी मंत्री जी से जवाब चाहता हूं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिंता जताई है वह ठीक है, मैं समझता हूं कि 6 मेडिकल कॉलेजिज में जहां-जहां भी हम लोगों ने जरूरत समझी और जिस प्रकार से हमारे पास रिक्वायरमैंट आई है उसके अनुसार मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो 2337 पद स्वीकृत है उनमें से 2159 भरे हुए हैं। इसका जो बीच का गैप है उसे भरने की पूरी प्रक्रिया की जा रही है और जो बेरोजगार की आपने बात कही वह नो डाउट कि हमारे पास ट्रेंड होकर जो पूरे डाक्टर्ज आ जाते हैं उन सबको हम एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1110/DT/AG-1

प्रश्न संख्या 3906 जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी..

बीच का जो गेप उसे भरने के लिए पूरी प्रक्रिया की जा रही है। जहां तक मेडिकल या पैरा मेडिकल स्टॉफ के संबंध में बेरोजगारी की बात कही गई है, जितनी भी व्यक्ति ट्रेंड हो कर आते हैं हम उन सभी को आब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीनियर रेजिडेंट्स के पदों में हम प्रदेश के डाकटर्ज को ही नियुक्त कर रहे हैं और कुछ डाक्टर्ज नीजि स्वास्थ्य संस्थानों में भी चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम इन डाक्टर्ज को प्रदेश के छः के छः मेडिकल कॉलेजिज और अटल इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पैशलिटी, चमियाणा, शिमला उनमें भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

Speaker : Hon'ble Chief Minsiter wants to supplement.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है। **मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगले छः महीने में प्रदेश कि किसी भी पी0एच0सी0 में डाक्टर की कमी नहीं होगी। हर पी0एच0सी0 में डाक्टर की नियुक्ति कर दी जाएगी।** Provided that कि जब राजनैतिक आधार पर कभी किसी डाक्टर की ट्रांसफर होने के कारण कही पद खाली हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार तीन सालों में चार सौ एम0बी0बी0एस0 डाक्टर्ज की भर्ती की जा रही है। 162 डाक्टर्ज को नियुक्ति पत्र भेज दिया गया था और वे ज्वाइन भी कर गये हैं। इसके अतिरिक्त डाक्टर्ज के

236 पदों के लिए लिखित परीक्षा हो चुकि है और जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा हे।

माननीय सदस्य ने मेडिकल एग्जूकेशन से संबंधित प्रश्न पूछा है, चुंकि यह विभाग मेरे पास है इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, आई0जी0एम0सी0 और आर0पी0एम0सी0 को छोड़, शेष चार मेडिकल कॉलेजिज केवल नाम के मेडिकल कॉलेज रह गये हैं। हमने मेडिकल कॉलजिज खोल दिए उनके लिए भवन भी बना दिए, इंस्ट्रूमेंट भी नए खरीद लिए, लेकिन इन मेडिकल कॉलेजिज में अगर फैक्लटी की बात की जाए तो उसमें हालात ज्यादा ठीक नहीं हैं। मै जिस भी मेडिकल कॉलेज में गया चाहे वह नाहन का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नेर चोक स्थित मेडिकल कॉलेज हो, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, मैंने सब जगह वहां के प्रशासन और डाक्टर्ज के साथ इंटरेक्शन किया लेकिन सब जगह पाया गया कि वहां फैक्लटी ही पूरी नहीं

19.03.2026/1110/DT/AG-2

है। अगर हम आई0जी0एम0सी0 शिमला और आर0पी0एम0सी0 टांडा की बात करें वहां पिछले कल ही कुछ सीटें भरी गई हैं। 40 सालों में इन मेडिकल कॉलेजिज में जितनी सीट्स बढ़ीं हैं हम अगले तीन सालों में इन पी0जी0 की सीटस को डबल करने जा रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेजिज अच्छे ढंग से चल सकें। आप को यह जानकर प्रसन्नता होगी की चंबा में भी हम बहुत जल्द पी0जी0 की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा भी कई बार मुझसे इस संदर्भ में बात हुई है और आपने विधान सभा में भी कई बार अधिकारियों को बुला कर इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। इसलिए हम प्रदेश में पहली बार पी0जी0 की सीट्स बढ़ाने जा रहे हैं और तकरीबन 200 पी0जी0 की सीट्स हम इंक्रीज करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने यह कहा कि हम एसिटेंट प्रोफैसर, एसासिऐट प्रोफैसर के आर0एण्ड0पी0 रूल्ज को रिलैक्स करेंगे ताकि ये मेडिकल कॉलेजिज अच्छी तरह चल सकें।

जहां तक इन कॉलेजिज में स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों की बात है मैं इसके संबंध में यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई आम आदमी किसी मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसे कम-से-कम यह तो पता लगना चाहिए कि उसे बिमारी क्या है यानी हमारे मेडिकल

कॉलेज रैफरल हॉस्पिटल नहीं बनने चाहिए। इसके लिए हम टेक्नॉलोजी की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश के कुछेक मेडिकल कॉलेजिज की फेक्लटी को मजबूत करना चाहते हैं। सब जगह फेक्लटी को स्ट्रेन्थन करने में अभी समय लगेगा। इस लिए कुछ कॉलेजिज में कुछ एक विभागों की फेक्लटीज जैसे डायग्नोज है, ओ0बी0जी0 है, कार्डिक है, पैथलॉजी है, यानी फर्स्ट स्टेच में क्या बिमारी है उस व्यवस्था को स्ट्रेन्थन करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेजिज खुल गये हैं जबकि ठीक-ठाक तीन या चार मेडिकल कॉलेजिज होने चाहिए थे। अब प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 120 सीट्स हो गई हैं। हम इन मेडिकल कॉलेजिज को स्ट्रेन्थन करेंगे हम इन्हे बंद नहीं करें, नेता प्रतिपक्ष इन्हें बंद करने की बात कर रहे हैं, हम इन्हें बंद नहीं करेंगे। मैं किसी भी मेडिकल कॉलेज को बंद करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं श्री जय राम ठाकुर जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मेडिकल कॉलेज बंद कर दो। यह चीज गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने स्कूल्ज बंद किये हैं उस बात को हम स्वीकार भी हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि अगले एक वर्ष के भीतर हैल्थ टूरिज्म की तरफ भी हम बढ़ेंगे और सारे मेडिकल कॉलेजिज में कुछ विभागों की फेक्लटीज को हम स्ट्रेन्थन करेंगे। इसके लिए हमें नई

19.03.2026/1110/DT/AG-3

नियुक्तियां भी करनी पड़ी तो हम नई नियुक्तियां भी करेंगे। इन्हीं मेंडिकल कॉलेजिज को स्ट्रेन्थन करने के लिए मैं एक और बात बताना चाहा रहा हूं कि हमारे प्रदेश में जो डिप्लोमा कोर्सिज होते थे उसमें जैसे एनेस्थेटिस्ट 18 पद थे ओ0टी0 अटेंडेंट की 18 पोस्ट हमारे दो मेडिकल कॉलेजिज यानी आई0जी0एम0सी0 या आर0पी0एम0सी0 में थी, उन्हें बढ़ा कर हमने इन्हें 50-50 पद किया ताकि जो रेडियोग्राफर की शोर्टेज हो रही है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2026/1115/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3906.....जारी मुख्य मंत्री..... जारी

वह अगले दो वर्षों में पूरी कर दी जाए। हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज को अलग से स्ट्रेंथन कर रही है। डी0एम0ई0 का कैडर अलग कर दिया गया है। हमारी सरकार डायरेक्ट्रेट ऑफ हैल्थ सर्विसिज़ को अलग से स्ट्रेंथन कर रही है और उनका कैडर भी अलग कर दिया गया है। **हमें अभी रेशनेलाइजेशन करने की जरूरत है और इसके संदर्भ में भविष्य में विचार किया जा सकता है।**...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है।...(व्यवधान) इन्होंने कोई प्रश्न खड़े नहीं किए हैं।...(व्यवधान) इन्होंने कहा है कि 6 माह में सारी रिक्तियां भर दी जाएंगी। अगले एक साल में मेडिकल कॉलेज में पी0जी0 की जितनी पोस्टें रिक्त हैं, वे सारी शुरू करके भर दी जाएंगी। He has assured this House that in the next one year...(व्यवधान) श्री राकेश जम्वाल जी ने पूछना है या श्री जय राम ठाकुर जी ने प्रश्न करना है? ...(व्यवधान) ठीक है, श्री जय राम ठाकुर जी, आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये सारी (***) हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : जब प्रूव होंगी तब देखेंगे, अभी कोई (***) नहीं हैं।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है और ये सारी (***) हैं। इसके अलावा (***) करने में इनका कुछ नहीं लगता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा नहीं है। माननीय सदन के नेता बोल रहे हैं और हमें इन पर विश्वास करना चाहिए।

19.03.2026/1115/ए.जी.-एन.जी./2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, एक वक्त था हिमाचल प्रदेश में वॉक-इन-इंटरव्यू होता था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह (***) शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी तरह कह देता हूं कि इनकी बातें फैक्ट्स पर नहीं हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा दिया है लेकिन वह सच्चाई नहीं है। एक वक्त था जब हिमाचल प्रदेश में वॉक-इन-इंटरव्यू होता था। जब कोई बच्चा पास होता था तो कैम्पस इंटरव्यू से ही उसको डॉक्टर की नौकरी मिल जाती थी क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स की शोर्टेज़ होती थी और पोस्टें खाली रहती थीं। उसके बाद सरकारी क्षेत्र में 6 मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सैक्टर में एक मेडिकल कॉलेज होने के कारण हमारे हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की संख्या में काफी बढ़ौतरी हुई। इसके अलावा दूसरे देशों जैसे यूक्रेन, चीन व रूस, से भी बच्चे ट्रेनिंग करके प्रदेश में आ गए हैं और उनका नम्बर भी बहुत ज्यादा है। मैं जब मुख्य मंत्री था तब मेरे पास कुछ बच्चे आए और उन्होंने बताया कि एम0बी0बी0एस0 करने के बाद 700 बच्चे अनेक महिनों तक नौकरी की तलाश कर रहे हैं और उन्हें डॉक्टर की नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद हमारी सरकार ने एक साथ 500 डॉक्टर के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की और 500 पदों में से 300 पदों को हमारी सरकार ने भर भी दिया था। मुख्य मंत्री जी, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि 500 पदों में से 300 पद हमारी सरकार ने भर दिए थे और 200 पदों को भरने के समय तक चुनाव आ चुका था? मुख्य मंत्री जी, जो पोस्टें हमारी सरकार ने स्वीकृत की थी और वित्त विभाग से उनकी मंजूरी भी मिल गई थी, उन्हीं पोस्टों को भरने के लिए you took more than two years. आप अपनी सरकार के कार्यकाल में जिन पदों को भरने की बात कर रहे हैं, वे वही पोस्टें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में स्वीकृति प्रदान की गई थी और आपने उन्हीं पोस्टों को भरने के लिए 3 साल से ज्यादा का समय लगा दिया।...(व्यवधान)

(* * *)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

19.03.2026/1115/ए.जी.-एन.जी./3

मुख्य मंत्री : नेता प्रतिपक्ष जी, आप यह बता दीजिए कि आपकी सरकार ने उन पदों को कौन से निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत किया था?

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री जी, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत ही स्वीकृत होंगी, इसके अलावा और कौन-सा निदेशालय है?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, Cabinet approval was for 500 posts और उनमें से 300 पोस्टों को भर दिया गया था तथा 200 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। They took 2-1/2 years to fill those posts.

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के पास यह आंकड़ा ही नहीं है और यह एक विचित्र परिस्थिति है। एक बच्चा पांच साल तक पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनता है और आज वह बेरोजगार है। उनका पंजीकरण किया जाता है और सरकार के पास उनका पूरा रिकॉर्ड होता है। यहां पर सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे पास सूचना नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों से डॉक्टर की पढ़ाई करके आते हैं उनका भी राष्ट्रीय स्तर पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद उनका भी पंजीकरण किया जाता है तथा उसका भी रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। हम कह रहे हैं कि

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1120/ए.पी. /ए.एस. -1

प्रश्न संख्या : 3906 जारी ....श्री जय राम ठाकुर जारी .....

कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो पास होने के बाद भी इस समय देश और प्रदेश में बेरोजगार हैं? दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि स्पेशलिस्ट की सारी पोस्टें भर दी गई हैं। पहले आप यह पता तो करें कि कितनी पोस्टें भरी गई हैं? हाल ही में मैं मेडिकल कॉलेज नेरचौक गया था, वहां पर रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट खाली है।

अध्यक्ष : इन्होंने खुद एडमिट किया है कि बहुत सारी पोस्टें स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट की अभी भी खाली हैं। इसलिए हम सभी मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. की क्लासेज शुरू करवा रहे हैं। This is what he said.

श्री जय राम ठाकुर : माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या आप इन सारी चीज़ों की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे? क्या आप यह भी बताएंगे कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट जो खाली पड़ी है, उसके कारण वहां पर सारा काम रुका पड़ा हुआ है। उस पोस्ट को आप भरने की बात करेंगे।

अध्यक्ष : आपका एक Walk-in-interview वाला ठीक है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विचित्र परिस्थितियां हैं। माननीय विपक्ष के नेता अनुपूरक प्रश्न करने के लिए हाथ उठाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और वे अच्छा प्रश्न भी पूछते हैं। मैंने इनसे पूछा है कि आप बताएं कि किस डायरेक्टरेट के तहत Walk-in-interview की 300 पोस्टों को सैंक्शन किया गया है। हमने क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन की दिशा में काम करना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज की नियुक्तियों को अलग किया है ताकि वे मेडिकल कॉलेजों की पोस्टों में न आ

सकें। हमने पहले 200 पोस्टों को सैंक्शन किया है। यह किसी तरह की continuation process से नहीं होता है।

19.03.2026/1120/ए.पी. /ए.एस. -2

...(व्यवधान) आप सुनो तो सही, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो। दूसरी बात यह कि जो सैंक्शन की गई पोस्टें थीं, उनमें हम 236 पोस्टों का फिर से इंटरव्यू करवा रहे हैं ताकि हेल्थ विभाग में कोई भी पी0एच0सी0 खाली न रहे। इसी दृष्टिकोण से सबसे पहले हमने कैडर को अलग किया। यह डी0एम0ई0 के तहत नहीं किया जा रहा है, बल्कि डी0एच0एस0 के तहत किया जा रहा है। आप मुख्य मंत्री रहे हैं, आपको इस बारे में पता होना चाहिए था कि डी0एम0ई0 और डी0एच0एस0 दोनों अलग-अलग हैं। इतनी जानकारी तो आपको होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही जा रही है कि देश और प्रदेश में कितने डॉक्टर अभी भी बेरोजगार हैं। मैं माननीय नड्डा जी से सूचना एकत्रित करूंगा, फिर आपको बता पाऊँगा कि देश में कितने डॉक्टर हैं जो अभी भी बेरोजगार हैं। ...(व्यवधान) (आप अभी रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि इन्होंने देश और प्रदेश में कितने डॉक्टर बेरोजगार है ऐसा कहा है।)

अध्यक्ष : इन्होंने यह कहा कि कुछ डॉक्टरों ने प्रदेश से डॉक्टरी की और कुछ बाहरी राज्यों से भी डॉक्टरी कर के आए हैं। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अच्छा चलिए ...(व्यवधान) आप अपना रिकॉर्ड निकलवा लेना। अगर गलत बोला हो...(व्यवधान) पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी, आप अपनी गलतियों में सुधार करें। आप अपनी गलतियों में सुधार नहीं करते हैं। आप अपनी गलती मान लीजिए, गलती मानना अच्छी बात होती है।...(व्यवधान)

Speaker : Shri Jai Ram Thakur ji, please take your seat. Let him explain. ...(Interruption) मैं आपको अनुपूरक प्रश्न करने का मौका दूंगा, अगर जरूरत हुई। ...(व्यवधान) Please don't take it very seriously, take it in a lighter and casual way.

19.03.2026/1120/ए.पी. /ए.एस. -3

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके गुस्से को जानता हूं और मैंने पहले भी कहा है कि एक पानी का गिलास बर्फ डालकर इनके पास रखा करें। मैंने हमेशा यही कहा है कि हम हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नेरचौक में जिस रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट की पूर्व मुख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं, उनके समय वहां पर एम0आर0आई0 की मशीन नहीं थी। ...(व्यवधान) अभी एम0आर0आई0 की मशीन हमारी सरकार के समय सैंक्शन हुई है और उसका ऑर्डर भी कर दिया गया है। उस ऑर्डर के तहत मशीन आ जाएगी।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप दो-तीन बातों को क्लेरिफाई कर दो।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब हमारी एम0आर0आई0 और सी0टी0 स्कैन की मशीनें आएंगी, तब हम रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि ओ0बी0जी0, रेडियोलॉजिस्ट विभाग और रेडियोग्राफर की पोस्टों को मज़बूत करने की ज़रूरत है। लेकिन यह बात सुनते ही नहीं है, स्वयं ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.03.2026/1125/AT/AS/01

प्रश्न संख्या 3906 जारी..मुख्य मंत्री जारी...

डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में अगले छह महीने में जो कहा है और अगले कुछ समय में उसके आगे मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है इसलिए हम उस कार्य को कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को सशक्त करें अभी तक हम आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज को सशक्त कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी मेडिकल कॉलेजों को सशक्त करने की भी आवश्यकता है।

19.03.2026/1125/AT/AS/02

प्रश्न संख्या 3907

श्री केवल सिंह पठानियाः माननीय अध्यक्ष महोदय, टांडा मेडिकल कॉलेज के संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो जानकारी आई है उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि पिछले तीन वर्षों में जिला कांगड़ा के अंदर टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए 85,23,74,482/- रुपये खर्च किए गए हैं। मैं कांगड़ा और चंबा की जनता की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यह हमारी लाइफ लाइन है टांडा मेडिकल कॉलेज और आपने सबसे ज्यादा पैसा यहां खर्च किया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें मंडी और हमीरपुर के लोग भी आते हैं।

श्री केवल सिंह पठानियाः सर, इस पर मैं सप्लीमेंट्री में आऊंगा। इसके बाद मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सितंबर महीने में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। कल भी जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तब इसका जिक्र हुआ। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, लगभग 95 रोबोटिक सर्जरी हुई हैं जो कभी किसी गरीब आदमी ने सोचा भी नहीं था। इसके लिए मैं रोबोटिक सर्जन और इस व्यवस्था परिवर्तन की सराहना करता हूं। यह वही व्यवस्था परिवर्तन है जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कंप्यूटर युग की बात की थी। उसी के अंतर्गत यह रोबोटिक तकनीक की बात हुई थी। अभी हाल ही में 25 रोबोटिक सर्जरी हिमाचल प्रदेश के अस्पताल में हुए है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ किडनी ट्रांसप्लांट भी कांगड़ा और चंबा के लिए लाइफ लाइन है।

Speaker : Please, order in the House.

19.03.2026/1125/AT/AS/03

श्री केवल सिंह पठानियाः पहले यह किडनी ट्रांसप्लांट चंडीगढ़ में होता था लेकिन अब इसका विभाग यहां आ गया है। 21 में से 21 किडनी ट्रांसप्लांट सफल हुए हैं और 16 किडनी ट्रांसप्लांट अभी लंबित हैं। इसके साथ-साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 21 लिफ्ट में से 7 लिफ्टों के लिए 4 करोड़ 40 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी के संदर्भ में, टांडा के अलावा मंडी और अन्य मेडिकल कॉलेजों जो मैंने मण्डी, चंबा ...(व्यवधान) आप जब पूछ रहे हैं तो मैं बीच में बोलता नहीं हूं।

Speaker : Please, don't pay attention. माननीय सदस्य श्री केवल पठाानिया जी इन की तरफ ध्यान मत दीजिए। ...(व्यवधान) Please, no disturbance please.

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टांडा मेडिकल कॉलेज और अन्य मेडिकल कॉलेजों में आने वाले समय में एम0आर0आई0 हो चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, कौन-कौन से कदम वर्तमान में मेडिकल एजुकेशन में उठाए जा रहे हैं? यह मैं जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय। Please, order in the House. माननीय सदस्य बीच में बैठकर न बोला करें।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें रखी हैं। एक टांडा के संदर्भ में है। मैं टांडा मेडिकल कॉलेज की स्थिति बताना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने रखी। यहां पर भी एस0आर0 की पोस्टें स्वीकृत नहीं थी, वह भी हमने इसी वर्ष स्वीकृत कि ताकि मेडिकल कॉलेज सही तरीके से चल सके।

इसके अलावा, मैं और एक बात बताना चाह रहा हूं कि वहां भी 10-15 साल पुरानी मशीनें थीं, जिन्हें हमने बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पहला चरण शुरू हुआ है यह कई

चरणों में मेडिकल कॉलेज को रिफोर्म किया जाता है। लेकिन इन मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, महल डॉक्टर नहीं चाहिए बल्कि मशीनें भी चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ और फैकल्टी भी चाहिए। कुछ फैकल्टी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन

19.03.2026/1125/AT/AS/04

कई फैकल्टी में हम कमजोर हैं, हम कमजोर फैकल्टी को सशक्त करेंगे।हमारी सरकार टांडा मेडिकल कॉलेज और अन्य मेडिकल कॉलेजों में आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 से ज्यादा पद भरने जा रही है और वह पद राज्य चयन आयोग के द्वारा भरे जाएंगे। हम वॉक-इन-इंटरव्यू इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि जो भी डॉक्टर आएं वह लिखित परीक्षा के माध्यम से आए। इसलिए हम सभी जगह लिखित परीक्षा करवा रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेज में जो भी डॉक्टर जाए या जो हमारे हेल्थ सर्विस में जो भी डॉक्टर जाए, वह गुणवत्ता वाले डॉक्टर मेडिकल अस्पताल में आए और सभी को मौका मिले

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1130/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या : 3907 जारी--मुख्य मंत्री जारी ---

वाक-इन-इंटरव्यू में कई सिफारिश लगा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। इसके अलावा हमने एक और परिवर्तन किया। जो लिखित परीक्षा की मैरिट पहले 30 और 35 नम्बर थी कि 30 नम्बर वाला भी केटेगरी से पास मान लिया जाता था उसमें भी हमने चेंजिंग की। 40 और 45 नम्बर वाले को पास किया जाएगा ताकि हैल्थ इंस्टीट्यूशन्ज़ में अच्छी चीजें आएं और उस दृष्टिकोण से हम देखें। जहां तक पठानिया जी ने कहा है, कई डॉक्टर हमने एसोसिएट/असिस्टैंट प्रोफैसर लगा दिए। विपिन सिंह परमार जी स्वास्थ्य मंत्री थे। ये जानते हैं कि असिस्टैंट प्रोफैसर के बाद हमें पी0जी0 की सीटें तब

मिलेंगी जब एसोसिएट प्रोफैसर बनेंगे। हम उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। रूल को रिलैक्स करके उनको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि उनको पी0जी0 की सीटें मिलें। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो मैडिकल कॉलेज में शाम को ड्यूटी देते हैं, असिस्टैंट प्रोफैसर और एसोसिएट प्रोफैसर फैकल्टी वाले ड्यूटी नहीं देते। वहां सारे ही एस.आर.शिप वाले होते हैं जो रात की ड्यूटी में कैजुअल्टी, इमरजेंसी या मैडिसिन में होते हैं। उनसे भी हमने इंटरैक्शन की है। इस दृष्टिकोण से भी हम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश में सभी मैडिकल कॉलेजों में टॉप के हैल्थ सिस्टम को डवलप करना है परंतु उसमें अभी समय लगेगा। हम उसकी जड़ तक पहुंच चुके हैं और जड़ में धीरे-धीरे पानी देंगे तभी हरा होगा। हम विपक्ष के साथियों की तरह तो है नहीं कि हम क्वालिटी को नहीं देखेंगे। हम क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैडिकल टैक्नोलॉजी में भी हम 3 हजार करोड़ रुपये के मैडिकल टैक्नोलॉजी के इक्विपमैंट्स खरीदेंगे और एक प्रदेश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूशन जहां कैंसर की रिसर्च भी होगी, वह हम हमीरपुर में बनाने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर उसके लिए काफी जगह है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि एक साल के अंदर मैडिकल कॉलेजों में, टांडा और आई0जी0एम0सी0 में तो आपको 6-7 महीने में नज़र आ जाएगा बाकी चार मैडिकल कॉलेज चलाने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन उनमें भी

19.03.2026/1130/केएस/डीसी/2

आपको सुधार नज़र आएगा। मैं सोलंकी जी को मुबारकवाद देना चाहूंगा, नाहन के मैडिकल कॉलेज में भी हमने पी0जी0 शुरू कर दी हैं। हमने वहां पर डॉक्टरों से इंटरैक्शन की, मेरे साथ वहां के स्थानीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी भी थे। अध्यक्ष जी, चम्बा में भी आपने मुझे कई बार बुला कर बात की है तो वहां भी हमने पी0जी0 के कोर्सिज़ शुरू कर दिए हैं। धन्यवाद। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही डिटेल में बता दिया है कि सरकार के प्रयास हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी और उसके लिए हम ये-ये स्टैप्स उठा रहे हैं। अब इसके आगे तो कोई प्रश्न बनता भी नहीं है। परमार जी, ऐसा है कि डिमांड्ज़ में भी आपने डिस्कस करना है और बजट में भी डिस्कस होना है। अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप नियम- 61 में ले आना, मैं उसमें आपको चर्चा की अनुमति दे दूंगा। ...(व्यवधान) परमार जी, अगला आपका प्रश्न है। आप अपना सवाल कर लीजिए या आज जो आपने चर्चा में भाग लेना है, उसमें सारा कुछ बोल लेना क्योंकि अभी आपने गवर्नर एड्रेस पर चर्चा में भी पार्टिसिपेट करना है, तब बोल लेना। ...(व्यवधान) सप्लीमेंट्री कुछ बन ही नहीं रहा है। अच्छा अपनी सप्लीमेंट्री बताओ तभी मैं अलाउ करुंगा।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यहां पर बहुत विस्तार से बात रखी गई है लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि आप प्रदेश में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो जब से टांडा में रोबोटिक सर्जरी या मशीन लगाई है, नम्बर ऑफ ऑप्रेशन वहां पर कितने हुए? उसमें गायनोकोलॉजी, यूरोलॉजी और सर्जरी के कितने ऑप्रेशन हुए और एक ऑप्रेशन के ऊपर कितना खर्चा आया है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान कार्ड चलते हैं या नहीं? तीसरा, ये जो आप मशीन्ज़ लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये कौन सी कम्पनी की मशीन्ज़ हैं और टेंडर प्रक्रिया किस रूप में अपनाई गई? क्या आप इस सदन में यह सारी जानकारी हमें देंगे कि कंपेरेटिवली एल-1, एल-2 और एल-3, ये कौन-कौन सी कम्पनियां आईं और किस आधार पर यह काम अवार्ड किया गया? इसकी प्रतिलिपि आप इस सदन में रखें और उसकी जानकारी मुझे भी दें।

मुख्य मंत्री जी अ0व0 की बारी में---

19.03.2026/1135/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 3907--------- क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जब उत्तर दे रहा होता हूं तो माननीय सदस्य मुझे गौर से नहीं सुनते। वर्ल्ड की एक बैस्ट कम्पनी दावैंची है जोकि 22 वर्षों से यही काम कर रही है। मैं अपने भाषणों में कई बार बोल चुका हूं कि यहां पर एम्ज़ बिलासपुर के स्तर की नहीं अपितु एम्ज़ दिल्ली के स्तर की मशीनें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो मशीन एम्ज़ दिल्ली में खरीदी गई वही मशीन मैंने यहां पर एक करोड़ रुपये सस्ती खरीदी है। ...(व्यवधान) यह टैण्डर प्रक्रिया के माध्यम से ही खरीदी गई है।

अध्यक्ष महोदय, वैसे इन्होंने यह सवाल नहीं पूछा था परंतु मैंने यह जानकारी इनकी गलतफहमी दूर करने के लिए दी है। हर चीज के लिए टैण्डर प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब टैण्डर प्रक्रिया हुई तो हमने पूछा कि एम्ज़ दिल्ली में कितने में खरीदी गई और हम उससे कम में खरीदेंगे

19.03.2026/1135/av/dc/2

प्रश्न संख्या : 3908

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा काफी विस्तार से उत्तर दिया गया है। इसमें एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके विभाग में भिन्न-भिन्न श्रेणी के जो तमाम पद खाली हैं क्या उनको भरने हेतु कैबिनेट से मंजूरी मिली है ताकि प्रदेश में किसान या पशु धन के रूप में जो लोग जीवनयापन करते हैं, उनका कामकाज ठीक से चल सकें और यह प्रक्रिया कब शुरू होगी? इसके अतिरिक्त अखबारों में पशु मित्रों के बारे में भी जानकारी मिल रही है। कृपा करके आप हमें यह भी बताएं कि ये पशु मित्र क्या है? क्या ये पशु मित्र फार्मासिस्ट्स का काम करेंगे या ये किसानों-बागवानों को जिन्होंने पशु धन के रूप में गाय, भैंस, भेड़-बकरियां इत्यादि पाली हैं; एसिस्ट करेंगे? इनके आर0 एण्ड पी0 रूल्ज क्या होंगे और क्या यह तदर्थ व्यवस्था है या स्थाई व्यवस्था है? ये लोग जब हिमाचल प्रदेश में लगाए जाएंगे तो इनका मानदेय क्या होगा? प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाने हेतु ये क्या काम करेंगे? कृपा करके ये सारी जानकारी दी जाए।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विभाग में सीनियर वेटरनेरी ऑफिसर्ज, वेटरनेरी ऑफिसर्ज, चीफ वेटरनेरी फार्मासिस्ट्स, एसिस्टैंट वेटरनेरी फार्मासिस्ट्स, वेटरनेरी फार्मासिस्ट्स और क्लास-iv यानी कुल मिलाकर हमारे पास 2976 सैंक्शन्ड पोस्ट्स हैं जिनमें से भिन्न-भिन्न श्रेणियों की 1517 पोस्ट्स फिलअप की गई हैं तथा 1459 पोस्ट्स खाली हैं। आपने जो पशु मित्रों के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे होस्पिटल्ज में मल्टी पर्पज वर्कर्ज होते हैं उसी तर्ज पर इनको लगाया जाएगा। इनका कार्य ऐसे होगा जैसे कोई पशु आता है तो उसको पकड़ना है और कास्ट्रेशन करनी है। हमने इनकी पहले चरण में 500 पोस्ट्स सैंक्शन की हैं जिसकी डिटेल मेरे पास हैं। प्रदेश के लाहौल-स्पिति में 5, चम्बा में 40, शिमला में 83, कांगड़ा में 123, ऊना में 36, कुल्लू में 14, सोलन में 37, हमीरपुर में 28, सिरमौर में 37, किन्नौर में 13, बिलासपुर में 17 और मण्डी में 67 हैं।

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1140/टी0सी0वी0/एच0के0-1

प्रश्न संख्या : 3908 ... क्रमागत् कृषि मंत्री ... जारी

यानी हम 500 पोस्टों को भरने जा रहे हैं और इनकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनको अभी मिनिमम 5000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और ये विभागीय भर्तियां होंगी। इन पोस्टों को आउटसोर्स पर नहीं भरा जाएगा। पहले चरण में 500 लोग की भर्ती की जाएगी और उसके पश्चात् दूसरे चरण में भी 500 लोगों की भर्तियां की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी vacancy position of doctors and paramedical staff के बारे में भी माननीय सदस्य को जानकारी दे दें।

कृषि मंत्री : पैरा मेडिकल स्टाफ भर्तियां भी चरणबद्ध तरीके से की जाएंगी। जहां-जहां भी इनके पद खाली होंगे उनको भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा ।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, इन पदों को भरने का यह चरणबद्ध तरीका क्या है, यह समझ में नहीं आ रहा है? मेरा मंत्री और मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको कैबिनेट में ले जाइये और उनको भरने की प्रक्रिया शुरू कीजिए।

दूसरा क्योंकि आजकल मैं मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का भी वक्तव्य पढ़ता और सुनता हूं। आप कांगड़ा के डगवार मिल्क प्लांट की बहुत चर्चा कर रहे हैं। आपका एन0डी0डी0बी0, अनंद गुजरात से एक एग्रीमैंट हुआ है, और उसमें चार जिला कवरr हो रहे हैं। उसमें कांगड़ा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : परमार साहब यह प्रश्न डगवार मिल्क प्लांट से संबंधित नहीं है। यह तो वैकेंसी से रिलेटिड प्रश्न है। आप नया प्रश्न पूछ रहे हैं। आप इसको छोड़ो, इस प्रश्न को बाद में पूछ लेना।

श्री विपिन सिंह परमार : सर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह डगवार का मिल्क प्लांट से संबंधित है।

Speaker : This doesn't arise from this question. ...(Interruption) This is entirely a different issue.

19.03.2026/1140/टी0सी0वी0/एच0के0-2

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आर्थिकी की मजबूती के लिए एक नया काम किया है और इसके लिए एक एग्रीमैंट किया गया है इसलिए यदि उसकी जानकारी इस माननीय सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसकी प्रतिलिपि भी सभा पटल पर रखने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : मंत्री महोदय, अगर आपके पास इसके संदर्भ में सूचना उपलब्ध है तो दे दें।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह Dairy Development Authority, Government of India की एक एजेंसी है और उसमें चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना का एक यूनिट बनाया गया है। इन चार जिलों से सोसायटी माध्यम से जो मिल्क आएगा उसको हम डगवार जहां

हम बहुत बड़ा मिल्क प्लांट लगाने जा रहे हैं जिसके ऊपर लगभग 213.14 करोड़ रुपये खर्च होगें, एकत्रित किया जाएगा। यह प्लांट सितम्बर, 2026 तक बन करके तैयार हो जाएगा और हम सोसाइटीज के माध्यम से जो दूध वहां पर एकत्रित करेंगे उसकी byproducts बनेगी। इसका एग्रीमैंट Dairy Development Authority से किया गया है और वह इसका संचालन करेगी। उनका ट्रेडमार्क 'हिम' नाम से हिमाचल प्रदेश सरकार का होगा। वे इसका रख-रखाव करेंगे और इसका सफल ट्रायल होने के पश्चात् इसको अन्य जिलों में भी इम्प्लीमैंट किया जाएगा ।

प्रश्न समाप्त

19.03.2026/1140/टी0सी0वी0/एच0के0-3

प्रश्न संख्या : 3909

कुमारी अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों से धोखा-धड़ी के संबंध में एक प्रश्न लगाया था जिसके जवाब में कहा गया है कि प्रदेश में वर्ष 2025 में 12 किसानों द्वारा धोखाधड़ी के मामले दर्ज करवाए गए हैं। मुझे लगता है कि यह आंकड़ा सिर्फ एफ0आई0आर्ज0 का है लेकिन इसके अलावा जो नॉर्मल कंप्लैंटस दर्ज होती है उसके आंकड़े पूरे प्रदेश में सैकड़ों या हजारों में भी हो सकते हैं क्योंकि मेरे जिला लाहौल-स्पीति में 16 मामले इसमें दर्ज हुए जिसमें से 14 मामले नार्मल कंप्लैंटस के हैं और दो में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है। इसमें सीधे तौर पर एफ0आई0आर0 दर्ज करने का प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि हमारा किसान अपने बच्चों की तरह फसल को बोता है और अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण करता है। उसकी पूरी आर्थिकी उस पर निर्भर करती है और प्रदेश की आर्थिकी में भी एग्रीकल्चर सैक्टर सबसे मेजर रोल निभाता है लेकिन कुछ सालों में जो किसानों के साथ धोखा-धड़ी के कई मामले सामने आए हैं और उसमें उस तरह की कार्रवाई नजर नहीं आती क्योंकि उनको कोर्ट में जाना पड़ता है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1145/NS-HK/1

प्रश्न संख्या : 3909----क्रमागत कुमारी अनुराधा राणा ----जारी

किसी भी मामले की बात की जाए तो कई किसान डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा पाते और वहां पर केसिज सॉल्व होने में लंबा समय लग जाता है । प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि एक मामले में आंशिक धनराशि वसूल की गई है। हम जानते हैं कि आपदा में किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है चाहे वर्ष 2023 की आपदा हो या वर्ष 2025 की आपदा हो। मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे इसमें शीघ्र एफ0आई0आर0 दर्ज हो। दूसरा, किसानों व कम्पनियों या आढ़तियों के बीच में जो कॉंट्रैक्ट होता है तो इसमें सरकार का प्रतिनिधि भी थर्ड पार्टी के तौर पर शामिल हो क्योंकि मैंने इसमें यह पाया है और अगर मैं अपने जिला का उदाहरण दूं तो कॉंट्रैक्ट किसानों व कम्पनी के बीच में होता है। मेरे क्षेत्र में जो आलू किसानों द्वारा बेचा गया था तो उसमें मारूति कम्पनी इन्वॉल्व है और अभी तक किसानों की पेमैंट्स नहीं हुई हैं। जब कॉंट्रैक्ट होता है तो उसमें कई बातें ऐसी हैं जो कम्पनी के हित में लिखी गई होती हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी कोई इस तरह का कॉंट्रैक्ट किसानों व कम्पनियों या आढ़तियों के बीच में हो तो इसमें थर्ड पार्टी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इसमें किसानों के हितों की बात भी हो सके। मेरा मुख्य मंत्री जी से इसके लिए निवेदन रहेगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सिविल मैटर्ज कंप्लेंटस होती हैं उनको एग्जामिन किया जाता है और उसके बाद एक्शन लिया जाता है। कई बार कृषक अपने स्तर पर ही थोड़े पैसे लेकर एग्रीमैंट कर लेता है। उसमें सरकार का ज्यादा इन्वॉल्वमैंट नहीं रहता है। माननीय सदस्या ने मेरे ध्यान में यह बात लाई है तो ऐसे मैटर्ज में हम देखेंगे कि क्या एक्शन लिया जा सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने यह तय नहीं किया है कि आप किसको फसल बेचे। जो पेमैंट नहीं करता है आप उसको अगली बार फसल न बेचे और

उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवाएं और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। यह किसानों को ही करना है और इसको सरकार नहीं करेगी

19-3-2026/1145/NS-HK/2

क्योंकि जो एग्रीव्ड पार्टी होती है तो यह उस पार्टी को करना पड़ेगा हम तभी एक्शन ले सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या बोल रही हैं कि as a safety clause गवर्नमैंट बीच में यानी जहां भी ऐसा एग्रीमैंट हो उसमें Government should stand as a surety to the farmer कि वे जो एग्रीमैंट करे या लेन-देन हो उसको इम्प्लीमैंट करे। Anyway, this is a suggestion for action.

19-3-2026/1145/NS-HK/3

प्रश्न संख्या : 3910

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग विभागों के अंदर विभागों का काम चलाने के लिए सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अलग-अलग ऐसी पॉलिसीज लेकर आती हैं जिससे लोगों को सरकारी क्षेत्र में रखा जाता है। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्ज रखे गए हैं। अप्रैल 2022 में यह पॉलिसी आई थी और उसके अंतर्गत मल्टी टास्क वर्कर्ज लोक निर्माण विभाग में रखे गए ताकि रख-रखाव का काम सही ढंग से हो सके। मैंने इसके उद्देश्यों में देखा तो उसमें ऐसा कहा गया है कि हम लोग ऐसा livelihood यानी 'To provide an opportunity for the eligible unemployed candidates to earn livelihood at local level'. एक तो यह था। दूसरा, उसमें जोड़ा गया है कि 'Right to claim Regular appointment'. उसमें ऐसा जोड़ा गया है कि केंडीडेट कभी भी अपने आपको रेग्युलर करने की बात नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा मानना है कि मानवीय आधार के ऊपर हम सब लोगों को इनके लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि पहले इनको 4500 रुपये पर रखा गया था और अब 5500 रुपये तनख्वाह महीने की मिलती है। मंत्री जी विभागों के अंदर यह देखा गया है कि आउटसोर्स से मल्टी

टास्क वर्कर्ज सबसे ज्यादा काम करते हैं और नौजवान भी हैं तथा पढ़े-लिखे भी हैं। इनका सभी विभागों के अंदर काफी योगदान है। क्या मानवीय आधार के ऊपर इनकी और तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है? वैसे तो इस प्रश्न के उत्तर में दिया गया है कि इनके मानदेय को बढ़ाया गया है। पहले इनको 4500 रुपये मिलते थे, फिर 5000 रुपये और अब 5500 रुपये मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 5500 रुपये से एक व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है? वैसे अमूमन यह माना जाता है कि वे 4 से 5 घंटे काम करेंगे लेकिन विभागों के अंदर वे 8 से 10 घंटे काम करते हैं। सारा काम यही देखते हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2026/1150/RKS/YK-1

प्रश्न संख्या : 3910 जारी....

श्री सतपाल सिंह सत्ती... जारी

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले समय में सरकार इन मल्टी टास्क वर्कर्ज को नियमित करने के लिए कोई नीति बनाएगी ताकि इनकी तनख्वाह या मानदेय भी बढ़ जाए और उन्हें यह भी उम्मीद जगे कि वे कॉंट्रैक्ट में आकर आगे रेगुलर हो जाएंगे। इन कर्मियों का कॉंट्रिब्यूशन भी उतना ही है जितना रेगुलर कर्मियों का है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब जानना चाहूंगा।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सिंह सत्ती ने एक महत्वपूर्ण विषय रखा है। यह मामला PWD के मल्टी टास्क वर्कर्ज के लिए पोलिसी बनाने से संबंधित है लेकिन हमारी संवेदनाएं प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी मल्टी टास्क वर्कर्ज के साथ हैं। चाहे वह शिक्षा विभाग हो, जल शक्ति विभाग हो या अन्य विभागों में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर्ज हों, हमारी संवेदनाएं इन सबके साथ है। जैसा अभी श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने कहा और हमने successively अलग-अलग वित्तीय वर्षों में इनके मानदेय को

बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। मल्टी टास्क वर्कर्ज को प्रतिमाह 4500 रुपये मानदेय दिया जाता था जिसे हमने वर्ष 2024 में बढ़ाकर पांच हज़ार रुपए प्रतिमाह कर दिया था। उसके उपरांत वर्ष 2025 में माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुसार मल्टी टास्क वर्कर्ज का मानदेय पांच हज़ार रुपए से बढ़ाकर पचपन सौ रुपए प्रतिमाह किया गया है। जहां तक इनकी कार्यावधि की बात है उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विभिन्न सर्किल और सैक्शन्ज में जो सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं वे निर्धारित करते हैं कि मल्टी टास्क वर्कर्ज से क्या काम करवाना है। यह भी ऑन रिकार्ड है कि इनकी नियुक्तियां वर्ष 2022 में हुई थी। भाजपा की सरकार के समय यह पॉलिसी बनी थी। मैं इसमें कोई राजनीतिक

19.03.2026/1150/RKS/YK-2

हस्तक्षेप या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहता हूं। मगर जब यह पोलिसी बनी थी तब ये सारी कंडिशन्ज तय कर दी जाती तो मैं समझता हूं कि वह सही होता। जब हमारी सरकार बनी तो हमने over the period of time इसको ठीक करने की कोशिश की।

Speaker : He is asking on humanitarian ground whether the Government wants to review this policy or not?

PWD Minister : On humanitarian grounds हमारी संवेदनशीलता सभी विभागों के लिए बरकरार है। **Department of Personal द्वारा आने वाले समय में सभी विभागों में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर्ज के लिए पोलिसी बनाने का कार्य किया जा रहा है। यह बात मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में भी है और I am sure in the times to come इसके ऊपर सही निर्णय लिया जाएगा। मगर जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता तब तक हम समय-समय पर मल्टी टास्क वर्कर्ज के मानदेय को बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। समय अवधि के साथ उनकी जो सर्विसिज हैं उसको सिक्योर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।**

अध्यक्ष : माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी this is enough. He has said it now. सरकार इसके लिए पोलिसी बना रही है और उनके मानदेय को बढ़ाने का भी विचार रखती है। क्या आप अब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं?

श्री सतपाल सिंह सत्ती : माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्मिक विभाग इसके बारे में पोलिसी बनोने का विचार कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा? मल्टी टास्क वर्कर्ज, पैरा-फिटर्ज की पोलिसी बनाने हेतु आपने क्या समय-सीमा निर्धारित की है? आपकी यह सोच कब तक पूरी हो जाएगी? मेरा दूसरा विषय यह है कि आपने उस समय पांच लाख रेगुलर नौकरियां देने का वायदा किया था। इस संदर्भ में अनेकों वीडियोज भी वायरल हुई हैं। अगर इन रेगुलर नौकरियों में आप इन लोगों को भी जोड़ दें तो सही होगा क्योंकि इन्होंने भी पांच साल तक चार हजार रुपये मानदेय पर अपनी सेवाएं दी हैं। यहां पर मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के अधिकारी बैठे हैं। आप इन लोगों को आदेश दें कि इसका जल्दी से कोई-न-कोई हल निकालें। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आने वाले बजट में इसके लिए कुछ प्रावधान कर सकते हैं।

19.03.2026/1150/RKS/YK-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कई विभागों में आउटसोर्स और मल्टी टास्क वर्कर्ज कार्यरत हैं। **हम आउटसोर्स वालों के लिए भी कानून के अनुसार कोई नीति बनाने पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से भविष्य में इन चीजों पर विचार करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। कानून की क्या प्रक्रियाएं हैं हमें उन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा।**

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1155/बी.एस./वाई.के.-1

प्रश्न संख्याः 3910 जारी...मुख्य मंत्री जारी...

और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में एक प्रथा है और यह प्रथा और परंपरा चली आ रही है जो सरकारी संस्थान में लगता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप सब कार्य प्रणाली को जानते हैं, यही मैं कहना चाहता हूं

19.03.2025/1155/बी.एस./वाई.के.-2

प्रश्न संख्या 3911

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री का पिछले साल सीमा कॉलेज, राहडू का दौर था तो हमने बहुत सारी डिमांड्स मुख्य मंत्री जी के सामने रखी थी। जिसमें एक डिमांड बी.एड. की क्लासेस चलाने की थी। आपने इन सभी डिमांड्स को माना था। मेरा मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जो बी0एड0 की क्लासेस के बारे में मुझे जो जवाब मिला है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मैं चाहूंगा कि इसे इसी सत्र में मंजूरी दी जाए, यही मैं आग्रह करना चाहूंगा।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला विचाराधीन तभी है जब मुख्य मंत्री की घोषणा है और साथ में मेरे पड़ोसी भी हैं नहीं तो इसमें उत्तर दूसरा भी आ सकता था। **हमारे अन्य कॉलेजेज में जहां पर हमारी माननीय कैबिनेट ने एन0ओ0सी0 दी है, उसमें भी अभी हमारे एन0सी0टी0ई0 से हमारे को एन0ओ0सी0 मिलनी है। निश्चित रूप में यह मामला विचाराधीन है और इसको हम करेंगे।**

19.03.2025/1155/बी.एस./वाई.के.-3

प्रश्न संख्याः 3912

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह हिमाचल प्रदेश में हमारे क्षेत्र के अंदर भी और बाकी जगह भी जो बांस किसानों के लिए बहुत लाभदायक रहता है। यह बात आपके ध्यान में रहे कि भारतीय वन अधिनियम-1927 में यह जो बांस है इसको वृक्ष की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। अब बांस वृक्ष नहीं है, बांस घास (झाड़ी) है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार और

उनके अधिकारी बांस को वृक्ष की तरह ट्रीट कर रही है। इस झाड़ी को काट कर हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अब इस घास को काटने के लिए पहले पटवारी और दूसरा इनका गार्ड वे आएंगे। वहां पर चेक करेंगे। चेक करना भी बुरी बात नहीं है। वे वहां पर पर्चा-ततिमा बनाएंगे उसके बाद वह जो घास है, उस घास के ऊपर 20 रुपये टैक्स प्रति क्विंटल लगा रहे हैं। जिस समय वह वृक्ष माना जाता था उस समय यह लगता था। जब इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वृक्ष की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, तो अब यह टेक्स क्यों लिया जा रहा है? अभी किसानों को तंग क्यों किया जा रहा है? आपने इसके लिए 500 रुपये परमिट फीस रखी है, तो क्या अधिनियम 1927 में जो बोला गया है, क्या उसको हूबहू हिमाचल प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा? और जो किसानों से परमिट फीस और टैक्स लिया जा रहा है, इसको बंद किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह जो बांस है, इसको ट्री की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसे झाड़ी की श्रेणी में रखा गया है। अब दो प्रकार का बांस है, एक सरकारी जमीन में उगा हुआ और दूसरा निजी जमीन में उगा हुआ बांस। निजी जमीन में जब बांस उगता है उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर वह प्रदेश के बाहर जाता है, तो इस प्रकार से उनसे परमिट फीस ली जाती है ताकि कोई सरकारी क्षेत्र का बांस उस गाड़ी में न जाए। कई बार आप भी शिकायत करते थे कि इस तरह की बात हो रही है। लेकिन दो बातें माननीय सदस्य ने ध्यान में लाई है कि एक तो उनसे फीस ली जाती है और मेरा मानना है **कि निजी क्षेत्र में कोई भी फीस उनसे न ली जाए, एक बात तो यह है और दूसरी बात निजी क्षेत्र को पटवारी से इसलिए दिखया जाता है कि दूसरे की**

19.03.2025/1155/बी.एस./वाई.के.-4

जमीन से बांस न काटे। लेकिन उसकी जमीन का जब बांस होगा हम आश्वासन देना चाहते हैं कि वह अपनी जमीन का बांस काट सकता है और परमिट फीस इसलिए लेना

जरूरी है ताकि अपनी जमीन से तो बांस काट के जाए परंतु सरकारी जमीन बांस अगर काट के जाए तो पता लग सके इसलिए हमने परमिट फीस का प्रावधान किया है।

प्रश्न काल समाप्त

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1200/DT/AG-1

अध्यक्ष : शून्य काल में मेरे पास 8 माननीय सदस्यों के विषय आये हैं। मैं इन सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कम-से-कम समय में अपने विषय को सदन में रखें ताकि सभी माननीय सदस्यों के विषय लग सकें क्योंकि आज बिजनेस भी बहुत लगा हुआ है। मेरा यह आग्रह सभी से रहेगा। सर्वप्रथम मैं डॉ0 जनक राज जी से आग्रह करूगा कि वह अपना विषय बहुत सूक्ष्म तरीके से रखें।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से इस शून्य काल में सरकार का ध्यान लोकल एरिया डवलपमेंड फंड की और आकृषित करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में चल रही या बनाई जा रही जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा स्वर्ण जयंती पॉलीसी के अंतर्गत 1 to 1.5 per cent depending upon की वह उस योजना का कितना मेगावॉट का प्रोडक्शन होगा, उसको सरकार के खाते में जमा करवाना पड़ता है। जो स्वर्ण जयन्ती पॉलीसी है उसके हिसाब से लोकल एरिया डवलपमेंट फंड का इस्तेमाल केवल और केवल उस लोकल एरिया जो उस प्रोजैक्ट की वजह से प्रभावित हुआ है, उसमें वहां के लोगों की चाहे एग्रीकल्चर की जमीन अफैक्ट हुई है, चाहे उनके रोड खराब हुए हैं या उन्हें वहां पर और इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए उसको खर्च किया जाता है। पहले एल0ए0डी0एफ0 से 10 प्रतिशत और सुख आश्रय के लिए जाता था लेकिन अब सरकार ने 40 प्रतिशत एल0ए0डी0एफ0 को सुख आश्रय योजना में डालने का निर्णय लिया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेकों जल विद्युत परियाजनाएं हैं जिनके द्वारा यह पैसा नियमित अंतराल में सरकार को जमा करवाया जा रहा है लेकिन पिछले कई वर्षों से लोगों को फ्री पॉवर के नाम पर जो पैसा उनके खतों में जमा होता था वह उन्हें नहीं मिला है ऊपर से सरकार ने उसका 40 प्रतिशत अमाउंट सुख आश्रय योजना के लिए डाइवर्ट कर दिया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगाा कि जो एल0ए0डी0एफ0 की गाइडलाइंस हैं, जिसमें

यह लिखा गया है कि लोकल एरिया डवलपमेंट फंड विशेषतौर पर उसी लोकल एरिया में खर्च होगा जहां का एरिया पॉवर प्रोजैक्ट के कारण अफैक्ट हुआ है और उसी पंचायत या उसी क्षेत्र के विकास के लिए वह पैसा खर्च होगा। तो क्या सरकार यह सुनश्चित करेगी की जो यह सुख आश्रय योजना के लिए 40 प्रतिशत पैसा एल0ए0डी0एफ0 से ले रही है क्या ये उसी क्षेत्र के अनाथ बच्चों पर खर्च होगा या समूचे प्रदेश के अनाथ बच्चों पर खर्च होगा? अगर इस पैसे को समूचे प्रदेश में खर्च

19.03.2026/1200/DT/AG-2

करने की सरकार की मंशा है तो हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने शून्य काल में मुझे अपना विषय उठाने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य के द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय इस मान्य सदन के ध्यान में लाया गया है और विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है। ये सारी जानकारी विधान सभा सचिवायल के माध्यम से माननीय सदस्य तक पहुंचा दी जाएगी। शून्य काल में अगला मामला उठायेंगे श्री सुरेन्द्र शौरी।

19.03.2026/1200/DT/AG-3

श्री सुरेन्द्र शौरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बंजार के नागरिक हस्पताल के संबंध में इस शून्य काल में अपनी बात रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि बंजार का नागरिक हस्पताल शायद पूरे प्रदेश का ऐसा हस्पताल हैं जहां पर मेडिकल ऑफिसर्ज के कुल पद 6 ही हैं। मैं एक सूची देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि प्रदेश में कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर चिकित्सकों के पद ज्यादा हैं। पिछली सरकार के द्वारा इस हस्पताल में डाक्टर्ज की पोस्टों की संख्या को 14 कर दिया गया था लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसे डिनोटिफाइड करते हुए केवल 6

पद ही इस हस्पताल में रखे गये हैं। बंजार का नागरिक हस्पताल लगभग 34-35 पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाता है वहां पर मात्र 4 डाक्टर्ज हैं

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2026/1205/ए.जी.-एन.जी./1

वहां पर न डेंटिस्ट है और न ही आंखों का डॉक्टर है। वहां पर रेडियोग्राफर भी नहीं है यानी कि वहां अल्ट्रासाउंड भी नहीं होता है। अगर शाम 4:00 बजे के बाद कोई हादसा हो जाए तो वहां पर एक्स-रे नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर केवल एक ही रेडियोग्राफर है। इसलिए यह बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि एक नागरिक अस्पताल के अंदर ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ने इस नागरिक अस्पताल को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा भी दिया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर जो डॉक्टरों की पोस्टें पहले डीनोटिफाई की गई थीं, उन्हें फिर से नोटिफाई करके उनकी संख्या बढ़ाई जाए और जो डॉक्टरों के खाली पद पड़े हैं, उन्हें भी भरा जाए। वहां पर डेंटिस्ट, ऑप्थैल्मिक ऑफिसर और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर की भारी कमी है। वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन भी खाली पड़ी हुई है। इसलिए इन सभी सुविधाओं को वहां पर उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। अन्यथा लोगों को 50-55 किलोमीटर दूर कुल्लू अस्पताल जाना पड़ रहा है। इसलिए यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत गंभीर चिंता का विषय है और मेरा आग्रह है कि इस नागरिक अस्पताल में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी-से-जल्दी वहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है। निश्चित तौर पर हम विभाग से कहेंगे कि जो-जो कमियां हैं, उन्हें जल्दी से दूर किया जाए। विभाग द्वारा इस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, उससे माननीय सदस्य को भी सूचित करेंगे।

अब अगला विषय माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा का है।

19.03.2026/1205/ए.जी.-एन.जी./2

(माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा द्वारा शून्य काल के दौरान हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स में हुई बढौतरी के संदर्भ में उठाया गया विषय।)

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं शून्य काल के माध्यम से अभी हाल ही में टोल टैक्स, जिसे हम एंट्री टैक्स भी कहते हैं, हिमाचल एंट्री टैक्स, उस विषय को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। वर्ष 2026-27 के लिए इसमें जो वृद्धि की गई है, उसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। सर, मेरा विधान सभा क्षेत्र पंजाब व हरियाणा राज्यों के साथ लगता क्षेत्र है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि एंट्री टैक्स में जो वृद्धि की गई है, चाहे जो लोग बाहर से आने वाले हमारे पर्यटक हों या बाहर से आने वाले वे लोग जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, इन सभी के लिए यह वृद्धि उचित नहीं है। चार पहिया वाहनों जैसे कार और अन्य वाहनों के लिए जो वृद्धि की गई है वह 70/- रुपये से बढ़ाकर 170/- रुपये की गई है जोकि 142 प्रतिशत है, which is very unfair. इसके अलावा ट्रकों के लिए भी 320/- रुपये से बढ़ाकर 570/- रुपये किया गया है जोकि 78 प्रतिशत की वृद्धि है। हम लोग माननीय मुख्य मंत्री से भी मिले हैं क्योंकि एक्साइज डिपार्टमैंट व फाइनेंस विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर्स फेडरेशन के लोग, माननीय सदस्य, श्री राम कुमार और

मेरे नेतृत्व में हम सब लोग माननीय मुख्य मंत्री से मिले और हमने अपनी ओर से एक प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। इसके बाद इसका व्यापक असर भी देखने को मिला है। अभी हाल ही में पंजाब में जो बजट सत्र चल रहा था, उस सत्र में वहां के एक माननीय विधायक, जोकि हमारे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगते रोपड़ विधान सभा क्षेत्र से हैं, ने भी इस मुद्दे को उठाया है।

19.03.2026/1205/ए.जी.-एन.जी./3

उसके जवाब में वहां के वित्त मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने यह कहा कि पंजाब राज्य भी इसी प्रकार का टैक्स लागू करने पर विचार कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश ही क्यों इस टैक्स को लगा रहा है? यह जो टोल टैक्स या एंट्री टैक्स है, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह टैक्स वर्ष 2001-02 में लगाया गया था। उस समय भाजपा की सरकार थी और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी उस समय मुख्य मंत्री थे। सरकारें समय के साथ बदलती रहीं और कभी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा लगातार इसमें वृद्धि होती रही। आपके माध्यम से मेरी विनती है कि जो वृद्धि की गई है, उसे यदि बढ़ाना ही है तो उसे उचित और तर्कसंगत रखा जाए ताकि हमें भी तथा हमारे साथ लगते राज्य हैं, वहां रहने वाले लोगों को भी

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1210/ए.पी. /ए.एस. -1

शून्य काल जारी .....श्री हरदीप सिंह बावा जारी .....

यह रास आएगा। हमारे क्षेत्र की स्थिति इस तरह है कि अगर हमारे लोगों को सीमेंट लेना हो, तो भी कठिनाई होती है। जबकि कंपनियां हमारे हिमाचल में सीमेंट के प्लांट चला रही हैं और सीमेंट का उत्पादन कर रही हैं। फिर भी हमें सीमेंट महंगा ही मिलता है। पंजाब में हमें सीमेंट सस्ता मिलता है। इसलिए अगर हमें सीमेंट की बोरी लेनी हो, तो हमें बॉर्डर पार करना पड़ता है। इसके अलावा टैक्स इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि किराए में बढ़ोतरी न्यायसंगत हो। यही मैं कहना चाहता हूं। हमने ऑल हिमाचल ट्रक ऑपरेटर फेडरेशन के माध्यम से भी इस प्रस्ताव को सरकार के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू कि इसे तर्कसंगत बनाया जाए और किराए में उचित बढ़ोतरी की जाए। धन्यवाद।

Speaker : Again a very important issue has been brought to the notice of this Hon'ble House and certainly we have taken a cognizance of it. The details which you have said in your own speech that is most genuine cause which you have ventilated through your speech. We will be asking the Government to take necessary action in this behalf. Whatever action will be taken, we will inform you accordingly. Thank you.

अब मैं राकेश कालिया जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना विषय शून्य काल में रखें।

19.03.2026/1210/ए.पी. /ए.एस. -2

शून्य काल जारी .....

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक महत्वपूर्ण प्रश्न शून्य काल में उठाने जा रहा हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी तीन दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक बी0डी0सी0 सदस्य, अनील डडवाल, जोकि कांग्रेस पार्टी में

सोशल मीडिया के राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेटर हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने के कारण हुई। यह एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है। क्योंकि पोस्टिंग तो हमारी सरकार के खिलाफ, हिमाचल सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार और हमारे नेताओं के खिलाफ भी होती रहती है। जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि यह क्या मुकदमा बनता है, तो उन्होंने पहले कहा कि यह 'बेलेबल ऑफेंस' है, आप भेज दीजिए दिल्ली। हमने परिवार से सलाह करके अपना लड़का बस में बैठाकर दिल्ली भेजा। वहां जाकर उसे थाने में बैठाए रखा और शाम को गिरफ्तार कर लिया। फिर कहा गया कि आपके ऊपर दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जो 'नॉन-बेलेबल' हैं। आज तीन दिन उसकी गिरफ्तारी को हो गये है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इसका संज्ञान ले और उसके परिवार की मदद करे। क्योंकि वह प्रधान भी रहा है और वर्तमान में भी बी0डी0सी0 सदस्य है। जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते, तब तक वह पद पर है और यह व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होने के नाते उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक शब्द भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है कि "जितना अन्याय करना पाप है, उतना ही अन्य सहना भी पाप है"। यह हमारे लोगों के साथ अन्याय है। इस समय इसका समाधान निकालने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली पुलिस के साथ कोई रास्ता निकालें। आप Resident Commissioner की ड्यूटी लगाए कि हमारे लोगों पर जो मुकदमा बनाया गया है, उसे उचित तरीके से देखा जाए और किसी अन्य धारा में ले जाया गया है, तो उसका न्यायसंगत निर्णय किया जाए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे साथी भी यहां बैठे एक फ्रेंच दार्शनिक इमैनुएल कांट ने भी कहा है कि "जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं कि आपके साथ हो, तो वैसा ही व्यवहार आप लोगों से करें"। यदि केंद्र सरकार हमारे लोगों को यहां गिरफ्तार करेगी, तो प्रतिक्रिया यहां भी हो सकती है। मैं

19.03.2026/1210/ए.पी. /ए.एस. -3

अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना प्रार्थना करता हूं कि हमारे लोग law abiding और चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसलिए चाहे बेल के लिए हो या किसी अन्य सहायता के लिए,

प्रदेश सरकार उनकी मदद करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके द्वारा शून्य काल में इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और मैं यह समझता हूं कि अगर बेलेबल आफैंस में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और उसके बाद अतिरिक्त सैक्शन लगाई गई है तो निश्चित तौर पर this issue is required to be enquired into and hopefully the police will take a necessary action and the Government will take necessary action in this behalf. And whatever the action the Government takes, we will inform the Hon'ble Member accordingly. Thank you very much for raising a very important issue.

अब मैं क्या इसी इश्यू पर आप बोलना चाहते है। आपने क्या इस पर अनुपूरक प्रश्न करना है। माननीय सुदर्शन सिंह बबलू।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.03.2026/1215/AT/AS/01

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी।

श्री सुदर्शन सिंह बबलूः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय राकेश कालिया जी लेकर आए हैं। जिस तरीके से हमारे अनिल डडवाल जी, जो राकेश कालिया जी की विधानसभा से हैं और युवाओं की आवाज हैं, वे बीडीसी मेंबर भी हैं, उन पर जिस तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं वह बिल्कुल गलत है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से

भी देखा है कि उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। छोटी सी बात को बहुत बड़ा ऑफेंस बना दिया गया है जबकि सोशल मीडिया पर विपक्ष के लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ पोस्टर बनाकर डालते रहते हैं। सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना लोगों का अधिकार है, सरकारी की नकामयाबी पर सवाल उठाना भी उनका हक है। जिस तरीके से पहले यूथ कांग्रेस के लड़कों के अभी हाल ही में व्यवहार किया गया वह भी खेदजनम है। श्री अनिल डडवाल जी जो कांग्रेस के बहुत तेज-तर्रार कार्यकर्ता हैं उनके विरूद्ध जो कार्रवाई की गई है इस प्रकार की कार्रवाईयों से युवाओं का मनोबल गिरता है। मैं समझता हूं कि श्री अनिल जी द्वारा कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं किया गया था जिस तरीके की धाराएं लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसलिए मैं माननीय सदन के अंदर गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर जरूर संज्ञान लिया जाए। हमारे देश के लोगों की आवाज को दबाने प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है।

माननीय राकेश कालिया जी जो विषय जीरो आवर में लेकर आए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए। धन्यवाद

Speaker: As I have Already said that the government will take a necessary action in this matter and whatever action will be taken by the Government and the Police, will be informing both of you.

अब माननीय सदस्य नीरज नैय्यर अपना मामला इस सदन में रखेंगे।

19.03.2026/1215/AT/AS/02

श्री नीरज नैय्यर: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, चंबा का हमारा मेडिकल कॉलेज है। लगभग ढाई वर्ष पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसकी बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 175 करोड़ रुपये दिए थे। डेढ़ साल बाद बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो गई। जब आप स्वयं चंबा आए थे तब हम आपके साथ मेडिकल कॉलेज भी गए थे और आपने वहां प्रशासन के साथ मीटिंग भी की थी। इसलिए आप स्थिति से भलीभांति अवगत हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी इस हाउस के अंदर श्री डी0एस0 ठाकुर द्वारा कहा गया कि छोटे-छोटे मामलों के लिए मरीजों को टांडा ले जाना पड़ता है। जबकि हमारा मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार है पैसा भी उपलब्ध है। इक्विपमेंट के टेंडर लगे हुए हैं और फर्नीचर-फिक्सचर के टेंडर भी लगे हुए हैं लेकिन इन टेंडरों के प्रोसैस को डेढ़ साल हो गया है। बिल्डिंग बने भी डेढ़ साल हो गया है और अब बाहर से उसका पेंट भी उखड़ने लगा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से गुहार लगाना चाहता हूं कि इन टेंडरों को जल्द से जल्द खोला जाए। मुझे जानकारी मिली है कि जिस कंपनी को टेंडर मिला था वह ब्लैकलिस्ट हो गई है और अब उसकी प्रक्रिया में फिर तीन-चार महीने लगेंगे। जो L2 या L3 वाली कंपनियां हैं अगर उनको टेंडर दे दिया जाए तो भी ठीक रहेगा। अगर केवल एक ही कंपनी आई है तो इस पर भी विचार किया जाए। आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहुंगा कि चंबा एक दूर-दराज का इलाका है इसलिए मैं यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसके अलावा, कुछ महीने पहले टांडा मेडिकल कॉलेज में मुख्य मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस मेडिकल कॉलेज को शुरू करना है तो हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज द्वारा मांग भी रखी गई है जिसमें सिक्योरिटी और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। इस संबंध में पूरी रिपोर्ट प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज द्वारा डीएचएस को भेजी गई है।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1220/केएस/डीसी/1

श्री नीरज नैय्यर जारी ---

मैं चाहूंगा कि ये जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां करनी हैं, ये भी काम साथ के साथ हो जाए क्योंकि अगर मैडिकल कॉलेज का टेंडर भी लग गया, सारी चीजें हो जाएंगी तो बाद में फिर बात आएगी कि हमारे पास सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, सफाई वाले नहीं हैं। उसमें दो-तीन महीने और लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये चीजें मैं यहां आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर आपने ज़ीरो आवर के माध्यम से माननीय सदन के ध्यान में एक गम्भीर विषय लाया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी जैसे आज सदन में कहा है कि सरकार मैडिकल कॉलेजिज़ के बारे में चिंतित है और उसमें चम्बा भी शामिल है। जो विषय चम्बा मैडिकल कॉलेज के बारे में आपने यहां रखा है, निश्चित तौर पर विभाग और माननीय मुख्य मंत्री इसका संज्ञान लेंगे और की गई कार्रवाई से माननीय सदन और आपको अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।

19.03.2026/1220/केएस/डीसी/2

अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया ज़ीरो आवर के माध्यम से अपना विषय रखेंगे। पठानिया जी, आपके दो इशूज़ हैं, जल्दी-जल्दी समाप्त करें क्योंकि समय हो रहा है।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी की इंटरवेंशन चाहता हूं कि एच0आर0टी0सी0 का एक पुराना टैम्पो हमारे धर्मशाला को शिफ्ट किया गया है जिसको चंद दिन पहले एयरपोर्ट से चलाया गया था। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट ली जाए। मेरे करेरी का क्षेत्र है और मैंने पर्यटन की दृष्टि से मुख्य मंत्री महोदय से पिछले विधान सभा सत्र के दौरान प्रश्न भी किया था। यह छोटा टैम्पो है और धर्मशाला से पिछली बार भी 4 लाख 10 हजार टूरिस्ट का फुटफॉल था मैं उप-मुख्य मंत्री महोदय से यह इंटरवेंशन चाहता हूं कि अगर वहां यह टैम्पो कामयाब नहीं है तो धर्मशाला से करेरी के लिए कुठारना होते हुए इसको चलाया जाए। इसके साथ-साथ मेरे यहां जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके लिए कुछ बसों की

ज़रूरत है क्योंकि वहां बच्चे समय पर नहीं पहुंच पाते। अध्यक्ष जी, उसमें भी मैं इनकी इंटरवेंशन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, न्यू शिमला के डी0ए0वी0 स्कूल के कुछ बच्चे और उनके पेरेंट्स कल हमसे मिले थे। आजकल प्लस वन और प्लस टू के विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं लेकिन ना प्राइवेट और ना ही सरकारी बस उनके स्कूल के समय के हिसाब से न्यू शिमला के लिए चल रही है। मैं उप-मुख्य मंत्री जी और आपके माध्यम से यह इंटरवेंशन भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि करेरी वाले मामले में उप-मुख्य मंत्री जी रिपोर्ट लें। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय आपने ज़ीरो आवर के माध्यम से माननीय सदन के ध्यान में लाया है। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और जल्दी ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी और उससे आपको और इस माननीय सदन को विभाग सूचित करेगा और उसकी सूचना हम आपको भी प्रेषित करेंगे।

19.03.2026/1220/केएस/डीसी/3

अब माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी ज़ीरो आवर के माध्यम से अपना विषय उठाएंगे। कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री मलेन्द्र राजन : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार व माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा विधान सभा क्षेत्र इंदौरा और उसके साथ ज्वाली, फतेहपुर तथा नूरपुर विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर एस0पी0 ऑफिस नूरपुर अलग से खोला गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा क्षेत्र बॉर्डर से सटा हुआ है और पिछले कुछ सालों से अवैध नशे, अवैध खनन और अवैध कटान की बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ भी उस क्षेत्र में होती आई हैं। हमें जानकारी मिली है कि पुलिस जिला नूरपुर में हैड कॉंस्टेबल,

कॉंस्टेबल, ए0एस0आई0 आदि अलग-अलग श्रेणियों के बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनको कब तक भर दिया जाएगा? इसके साथ-साथ पुलिस लाइन नूरपुर में क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स अभी तक भी नहीं हो पाई हैं जिसके कारण वहां पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नूरपुर जिला के बाद जो भी पुलिस जिला बने वहां पर पोस्टें क्रिएट हो चुकी हैं लेकिन पुलिस लाइन नूरपुर में अभी तक पोस्टें क्रिएट नहीं हो पाईं हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

19.03.2026/1225/av/dc/1

श्री मलेन्द्र राजन--------- जारी

मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह आग्रह रहेगा कि वहां जल्दी से पोस्ट्स क्रिएट करके उनको भरा जाए। हमारा क्षेत्र नेशनल हाईवे पर भी पड़ता है इसलिए वहां पर एक्साइज की चोरी भी बहुत होती है।

इसके अतिरिक्त बदरोहा के अंदर एक पुलिस चैक पोस्ट खोली जानी प्रस्तावित है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर उसको भी शीघ्रातिशीघ्र खोला जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा जीरो आवर के माध्यम से माननीय सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाया गया है। **माननीय मुख्य मंत्री और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। सरकार इस विषय के संदर्भ में जल्दी ही कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई से हम माननीय सदन के माध्यम से आपको सूचित करेंगे।**

अब अंत में माननीय सदस्या सुश्री अनुराधा राणा अपना विषय उठाएगी।

19.03.2026/1225/av/dc/2

सुश्री अनुराधा राणा : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं जो मुद्दा जीरो आवर के माध्यम से उठा रही हूं यह वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि इज़रायल और ईरान में पिछले 15-20 दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है। परंतु इसमें चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर तो पड़ा ही है साथ-ही-साथ हमारा हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। पूरे देश में एल0पी0जी0 का क्राइसिज देखने को मिल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट लागू किया गया है। हमारा देश एल0पी0जी0 की सप्लाई हेतु बाहरी देशों पर लगभग 60 प्रतिशत निर्भर है। इसमें 60 प्रतिशत में भी 90 प्रतिशत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो ईरान और ओमान के बीच के समुद्री मार्ग से हमारे देश में सप्लाई आती है, युद्ध छिड़ने के बाद पहले इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। परंतु केंद्र सरकार की इंटरवेंशन के बाद अब यह सुखद है कि वहां से दो जहाजों को आने की अनुमति मिली है। परंतु फिर भी हम देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में तो हालत बहुत खराब है हालांकि हिमाचल प्रदेश में उतने ज्यादा नहीं है। यहां अभी घरेलू गैस सप्लाई की सुविधा जारी है परंतु कॉमर्शियल गैस सप्लाई में यहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं। यह वैसे तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि केंद्र सरकार द्वारा जो रीफिलिंग के स्पेन के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, वह चाहे घरेलू या कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का है। वह अर्बन एरियाज के लिए 25 डेज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिनों का है। यह जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिनों का स्पेन रखा गया है यह कहीं-न-कहीं अनफेयर है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक सिलेंडर ज्यादा-से-ज्यादा एक महीना ही चलता है। खासकर लाहौल-स्पिति जैसा क्षेत्र जहां पर जंगल या अपना कोई फ्यूल का माध्यम नहीं है तो इसके दृष्टिगत इस स्पेन को कम किया जाए। इसको भी अर्बन क्षेत्र की तर्ज पर 25 से 30 दिनों तक निश्चित किया जाए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध रहेगा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने निश्चित तौर पर जीरो आवर के माध्यम से माननीय सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाया है। **विषय की गम्भीरता को महसूस करते हुए सरकार इसके संदर्भ में उचित कदम उठाएगी तथा उठाए गए कदमों से हम माननीय सदन के माध्यम से आपको सूचित करेंगे।**

19.03.2026/1225/av/dc/3

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, सलाहकार (योजना), ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या : पीएलजी (ए) 3-4/2017-लूज़, दिनांक द्वारा दिनांक 23.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.02.2026 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय उप-मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उप-मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, सहायक अभियन्ता (सिविल), वर्ग-1(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः जे0एस0वी0-ए-ए(3)-1/2023, दिनांक द्वारा 11.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.02.2026 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम 1971 की धारा-क (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय कृषि मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-2025 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

19.03.2026/1225/av/dc/4

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) आठवां संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-11/2024-II, दिनांक द्वारा 15.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.01.2026 को प्रकाशित; और

(ii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नौवां संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-14/2024-IV, दिनांक द्वारा 17.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.01.2026 को प्रकाशित।

अध्यक्ष : अब माननीय लोक निर्माण मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

लोक निर्माण मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।+

अध्यक्ष : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अगला विषय टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1230/टी0सी0वी0/एच0के0-1

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अंतिम किश्त) वित्तीय वर्ष 2025-26

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किश्त) को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किश्त) को सदन में प्रस्तुत करता हूं जोकि इस प्रकार है:-

1. मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2025–26 के लिये अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम तथा अन्तिम किश्त प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. यह अनुपूरक मांगें ₹40461 करोड़ 95 लाख की हैं, जिनमें से ₹36374 करोड़ 61 लाख राज्य स्कीमों और ₹4087 करोड़ 34 लाख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों हेतु प्रावधित किए गए हैं।

3. राज्य स्कीमों के अन्तर्गत मुख्यतः ₹26194 करोड़ 95 लाख Ways and Means और Overdraft के लिए, ₹4150 करोड़ 14 लाख विद्युत उपदान और HPSEBL को उदय योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाए गए ऋण को इक्विटी में बदलने, क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत, ₹818 करोड़ 20 लाख प्राकृतिक आपदा राहत, ₹785 करोड़ 22 लाख जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं, ₹657 करोड़ 22 लाख हिमकेयर, सहारा योजना, चिकित्सा महाविद्यालय शिमला, टांडा, हमीरपुर, नेरचौक और AIMSS चम्याणा में रोबोटिक सर्जरी, टांडा, हमीरपुर और AIMSS चम्याणा में उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, हमीरपुर और टांडा के लिए पैट स्कैन की खरीद, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर और विभिन्न अस्पतालों के निर्माण कार्यों तथा AIIMS बिलासपुर के लिए विद्युत आपूर्ति, ₹555 करोड़ 89 लाख

द्वारका में राज्य अतिथि गृह और हिमाचल भवन चण्डीगढ़ के निर्माण, ₹148 करोड़ 24 लाख National Disaster Response Force Battalion बैहना मण्डी की स्थापना, ₹108 करोड़ 17 लाख माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में SGST reimbursement और ₹104 करोड़ 65 लाख JICA Project, MIS के लम्बित दायित्व, HP SHIVA Project हेतु प्रावधित किए गए हैं।

4. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अधिकतर राशि चालू तथा नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केन्द्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। ₹2453 करोड़ 97 लाख NDRF से प्राप्त आपदा प्रबन्धन हेतु, ₹688 करोड़ 40 लाख प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना, ₹352 करोड़ 18 लाख रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवज़े, ₹82 करोड़ 45 लाख प्रधान मन्त्री आवास योजना (ग्रामीण), ₹68 करोड़ 30 लाख मनरेगा, ₹55 करोड़ 50 लाख फिनासिंह परियोजना, ₹36 करोड़ 66 लाख राष्ट्रीय आयुष मिशन, ₹36 करोड़ 17 लाख PM ABHIM, ₹33 करोड़ 37 लाख प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना और ₹25 करोड़ धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में सकरैन, मलथोड़, थोथू, डोल और समौर खड्ड के कटाव रोधी उपायों हेतु प्रस्तावित है।

5. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ महत्वपूर्ण अनुपूरक अनुदान मांगों की रूप रेखा प्रस्तुत की है। मांगों का पूरा विवरण माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेज़ों में दर्शाया गया है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत सब्जी मंडी शिमला और नगर परिषद हमीरपुर में Shopping Complex, हमीरपुर में HRTC बस अड्डे, खलीनी शिमला में Flyover, छोटा शिमला से विल्ली पार्क तक underground utility duct के निर्माण और Scandal point पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण, ₹453 करोड़ 63 लाख सड़को के रखाव, पुलों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मुआवज़े, ₹443 करोड़ 33 लाख हिमाचल पथ परिवहन निगम को यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को किराए में दी जा रही छूट के एवज में उपदान, हमीरपुर में बस अड्डे और सिरमौर में भवन के निर्माण तथा Electric Vehicle Charging Infrastructure के सुदृढ़ीकरण, ₹262 करोड़ 16 लाख 15वें वित्तायोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण, ₹244 करोड़ 31 लाख स्कूल भवनों, राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुलह, राजीव गान्धी राजकीय अभियान्त्रिकी कॉलेज और आई0टी0आई0 नगरोटा बगवां में भवनों तथा नादौन (हमीरपुर), नाहन (सिरमौर), बैजनाथ (कांगड़ा), कल्पा में इन्डोर स्टेडियमों के निर्माण, ₹221 करोड़ 53 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के मानदेय, मुख्य मन्त्री सुख आश्रय कोष, मुख्य मन्त्री सुख आश्रय योजना, मुख्य मन्त्री सुख शिक्षा योजना, लुथान कांगड़ा में सुख आश्रय परिसर एवं विभिन्न जिलों में शिशु देखभाल केन्द्रों के निर्माण और पैंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ₹192 करोड़ 20 लाख National Disaster Response Force Battalion मुख्यालय बैहना मण्डी के लिए सड़क निर्माण तथा मशीनरी व उपकरणों की खरीद, ₹186 करोड़ 73 लाख National Law University Ghandal में न्यायिक अवसंरचना के उन्नयन, छात्रा छात्रावास, राजस्व भवनों, जेल भवनों, राज्य के विभिन्न स्थानों पर Combined Office Buildings, नई दिल्ली स्थित

6. इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदन से इन अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने की सिफारिश करता हूँ।

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम एवं अन्तिम किश्त) पर चर्चा होगी जो आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान भी आज ही होगा। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी पारित होगा।

(सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं तथा माननीय मुख्य मत्री जिनके पास वित्त विभाग है चर्चा का उत्तर देंगे।)

Anybody wants to speak? Nobody wants to speak.

अब वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मुख्य मंत्री महोदय की ओर से सभी मांगों को प्रस्तुत हुआ समझा जाए जो इस प्रकार से है:-

मांग संख्या	मांग का नाम		मांग की राशि जो विधान सभा की स्वीकृति वोट के लिए प्रस्तुत है। ₹ में
1	2		3
01	विधान सभा	(राजस्व) (पूंजीगत)	10,61,94,000 6,72,35,000
02	राज्यपाल और मंत्री परिषद्	(राजस्व)	5,93,60,717
03	न्याय प्रशासन	(राजस्व) (पूंजीगत)	16,01,01,671 19,83,44,000
04	सामान्य प्रशासन	(राजस्व) (पूंजीगत)	37,71,39,823 1,65,00,68,000
05	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व) (पूंजीगत)	34,35,09,97,322 9,68,00,000
06	आबकारी और कराधान	(राजस्व) (पूंजीगत)	60,06,63,611 1,17,47,000
07	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व) (पूंजीगत)	2,000 6,76,24,000
08	शिक्षा	(राजस्व) (पूंजीगत)	21,000 83,32,08,000
09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व) (पूंजीगत)	2,23,38,40,000 5,59,43,34,000
10	लोक निर्माण-सड़क, पुल एवं भवन	(पूंजीगत)	10,69,71,69,000
11	कृषि	(राजस्व) (पूंजीगत)	51,78,69,854 11,43,00,000
12	उद्यान	(राजस्व)	63,86,41,295
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व) (पूंजीगत)	4,87,94,57,064 4,24,07,90,601

1	2		3
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व) (पूंजीगत)	9,98,44,390 16,95,01,000
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(राजस्व) (पूंजीगत)	37,85,346 1,89,12,31,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व) (पूंजीगत)	9,000 2,00,00,000
17	निर्वाचन	(राजस्व) (पूंजीगत)	18,26,50,561 2,24,09,000
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व) (पूंजीगत)	23,07,62,667 15,73,83,000
19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व) (पूंजीगत)	1,44,04,16,582 1,09,50,69,843
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व) (पूंजीगत)	5,62,60,94,187 2,27,00,000
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	29,68,04,953
23	विद्युत विकास	(राजस्व) (पूंजीगत)	11,41,90,14,040 30,42,75,60,000
24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	(राजस्व)	67,73,056
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व) (पूंजीगत)	2,50,70,32,000 96,89,00,000
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व) (पूंजीगत)	32,42,88,403 96,34,39,348
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व) (पूंजीगत)	8,85,94,750 4,01,00,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व) (पूंजीगत)	5,20,33,15,647 90,00,00,000
29	वित्त	(राजस्व) (पूंजीगत)	6,000 16,27,500

1	2		3
30	विविध सामान्य सेवाएँ	(राजस्व) (पूंजीगत)	16,11,53,498 1,18,33,43,000
31	जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(राजस्व) (पूंजीगत)	60,27,15,853 16,19,59,400
32	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम	(राजस्व) (पूंजीगत)	4,60,11,87,448 78,42,61,156
	जोड़	**(राजस्व)** **(पूंजीगत)**	**76,71,87,36,738** **62,38,11,03,848**
	कुल जोड़		**1,39,09,98,40,586**

अब इन्हें मैं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां क्रमशः 76,71,87,36,738/- रुपये (राजस्व) एवं 62,38,11,03,848/-रुपये (पूंजी) जिसका कुल जोड़ 1,39,09,98,40,586/- रुपये सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए?

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 1,2,3, 4.5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17,18,19 20,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31 और 32 के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां क्रमश : 76,71,87,36,738/- रुपये (राजस्व) एवं 62,38,11,03,848/-रुपये (पूंजी) जिसका कुल जोड़ 1,39,09,98,40,586/-रुपये सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए

प्रस्ताव स्वीकार

19.03.2026/1230/टी0सी0वी0/एच0के0-9

मांगे पूर्णरूप से पारित हुईं।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पुरःस्थापित हुआ।

19.03.2026/1230/टी0सी0वी0/एच0के0-10

विधेयक पर विचार-विमर्श और पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

तो प्रशन यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1)पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

19.03.2026/1230/टी0सी0वी0/एच0के0-11

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1)को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पारित हुआ"

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1235/NS-HK/1

अध्यक्ष ------जारी

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी

अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। मुझे सत्ता पक्ष से 7 माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं और विपक्ष से 9 माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं। पिछले कल अंतिम वक्ता विपक्ष के थे और अब सत्ता पक्ष के सदस्य से चर्चा आगे जारी होगी। अब मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा को आगे बढ़ाएं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। हालांकि, वे राज्यपाल महोदय अब इस राज्य के राज्यपाल नहीं हैं और दूसरे राज्य के राज्यपाल बने हैं। पिछले कल नेता प्रतिपक्ष ने उनके द्वारा दिए गए भाषण और उन द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया कि वे पैरा संख्या : 1 से लेकर 16 तक पढ़ नहीं सकते तथा वे दो मिनट में ही यहां से चले गए। अध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा नहीं हुआ। जब श्री जय राम ठाकुर जी मुख्य मंत्री थे तब भी ऐसा ही वाक्य हुआ था कि राज्यपाल महोदय दो मिनट में ही चले गए थे। इनका लॉजिक है कि अभी वाले राज्यपाल महोदय तंदरूस्त थे और जो पहले वाले राज्यपाल महोदय थे वे बीमार थे।

अध्यक्ष महोदय, जो कैबिनेट का अनुमोदन या सिफारिश होती है राज्यपाल महोदय उसके ऊपर अमल करके आगे काम करते हैं। हमारे देश का संविधान इस तरह से बना हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि राज्यपाल महोदय पूरा अभिभाषण पढ़ते। अगर उन्होंने नहीं भी पढ़ा तब भी इसे पढ़ा हुआ समझा जाता है। जब उन्होंने इसे यहां पेश कर दिया तो इसको पढ़ा हुआ ही माना जाता है। इसलिए उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा लेकिन वे यहां पर आए और संवैधानिक अनिवार्यता के तहत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां पर चर्चा हो

रही है। इसलिए इसमें कोई असंवैधानिक मसला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के समय में हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध किया था। हमने कहा था कि वे सारा अभिभाषण पढ़ कर जाएं। हम उनसे रिक्वैस्ट करने बाहर तक गए।

19-3-2026/1235/NS-HK/2

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा के अंदर जब एम0एल0एज0 कोई भी काम करते हैं तो उस समय श्री जय राम जी की सरकार ने हमारे ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी थी। ...(व्यवधान) अब आप थोड़ा सुन लें और फिर उसके बाद रिएक्ट करें। ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete. मैं उसके बाद आपको बोलने का समय दूंगा। आप पांच वर्षों तक मुख्य मंत्री रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपका ही रेफरेंस आएगा। आप इनको बोलने दें फिर मैं आपको समय दूंगा। आप सत्ता में रहे हैं और अब नेता प्रतिपक्ष हैं। ...(व्यवधान) फिर श्री रणधीर शर्मा जी भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : देश में यह भी नहीं हुआ कि

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

19.03.2026/1240/RKS/YK-1

उप-मुख्य मंत्री जारी.....

...(व्यवधान) देश में तो यह भी नहीं हुआ कि विधान सभा के अंदर विधायकों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गई हो। ...(व्यवधान) किस देश में हुआ? लोक सभा में हुआ,

राज्य सभा में हुआ या किसी अन्य विधान सभा में हुआ? ...(व्यवधान) यहां पर विधायकों के विशेषाधिकार हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस कानून के तहत विधायकों के खिलाफ विधान सभा परिसर के अंदर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई? ...(व्यवधान) किस कानून के तहत हुई? वह कौन-सा कानून है?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कृपया बैठ जाइए आपको बाद में बोलने का मौका दिया जाएगा।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई खतरा नहीं था। ...(व्यवधान) आपने देशद्रोह का मुकदमा किया। ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete. ...(Interruption) Please take your seats. Nothing is going on record except the speech of Hon'ble Deputy Chief Minister.

उप-मुख्य मंत्री : आप नेता प्रतिपक्ष हैं। पहले जो नेता प्रतिपक्ष मुख्य मंत्री रहा करते थे वह बहुत कम बोलते थे लेकिन मैं तो मुख्य मंत्री नहीं रहा। मैं नेता प्रपिपक्ष था इसलिए मैं यह सब बोल सकता हूं। ...(व्यवधान) आप तो मुख्य मंत्री रहे हैं। आपका डेकोरम लगभग बराबरी का है इसलिए आपको हमारी बात सुननी चाहिए। यह विधान सभा की परम्पराओं का सवाल है। इन्होंने 6 विधायकों को सदन से बाहर निकाल कर विधान सभा गेट से बाहर बिठा दिया। उन्हें कहा गया कि वे परिसर में न आएं। दूसरा, इन्होंने ऐसी-ऐसी धाराओं के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज करवा दी जो बनती ही नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, आप कानून ज्ञाता है। आप वकील भी हैं। आप सब कुछ जानते हैं। मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि क्या विधान सभा परिसर के अंदर एफ0आई0आर0 दर्ज हो सकती है या नहीं? आप इसमें स्पीकिंग ऑर्डर पास करें कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। इन्होंने एफ0आई0आर0 दर्ज की थी। ये कहते हैं कि राज्यपाल महोदय को खतरा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम आतंकवादी है? हम 5-5, 6-6 बार विधान सभा में चुनकर

19.03.2026/1240/RKS/YK-2

आए हैं। क्या हमारे पास कोई हथियार था जो हम कोई ऐसी वारदात करते? ...(व्यवधान) आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? यह आपके समय में हुआ है। यह आपकी डायरेक्शन पर हुआ है। आपने विधान सभा के अंदर पुलिस एंटर करवाई। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि विधान सभा परिसर में पुलिस कैसे एंटर हुई? ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सस्पेंड रहना अलग बात है। ...(व्यवधान)

Speaker : That is within the Doman of Speaker. ये एफ0आई0आर0 की बात कर रहे हैं। Can a FIR be lodged against the Hon'ble Members in pursuance to any act which we do while conducting a Business. ...(Interruption)

उप-मुख्य मंत्री : आपने पुलिस से एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई। ...(व्यवधान)

Speaker : Let him complete. ...(Interruption) नेता प्रतिपक्ष जी आप इनको बोलने दीजिए इसके बाद मैं आपको बोलने का पूरा समय दूंगा।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा देश के इतिहास में किसी असैम्बली में पहली दफा हुआ है। लोक सभा या राज्य सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ। ...(व्यवधान) ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं। ...(व्यवधान) यहां पर श्री विपिन सिंह परमार जी भी बैठे हैं। ...(व्यवधान) ये कहते हैं कि इसमें मैं भी था। ...(व्यवधान) इन्होंने डी0एस0पी0 से एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई जो बाहर का आदमी था। ...(व्यवधान) मेरा तो सीधा प्रश्न है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ...(व्यवधान) ये कह रहे हैं कि मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड करना आपका राइट है। आप किसी भी विधायक को बाहर कर सकते हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1245/बी.एस./वाई.के.-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

आप यह भी कर सकते हैं, सस्पेंड करना राइट है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, एफ0आई0 आर0 दर्ज करना इस पर रुलिंग आनी चाहिए और यह देश की परंपराओं का सवाल है। ऐसा देश में किसी जगह नहीं हुआ और यह सिर्फ हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो किया है, जो उस समय आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने किया, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...मैं आपसे यह चाहता हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप रुलिंग दें, स्पीकिंग ऑर्डर दें अन्यथा आने वाले समय में भी कोई-न-कोई ऐसा हुक्मरान आ जाएगा जो फिर से कहेगा कि एम0एल0ए0 पर एफ0आई0आर0 की जाए। मैं यह बहना चाहता हूं कि एम0एल0ए0 पर एफ0आई0आर0 इस कैंपस की परिधि में नहीं हो सकती। उसके बारे में आपका फैसला आना चाहिए।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह आदरणीय जय राम जी की अगुवाई में पहली दफा हो रहा है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ आप प्रिविलेज दे आये। यह भी फर्स्ट टाइम हो रहा है। यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। आप चर्चा में हिस्सा लो न। आपको मुख्य मंत्री से कोई परेशानी है, उसे भी आप यहां पर रखिए। लेकिन, ...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, पहली दफा यह हो रहा है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। आप सुनिए। आप भी बाहर कई कुछ बोल रहे हैं। हम भी अपने छः-सात आदमियों को कह देते कि जाइए और जय राम जी के खिलाफ जाकर प्रिविलेज दे दो। यह कौन सी परंपराएं आप डाल रहे हैं? नियम- 75 (1) किस चीज के लिए बना है? ...(व्यवधान)...

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सब झूठ लिखा गया है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : कृपया शांत रहिए। उद्योग मंत्री जी कृपया बैठ जाइए।

उप- मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय,जो इन्होंने प्रिविलेज डाक्यूमैंट दिया है, इस पर प्रिविलेज बनता है, क्योंकि उसमें सब कुछ झूठ लिखा है।

Speaker : Please take your seats. ...(Interruption) माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। Let the Hon'ble Deputy Chief Minister complete his speech.

19.03.2025/1245/बी.एस./वाई.के.-2

...(Interruption) नहीं, I will allow. माननीय मुकेश जी you want to yield? Okay, you don't want yield. ...(Interruption) इनको बोलने दीजिए मैं आपको भी बोलने के लिए समय दूंगा।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं, पहला यह है कि सदन के अंदर कोई भी मेंबर कुछ भी बोलता है उसके ऊपर defamation नहीं हो सकती। एक बात तो यह है। दूसरा, सदन के कैंपस के अंदर किसी एम0एल0ए0 के खिलाफ एफ0आई0आर0 नहीं हो सकती। यहां एम0एल0ए0 की बात हो रही है। आप जो गोलियों की बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो विधान सभा कैंपस की बात कर रहा हूं। कैंपस में एम0एल0ए0 के विशेष अधिकार हैं और उनको हर हालत में प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए।

अब हमारे गांधी जी बैठे हैं। कल इन्होंने कहा, मेरे 32 दांत हैं। मैं प्रडिक्ट करता हूं कि कांग्रेस के लोग आएंगे उनके गलों में जूते के हार डाले जाएंगे। ...(व्यवधान)...आप मेरी बात सुनिए। आपको मैं बताऊं, आप सुनिए।...(व्यवधान)... आप सुनिए। बहुत जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। ऐसा है, आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। Anti-incumbency सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती है वह विपक्ष की भी होती है। पता लगेगा कि कितने वापस आते हैं। आप गलतफहमी निकाल दो और यह दिमाग से निकाल दो कि हम तो हवाओं में बह करके यहां आ जाएंगे। यह जो आपके दिमाग में चल रहा है न उस समय पता लगेगा। लेकिन यह कह कर लोगों को उकसाने का प्रयास नहीं होना चाहिए।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1250/डीटी/एजी-1

उप-मुख्य मंत्री जारी

आज आप हमारे लिए करेंगे कल आपके ऊपर यह बात आएगी।

अध्यक्ष : ये जिसका रेफरेंस कर रहे हैं यह आपकी स्टेटमेंट है जो अखबारों में आई है। आपका ओडियो भी है, let him refer.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, किसके गले में कब क्या पड़ जाए, किसके सांप पड़ जाए, किसके माला पड़ जाए, यह तो समय बताएगा। लेकिन यह भाषा ठीक नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम आप से संरक्षण चाहते हैं। यह एक अलग ही परंपरा हो गई कि जब मुख्य मंत्री और उप-मुख्यमंत्री बोलते हैं तो हम बोल ही नहीं सकते। उप-मुख्य मंत्री जी इस सारे विषय को किस संदर्भ में जोड़ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। आपकी क्या बात हुई है, मुझे मालूम नहीं है? आप सारी चीजों की सैटिंग आपस में करते रहो लेकिन गलत बात मत करिए। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो कहा जा रहा है कि FIR हुई उसकी परिस्थिति के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि यह स्थिति पूरे देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुई जब राज्यपाल महोदय को रोका गया, उनके खिलाफ slogan shouting हुई, उसके बाद गाड़ी में बैठने से रोका गया और उन्हें धक्का दिया गया। अगर हमारे विधायक वहां पर साथ नहीं होते तो राज्यपाल महोदय जी नीचे गिर जाते। वे अपने परिवार के साथ आए थे। हद तो यह हो गई कि अगर ऐसा कोई दूसरा विधायक करता तो हमें समझ में आता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल महोदय को इस प्रकार रोक करके खड़े हो गए। ये उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। वहां पर जिस तरह की परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में क्या करना था? कार्यवाही कानून के मुताबिक होनी थी। विधान सभा से अनुमति ली गई और जो यहां पर जो DSP तैनात थे उनकी ओर से FIR दर्ज की गई। इसमें क्या गलत किया गया? कानून सबके लिए है। आप कानून से ऊपर नहीं है। हम भी कानून से ऊपर नहीं है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कानून के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो

19.03.2026/1250/डीटी/एजी-2

सकती है? कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी, निश्चित रूप से होगी। दूसरा, अध्यक्ष महोदय सस्पेंशन करने का अधिकार विधान सभा अध्यक्ष को तब भी था जब हमारी सरकार सत्ता में थी। यह अधिकार आज भी है और आगे भी रहेगा। ...(व्यवधान) निकालने का भी है। हां, आपके दिमाग में वही बात बैठी है और इसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जब निकालेंगे तब हम देखेंगे। इसमें भी कानून बना है। ...(व्यवधान) जो घटना घटित हुई उसमें हमने भी नारे लगाए। आपको लगा कि यह उचित नहीं इसलिए आपने कार्रवाई की। Including me, we were suspended from the House. हम लोग जब तक सस्पेंड थे, तब तक हमें हाउस के अंदर आने की अनुमति नहीं थी और वही आपके साथ हुआ। ऐसा थोड़ी है कि हमने कोई अलग से फैसला लिया है। जो कुछ भी फैसला लिया गया वह नियम और कानून के अनुसार लिया गया है। लेकिन आज प्रश्न पैदा होता है कि महामहिम राज्यपाल को जिस वक्त आपने धक्के मारे थे, जिनके खिलाफ नारे लगाए थे, वह भी आज यहां के गवर्नर नहीं है। जिन्होंने राज्यपाल अभिभाषण अबकी बार प्रस्तुत किया, वह भी आज यहां गवर्नर नहीं है। वे दूसरे राज्य में चले गए हैं। आप पासिंग रेफरेंस में कह सकते हैं लेकिन आप इस प्रकार सारी व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही विधान सभा के नियम के अनुसार नहीं है। उप मुख्य मंत्री जब इतने लंबे समय से हैं तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे। सत्ता पक्ष में रहते हुए आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। यह जरूरी नहीं है कि जो मुख्य मंत्री जी करते हैं, वह आप भी करें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कम से कम सब्र रखें, संयम रखें और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलें।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि विपक्ष के लोग ही बोलते रहेंगे (श्री इन्द्र सिंह गांधी को बोलते हुए।)। जब इनकी बारी आएगी तब ये बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कह दी है, यह ठीक है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

19.03.2026/1255/ए.जी.-एन.जी./1

उप-मुख्य मंत्री..... जारी

...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

Speaker: Gandhi ji, please take your seat. ...(व्यवधान) बाद में समय दूंगा।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता कि हर आदमी बोलता जाएगा।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।। have not allowed.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी ने भी दोनों राज्यपाल महोदय की तुलना की थी और मैं उसी को रिसपोंड कर रहा हूं। इन्होंने पिछले कल कहा था कि पहले राज्यपाल महोदय आए तो उनके बारे में क्या था और दूसरे राज्यपाल महोदय आए थे तो उनके बारे में क्या था। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा की तो बड़ी अच्छी परम्पराएं रही हैं लेकिन जिन राज्यों में कुर्सियां चलती हैं और माइक उतार कर एक-दूसरे पर मारे जाते हैं, वहां पर भी आज तक कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई है। लेकिन इस प्रदेश में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है।...(व्यवधान) सत्ती जी, क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि एम0एल0ए0 पर इस कैंपस के अंदर एफ0आई0आर0 दर्ज हो?...(व्यवधान) क्या यहां पर कोई ऐसा मसला आया?...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इन्होंने...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य, श्री सतपाल सिंह सत्ती, अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय उप-मुख्य मंत्री के साथ बहस करने लगे।)

Speaker : Satti ji, please take your seat. ...(व्यवधान)

19.03.2026/1255/ए.जी.-एन.जी./2

उप-मुख्य मंत्री : सत्ती जी, अगर आपके दिल में तमन्ना है तो आप वह भी कर लीजिए। हम भी देख लेंगे कि तब क्या होगा।...(व्यवधान) क्यों नहीं है...(व्यवधान) ऐसा है, एम0एल0ए0 एक लाख-सवा लाख आदमियों में से चुन कर आता है और यहां पर उसका विशेषाधिकार होता है।...(व्यवधान)

Speaker : Satti ji, please, let the Hon'ble Deputy Chief Minister speak. ...(व्यवधान) Please, don't interrupt him? सत्ती जी, आप जितना ज्यादा इंट्रप्ट करेंगे उससे बेवजह व्यवधान उत्पन्न होगा।...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : सत्ती जी, इस प्रकार से आपको आइना दिखाया जा रहा है।...(व्यवधान) आपको आइना दिखाया जा रहा है।...(व्यवधान) सत्ती जी, आप जब प्रशासक थे, तब आपने क्या किया?...(व्यवधान) आप आज इस तरह से बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री सतपाल सिंह सत्ती : उप मुख्य मंत्री जी, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलिए।...(व्यवधान)

उप-मुख्य मंत्री : सत्ती जी, मैं अभिभाषण पर ही बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

Speaker : Please, don't interrupt him.

उप-मुख्य मंत्री : सत्ती जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?...(व्यवधान) आप तो उस समय इस सदन में मौजूद ही नहीं थे और आपने कुछ देखा ही नहीं है कि इन्होंने (श्री जय राम ठाकुर जी को कहा) हमारे साथ क्या-क्या किया है।...(व्यवधान)

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अच्छा हुआ मैं नहीं था, (***)। (अपने स्थान से बिना अनुमति के कहा गया)

19.03.2026/1255/ए.जी.-एन.जी./3

उप-मुख्य मंत्री : सत्ती जी, वह तो अब भी देख लेंगे।...(व्यवधान) (***)।...(व्यवधान) आप कोई गलतफहमी में मत रहना। क्या (***)है?...(व्यवधान)

Speaker: Please, please. इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें।...(व्यवधान) ऐसे शब्दों का उपयोग तो पंजाब की विधान सभा में होता है।...(व्यवधान) Don't use such kind of language. ...(व्यवधान) सत्ती जी, आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।...(व्यवधान) Don't use such type of words? They will not form part of the record.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिससे इन्होंने एफ0आई0आर0 करवाई उन्होंने लिख कर दे दिया है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने हमें आपके खिलाफ एफ0आई0आर0 करने के लिए विवश किया था। वह सारा रिकॉर्ड सामने आ गया है।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि इस दस्तावेज में आर0डी0जी0 की बात आई और यह बात असंवैधानिक है।...(व्यवधान) यहां पर 16 पैरों की बात हो रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में यह बिल्कुल स्पष्ट है और इस अभिभाषण के पहले पन्ने पर ही इसे मेंशन कर दिया गया है। जो भी Consolidated Fund of India होगा या भारत सरकार का जो कोष होगा, उसको राज्यों की सरकारों में उनकी मांग व जरूरतों के मुताबिक दिया जाएगा। यह कानूनन और संवैधानिक प्रावधान है। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, आप विपक्ष की ओर ध्यान मत दें और अपना भाषण जारी रखें।

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

19.03.2026/1255/ए.जी.-एन.जी./4

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आपका आर0डी0जी0 पर क्या स्टैंड है? जी0एस0टी0 का कंपनसेशन बंद हो गया और हिमाचल प्रदेश को नुकसान हो गया।...(व्यवधान) क्यों नहीं हुआ?...(व्यवधान)हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। जी0एस0टी0 का फायदा केवल उन राज्यों को हुआ है...(व्यवधान)

Speaker : Please, no interruption.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जी0एस0टी0 का फायदा उन राज्यों को हो रहा है, जहां पर चीजें बिकती हैं। हम उत्पादक राज्य हैं और हमारे प्रदेश को जी0एस0टी0 लगने से 3-4 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हम नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से जानना चाहते हैं कि जी0एस0टी0 कंपनसेशन बंद होने पर आप सब की क्या राय है?

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1300/ए.पी. /ए.एस. -1

राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा जारी ...

उप-मुख्य मंत्री जारी .....

अध्यक्ष महोदय, आर0डी0जी0 बंद होने से हिमाचल प्रदेश को हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हमने कहा था कि सदन में प्रस्ताव पास कर लेते हैं, लेकिन उस समय आप बाहर चले गए और साथ नहीं दिया। आर0डी0जी0 के मुद्दे पर आप कहते हैं कि आप दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर आए हैं। यदि वहां से कोई पत्र या चिट्ठी मिली है तो उसे सदन के समक्ष रखें, ताकि स्पष्ट हो सके कि आपने वहां क्या कहा। कहीं ऐसा तो नहीं आपने हि दिया कि प्रदेश का हुक्का-पानी भी बंद कर दिया जाए। आप आर0डी0जी0 पर अपना स्पष्ट स्टैंड बताइए। हमने तो उस समय यह भी कहा था कि हम आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप उस समय भी तैयार नहीं हुए। अकेले जाकर आपने क्या बात की, यह किसी को पता नहीं। जी0एस0टी0 बंद होने पर भी आप नहीं बोले, आर.डी.जी. बंद होने पर भी आप कुछ नहीं बोले। आपके समय में आर0डी0जी0 से 75,000 करोड़ रुपये मिले थे। वर्ष 2022 में जैसे ही हमारी सरकार आई, जी0एस0टी0 का कम्पनसेशन बंद हो गया। उस समय आपके पास दो-चार महीने बचे थे (तंज कसते हुए कहा कि जाती बहार के मेले थे)। उसके बाद वर्ष 2026 में आर0डी0जी0 ग्रांट भी बंद हो गई। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने साहस दिखाकर कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 दी। यह आसान काम नहीं था। पंजाब सरकार भी अभी तक ओ0पी0एस0 नहीं दे पाई है। जब सदन में ओ0पी0एस0 की बात होती थी तो माननीय जय राम जी कहते थे कि चुनाव लड़ो और पेंशन लो। उन्होंने कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 से साफ इंकार कर दिया था। अब भी वे कहते हैं कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो ओ0पी0एस0 को फिर से बंद कर दूंगा। पूर्व सरकार ने तो कर्मचारियों के 12,000 करोड़ रुपये के एरियर नहीं दिए। आपने कर्मचारियों को न एरियर दिया और न ही ओ0पी0एस0 दी। फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी आपके लिए काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब कर्ज की लिमिट बढ़ाने की बात

होती है तो विपक्ष कहता है कि इसे कम किया जाए। विदेशी फंडिंग पर कैप लगती है तो भी विपक्ष कुछ नहीं बोलता। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आकर आपदा

19.03.2026/1300/ए.पी. /ए.एस. -2

राहत के लिए 1,500 करोड़ रुपये का ऐलान करके चले गए लेकिन वह पैसा अभी तक नहीं आया। उस पर भी विपक्ष कुछ नहीं बोलता। प्रधानमंत्री जी का बोला हुआ पत्थर पर लकीर होना चाहिए। आप ही बताइये कि वे पैसा कब आएगा? क्या उस पैसे को टायर लगे है, जो दिल्ली से चला है और सोनीपत या कर्नाल पहुंचा है, आप बता दें तो वहां पर जा कर पैसे ले आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही आशचर्यजनक है कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा जोकि इतने एम0पी0 और मंत्रियों के बीच में हुई और आज तक वह पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक हमें वर्ष 2023 की आपदा का पूरा पैसा नहीं आया है। वर्ष 2024 और 2025 का कब आएगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है। जल जीवन मिशन का 1,227 करोड़ रुपये आना था, वह भी अभी तक नहीं आया। इन्होंने कब से सत्ता छोड़ी है। कल ही एम0ओ0यू0 साइन करने की बात कही गई है। हमने सचिव को कहा है कि एम0ओ0यू0 साइन कर आएं ताकि लोगों ने जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम किया है उसका उनको पैसा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के लिए दो काम बहुत ज़रूरी हैं। पहला, हवाई अड्डा बनाना। यह इनके समय में हवा में ही रह गया। माननीय जय राम ठाकुर जी इसे बनाना चाहते थे, उसके लिए बजट भी था, लेकिन उसका क्या हुआ यह स्पष्ट नहीं है। उस समय आप मुख्य मंत्री थे, आपको बताना है कि वह पैसा कहा गया? मंडी का हवाई अड्डा हवा-हवाई हो गया। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हवाई अड्डा बनाने का काम केंद्र सरकार का है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.03.2026/1305 /AT/AS/01

उप-मुख्यमंत्री जारी...

हवाई अड्डे बनाने का काम केंद्र सरकार का है। अभी बिहार के चुनाव हुए थे और प्रधानमंत्री जी ने वहां तीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार में एयरपोर्ट बनाएगी तो केंद्र सरकार हिमाचल में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना सकती। हिमाचल में चाहे पहले से जो एयरफील्ड हैं उनका विस्तार किया जाता। लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में निर्णायक काम किया है। गगल एयरपोर्ट के लिए लगभग जमीन खरीदने का काम पूरा होने के करीब है और लगभग 2000 करोड़ रुपये जमीन की पेमेंट भी कर दी गई है। अब अगर जमीन पूरी हो जाती है तो उसके बाद कम-से-कम आप केंद्र सरकार से कहो कि वह हिमाचल में एयरपोर्ट बनाने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय रेलवे का है, अंग्रेजों के समय रेल विस्तार हिमाचल पहुंचा था। लेकिन उसके बाद रेल की वर्तमान में किस तरह की स्थिति है? लेकिन वर्तमान में बिलासपुर तक रेल पहुंच गई है। हम बार-बार कह रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाए क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्वाइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे का आगे लेह तक विस्तार करना है। बिलासपुर से आगे वह कैसे आगे जाएगी? आगे एक सीमेंट का कारखाना है अडानी चाहता है कि वह रेल लाइन उसके कारखाने से होकर जाए। अडानी के कारखाने तक रेल पहुंचाने की बात है तो वह सब केंद्र सरकार देखे क्योंकि वह उनके मित्र हैं। तो उसका खर्च भी केंद्र सरकार ही लगाए।

जहां तक प्रदेश सरकार की बात है तो हम बिलासपुर तकरेल लाइन पहुंचाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ताकी रणधीर जी....(व्यवधान) नहीं ऐसा नहीं है,नहीं ऐसा नहीं है हमारी कमिटमेंट बिलासपुर तक है और बहुत जल्द बिलासपुर तक रेल पहुंच जाएगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी मिशन लोटस करने की कोशिश की लेकिन वह मिशन सफल नहीं हुआ। अब जय राम जी ने....(व्यवधान) जय राम जी आपने कोई रहम नहीं किया। उस मिशन के बाद अब आपने तौबा कर ली है और

19.03.2026/1305 /AT/AS/02

अब आप कान पकड़ेगे। इसीलिए तो आप राज्यसभा चुनाव के दोरान कैंपस के नजदीक भी नहीं आए ....(व्यवधान) कुछ नहीं होना था,जब हो सकता था, तब भी कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया लेकिन वह विफल रहा। जय राम जी ने तो यहां तक कह दिया था कि इस सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। इतना ही नहीं ये तो लोक भवन में गवर्नर साहब से भी मिलने चले गये थे। अब जब ऑपरेशन लोटस फेल हो गया तो ये बाबा बन गए हैं। कल कह रहे थे कि तुम्हें श्राप लगेगा।.....(व्यवधान) अब ये श्राप देने पर आ गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से यह कहना चाहता हूं कि ये वहां पर बैठे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन कृपया बार-बार मत उठा करें.....(व्यवधान) आगे क्या होगा यह समय बताएगा।

इब्तिदा-ए-इश्क है रोता है क्या,
आगे- आगे देखिए होता है क्या ।

आगे क्या होगा वह तो समय ही बताएगा।

अध्यक्ष महोदय, ये मुझे बोलने नहीं देना चाहते, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब इस सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न स्थगित की जाती है।

19.03.2026/1415/केएस/डीसी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : हर्षवर्धन जी, अभी आपकी लिस्ट में पांच ही नाम हैं और पांच में से भी एक ने चर्चा में भाग ले लिया है और अब चार ही बचे हैं। प्रतिपक्ष से 9 नाम हैं। या तो लिस्ट अपडेट कर लीजिए नहीं तो फिर 2:1 होगा । अब मैं माननीय श्री रणधीर शर्मा जी से आग्रह करुंगा कि वे इस चर्चा में आगे भाग लें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी को बजट सत्र शुरू होने पर महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया था जिस पर ठीक एक महीने बाद सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा चल रही है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस बार बहुत कुछ नया हो रहा है। यह बजट सत्र 16 फरवरी, 2026 से शुरू हो कर 2 अप्रैल, 2026 तक चल रहा है। बैठकें तो 16 हो रही हैं, छुट्टियां 33 हैं। 16 बैठकों के सत्र में 30 दिन का डायरैक्ट अवकाश है और ऐसा पहली बार हुआ है। यह भी पहली बार हुआ है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा उस पर टिप्पणी की है। यहां पर हमारे सत्ता पक्ष के साथी बोल रहे थे कि ऐसा पहले भी होता आया है कि महामहिम राज्यपाल कह देते हैं कि अभिभाषण को पढ़ा हुआ समझा जाए। परंतु इस बार पढ़ा हुआ समझा जाए नहीं कहा गया। जो शब्द महामहिम राज्यपाल ने कहे हैं और जो ऑफिस रिकॉर्ड में हैं, मैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि पैरा संख्या 3 से लेकर पैरा संख्या 16 तक संवैधानिक संस्था के संदर्भ में टिप्पणियां हैं और मैं नहीं समझता कि मुझे इन्हें पढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो 13 पैराग्राफ हैं, ये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हिस्सा नहीं समझे जाएंगे। यह ठीक है कि उसके बाद उन्होंने कहा कि पैरा नम्बर-16 के बाद अभिभाषण पढ़ा हुआ समझा जाए। इसलिए यह कहना कि

ऐसा पहले भी होता आया है, ऐसा नहीं है। इस अभिभाषण में सरकार की जो आदत है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं से टकराव लेना, वह इन 13

19.03.2026/1415/केएस/डीसी/2

पैरों से नज़र आता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा पहले नहीं हुआ, इस सरकार की आदत बनी है। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

19.03.2026/1420/av/dc/1

श्री रणधीर शर्मा--------- जारी

इस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और शहरी निकायों के चुनाव के लिए चुनाव आयोग से टकराव लिया और चुनाव आयोग का अपमान किया। इस सरकार ने और मुख्य मंत्री जी ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों पर टिप्पणियां कीं और ऐसा करके इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का भी अपमान किया। इस अभिभाषण में वित्तायोग से टकराव लेकर इस सरकार ने उसका अपमान करने का भी काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, यही नहीं; इस सरकार ने लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तम्भ मीडिया से भी लगातार टकराव लिया है। उप-मुख्य मंत्री जी को अपने ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज होने का तो दर्द था परंतु इस सरकार के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ खबरें छापने के लिए जो पत्रकारों पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुई, उस पर उप-मुख्य मंत्री जी कुछ नहीं बोले जोकि खुद पहले एक पत्रकार रहे हैं। इनको उन पत्रकारों का दर्द नज़र नहीं आया जिन पत्रकारों के साथ अभी तीन दिन पहले हाथापाई की गई। हरियाणा के विधायक शिमला में रखे गए। उस खबर को कवर करना मीडिया का फर्ज था। मीडिया कर्मी वहां पर खबर को कवर करने जाते हैं और पुलिस उनको ऐसा करने से रोकने के लिए उनसे हाथापाई करती है और सरकार मूकदर्शक बनी रहती है। इन्होंने आज मीडिया को भी अपना बन्धुआ मजदूर बनाने की कोशिश की है। यह ठीक है, टकराव लेना तो माननीय मुख्य मंत्री की

पहले से आदत रही है। एन0एस0यू0आई0 के समय स्व0 राजा वीरभद्र सिंह जी से टकराव लेकर रखा। परंतु अब तो आप मुख्य मंत्री बन गए हैं, आप अब तो इस आदत को छोड़ दीजिए। अभी भी चाहे मंत्रियों के साथ टकराव है या अधिकारियों के साथ है; ये एक टकराव लेकर इस सरकार को चला रहे हैं जोकि न तो प्रदेश हित में है और न ही इस सरकार के हित में है।

इस सरकार ने संसद में पारित बिल पर अमेण्डमैंट पास करवाई है। इन्होंने तो संसद का भी अपमान किया है। हद तो तब हो गई जब वर्ष 2005 में डॉ0 मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इनकी ही सरकार के कार्यकाल में संसद में 'सूचना का अधिकार' बिल पास होता है तो उस पर भी कैबिनेट की मीटिंग में अमेण्डमैंट कर दी। इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना इनकी आदत बन गई है।

19.03.2026/1420/av/dc/2

अध्यक्ष महोदय, ये यहां पर जिस आर0डी0जी0 की चर्चा करते हैं और जिसके लिए आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं तथा राजनीति करते हुए कह रहे हैं कि आप साथ नहीं देते उस पर ये कितने गम्भीर है, यह आप खुद देख सकते हैं। मैं इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इन्होंने आर0डी0जी0 पर विधान सभा की परम्पराओं को तार-तार किया है। बजट सत्र के दौरान कभी भी तीन दिन के बाद अवकाश नहीं हुआ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है और उस पर चर्चा होती है। लेकिन ये आर0डी0जी0 पर चर्चा ले आए और तीन दिन बाद ही सत्र स्थगित कर दिया कि अब पूरी कैबिनेट इस प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के पास जाएगी। लेकिन दिल्ली जाकर ये न तो प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं और न ही वित्त मंत्री जी से मिलते हैं अपितु वहां पर अपने आलाकमान से मिलते हैं। उस समय दिल्ली के अंदर जो ए0आई0 इम्पैक्ट समिट चली हुई थी, उसमें वहां सौ देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे। उस दौरान ये वहां नग्न प्रदर्शन करने की रचना करते और उसके सूत्रधार माननीय मुख्य मंत्री बन जाते हैं। दिल्ली में उन उपद्रवियों को जिन्होंने देश की छवि को पूरे विश्व में धूमिल किया, उनको हिमाचल में छिपाकर रखने का काम करते हुए उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं। यहां

दिल्ली की पुलिस आती है तो उनको उन्हें पकड़ने नहीं देते। उन उपद्रवियों को दिल्ली से लाकर शिमला की वादियों में रखा जाता है। मुख्य मंत्री जी वहां प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को मिले बिना शिमला आ जाते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी आर0डी0जी0 के संदर्भ में इस प्रकार की गम्भीरता है। यहां आकर भी उन उपद्रवियों को बचाने के लिए हिमाचल पुलिस की दिल्ली पुलिस से भिड़ंत करवा देते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में ए0आई इम्पैक्ट समिट के दौरान किया गया नग्न प्रदर्शन एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था। यहां पर पिछले कल श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी कह रहे थे कि हरियाणा में भी नग्न प्रदर्शन हुआ। अरे! हमें आपके नग्न प्रदर्शन से कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने मर्जी नग्न प्रदर्शन कीजिए। परंतु ऐसा करते हुए स्थान और समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। जब यहां पर सौ देशों के प्रतिनिधि आए हों तो उस समय यहां पर नग्न प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी?

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1425/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री रणधीर शर्मा ... जारी

इस तरह आर0डी0जी0 के बजाय इस राष्ट्रवादी कृत्य को मुख्य मंत्री जी ने प्राथमिकता दी, ये इनकी गंभीरता है। ये सिर्फ राजनीतिक करना चाहते हैं, यहां मुख्य मंत्री जी भी पूछ रहे थे कि आप आर0डी0जी0 के पक्ष में खड़े हैं या विरोध में खड़े हैं। इतिहास पूछेगा जब आर0डी0जी0 गई तो आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं कि जब अटल जी द्वारा दिया गया विशेष औद्योगिक पैकेज की समय सीमा, डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने कम की थी तो आपने क्या किया था तो आप क्यों नहीं प्रदेश के साथ खड़े हुए थे, तब प्रदेश के हित कहां गए थे? वर्ष 2010 में डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने प्रदेश की आर0डी0जी0 को कम कर दिया था बाकी प्रदेशों में बढ़ोतरी की गई और हिमाचल की आर0डी0जी0 कम कर दी गई थी क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अन्याय तो हिमाचल प्रदेश के साथ तब हुआ था, तब आप कहां थे, तब हिमाचल प्रदेश के हित कहां थे? आदरणीय अटल जी ने

हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया था लेकिन डॉ मनमोहन सिंह जी ने वह भी छीन लिया, तब भी आप चुप रहे, तब क्यों नहीं बोले? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने फिर से विशेष राज्य का दर्जा बहाल किया और आज हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय योजना में 90 प्रतिशत पैसा मिलता है। इसलिए दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय जरा पहले अपने गिरेबान में भी झांके कि हम स्वयं क्या कर रहे हैं, कितनी गंभीरता से काम करते रहे हैं, यह बताने की आज आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के हालात के बारे में भी बताना चाहता हूं। आज उप-मुख्य मंत्री जी को एफ0आई0आर0 का दर्द था। इतिहास में पहली बार एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई। इतिहास में पहली बार तो आपने राज्यपाल महोदय का धेराव किया था। विधान सभा सदन के अंदर कुछ भी होता है परंतु आपने राज्यपाल महोदय की गाड़ी

पार्किंग में रोकी। उसके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं होनी थी तो क्या होना था। आप जब इतिहास में पहली बार गलती करोगे तो उसकी सजा भुगतने को भी तैयार हरना पडेंगा। मुख्य मंत्री जी संविधानिक पद पर बैठे हैं। 3 साल के जश्न का कार्यक्रम मंडी में था। ...(व्यवधान) जश्न का था मैं रुलिंग पढ़ दूंगा। सेलिब्रेशन को क्या बोलते हैं? आपकी नोटिफिकेशन है और उसमें उप-मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा है, मुख्य मंत्री महोदय, आपको डंडा उठाना पड़ेगा, यह भाषा उप-मुख्य मंत्री की है। अधिकारी काम नहीं कर रहे, इन्हें हमें रात के अंधेरे में निपटाना पड़ेगा, ये शब्द उप-मुख्य मंत्री महोदय के हैं। आप संविधान की शपथ लेकर जनसभा के अंदर किस तरह के भाषण दे रहे हैं। ...(व्यवधान) वह रिकॉर्ड पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने रात के अंधेरे में अधिकारी निपटाए या नहीं निपटाए लेकिन अधिकारियों ने इन्हें दिन के उजाले में निपटाना शुरू कर दिया और फिर आपको बड़ा दर्द हुआ। लोक निर्माण मंत्री जी कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों के अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी

कहते हैं कि कुछ हिमाचल के भी हैं जो हमारा काम नहीं कर रहे हैं और श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने तो अधिकारियों के साथ हाथापाई तक कर दी, ये मंत्रियों के हालात है। आपने संविधान की शपथ ली है और मैं कहना चाहता हूं या तो मंत्री सक्षम नहीं हैं जो अधिकारियों से काम ले सके या अधिकारी बेलगाम है जो मंत्री की सुनते नहीं है परंतु दोनों स्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। प्रदेश के लिए नुकसानदायक, प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। न अधिकारी इनकी सुनते, न मुख्य मंत्री जी इनकी सुनते हैं। विधायक भी दुःखी, सरकार भी दुःखी और जनता भी दुःखी है। आज इस हालत में हिमाचल प्रदेश की सरकार है। माननीय मंत्री श्री गोमा जी अभी यहां नहीं बैठे हैं। वे तो एक अधिकारी पर प्रिविलेज मोशन लेकर आए। आज तक इतिहास में कभी सुना है, ...(व्यवधान) हम तो ला सकते हैं। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कोई मंत्री किसी अधिकारी पर इस तरह से प्रिविलेज मोशन लाया हो लेकिन उनके प्रिविलेज मोशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उद्योग मंत्री, श्री हर्षवर्धन चौहान जी ने पता नहीं क्या बयान दिया।

19.03.2026/1425/टी0सी0वी0/एच0के0-3

अध्यक्ष महोदय, सरकार की हालत क्या बताएं? जिस सरकार का चीफ सेक्रेटरी कार्यवाहक हो, ब्यूरोक्रेसी का हैड ही रेगुलर न हो, जिस सरकार का डी0जी0पी0 कार्यवाहक हो

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1430/NS-HK/1

श्री रणधीर शर्मा------जारी

और रेग्युलर नहीं हो तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा? उन प्रदेशवासियों की क्या हालत होगी? अब बताइए कि वे अग्निवीर हैं या ट्रेनी हैं। उप-मुख्य मंत्री जी, अब सदन में पहुंचे और मैंने जो बातें कही हैं आप उनका अवश्य जवाब दें। आपने संविधान की शपथ लेकर अधिकारियों को निपटाने की बात की थी। आज वही अधिकारी आपकी सरकार को निपटाने के लिए तैयार बैठे हैं और समय आने वाला है। इसलिए जो सरकार रेग्युलर मुख्य सचिव नहीं लगा सकती, जो सरकार रेग्युलर डी0जी0पी0 नहीं लगा सकती वह सरकार क्या काम करेगी? जो मुख्य मंत्री तीन वर्षों में एक मंत्री, डिप्टी स्पीकर नहीं बना सके तो वे क्या काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय यहां बैठे-बैठे थक जाते हैं। हम इस सरकार का क्या करें? ...(व्यवधान) आपने विधानसभा में बोला और फिर कहते हैं कि प्रिविलेज क्यों लाए? जब बजट में झूठ बोलेंगे और सदन को गुमराह करेंगे तो प्रिविलेज ही लाएंगे फिर क्या करेंगे? आपने कहा था कि कुछ ही दिनों में खुशखबरी मिलेगी कि श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी मंत्री बनेंगे। नवरात्रि भी आ गए लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी ही नहीं आई। मुख्य मंत्री जी की बात का वजन होता है और सदन में कही गई बात का ज्यादा महत्व होता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात है, इसमें वैसे तो बहुत कम लिखा गया है परंतु जो लिखा गया है उसका जिक्र करना जरूरी है। इसमें प्रदेश सरकार के मुद्दे बहुत कम हैं और केंद्र सरकार के बहुत ज्यादा हैं। अगर उनकी चर्चा करें तो आपको लगेगा कि यह केंद्र सरकार के बारे में अभिभाषण पढ़ा गया है। आर0डी0जी0 पर वर्ष 2010 में जो आपका स्टैंड था, वही हमारा है। जो स्टैंड विशेष औद्योगिक पैकेज छीनने पर आपका था, वही हमारा है। विशेष राज्य दर्जा छूटने पर जो आपका स्टैंड था, वही हमारा है। आप बार-बार क्यों पूछते हैं? इतिहास में आपका नाम भी लिखा हुआ है क्योंकि मुकेश जी उस समय आप भी विधान सभा में थे। जब विशेष राज्य का दर्जा छीना गया तब भी आप विधान सभा में थे। जब विशेष औद्योगिक पैकेज छीना गया तब भी आप विधान सभा में थे।

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें इस अभिभाषण में कही गई हैं और मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहता हूं। इस दस्तावेज के पेज नम्बरः 30 के पैरा संख्या : 79 में लिखा

है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व वृद्धि करने के लिए टोल बैरियर टैक्स 173 करोड़ 89 लाख रुपये बढ़े हैं। यह कैसे बढ़े क्योंकि आपने एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी की। एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी थोड़ी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस वाहन पर पहले 70 रुपये लगते थे उस पर अब 170 रुपये लगेंगे। जिस वाहन पर पहले 110 रुपये लगते थे उस पर भी 170 रुपये लगेंगे। जिस वाहन पर 180 रुपये लगते थे उस पर 320 रुपये लगेंगे। जिस वाहन पर 320 रुपये लगते थे उस पर 600 रुपये लगेंगे। जिस ट्रक का एंट्री टैक्स 720 रुपये लगता था उसके 900 रुपये लगेंगे। जिस वाहन पर 570 रुपये लगते थे उसके 800 रुपये लगेंगे। यहां तक कि ट्रैक्टर पर 70 रुपये एंट्री टैक्स लगता था उसको बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है। यह एंट्री टैक्स हिमाचलवासियों पर है। सिर्फ छोटी प्राइवेट गाड़ियों पर एंट्री टैक्स नहीं है। हिमाचलवासियों के ट्रक, पिकअप, यूटिलिटी, टैक्सी आएगी तो आपने सब पर एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है। आपने इतनी बेतहाशा वृद्धि की है। पिछली सरकार ने हिमाचल की गाड़ियों का एंट्री टैक्स हटा दिया था। उसके लिए हम श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करते हैं। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please. ...(Interruption)प्लीज बैठे-बैठे न बोलें।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं वहां के क्या हालात हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। स्वारघाट में पंजाब से किसी रिश्तेदार ने आना है तो उसे 300 रुपये टैक्स देना पड़ता है। एन0एच0ए0आई0 का भी टोल बैरियर लगा है और हिमाचल का एंट्री टैक्स का टोल बैरियल लगा है। अब पंजाब ने धमकी दी है कि हम भी एंट्री टैक्स लेंगे। फिर हालात क्या बनेंगे? इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उप-मुख्य मंत्री जी आपका भी बॉर्डर का इलाका है और आपको भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पंजाब में जिस पार्टी की सरकार है वह आपकी सहयोगी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब कानून व्यवस्था की बात करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में आज गोलीकांड हो रहे हैं। ऊना, बिलासपुर, बद्दी और नालागढ़ में गोलीकांड हो रहे हैं

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

19.03.2026/1435/RKS/YK-1

श्री रणधीर शर्मा जारी....

आप मुझे बताएं कि आज कहां गोलीकांड नहीं हो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में यह गन कल्चर इसी सरकार के दौरान आया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उप- मुख्य मंत्री महोदय ने भी अपने एक कार्यक्रम में कहा है कि यह गन कल्चर बंद होना चाहिए। इन्होंने अधिकारियों को इस गन कल्चर को बंद करने के निर्देश दिए थे लेकिन अब अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते। वे माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुनेंगे क्योंकि उनके पास यह विभाग है। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार इस गन कल्चर को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज हिमाचल की कानून व्यवस्था कहां तक बिगड़ गई है? आज हर जगह वन माफिया फैल रहा है। सिरमौर के अंदर 25 पेड़ों को काटने की अनुमति लेकर तीन सौ पेड़ काट दिए गए लेकिन दोषियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास इसके सारे फोटोज़ उपलब्ध हैं। उन लोगों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहां पर जो अवैध माइनिंग हुई है उसकी लिखित शिकायत की गई है लेकिन इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अवैध कटान के बार में तो सुना था लेकिन धर्मपुर में तो पिछले साल अवैध डिपो ही खोल दिया गया। उस अवैध डिपो में कितनी लकड़ी थी इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके लिए हमारी पार्टी ने एक टीम गठित की थी और वह टीम इस अवैध डिपो के बारे में सारी बातें बताएगी। बिलासपुर में इसी वन माफिया ने वन अधिकारियों के साथ मारपीट की। इन लोगों को सरकार का संरक्षण मिला है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस सरकार ने हमारे प्रदेश में आज यह हालात खड़े कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के समय जिस तरह से हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसे आप सब लोग देख रहे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? कभी एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर विभाग को ठीक समझा जाता था लेकिन आज इन विभागों में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर मैं सारी डिटेल पढ़ूं तो उसमें समय लगेगा

परंतु मैं कहना चाहता हूं कि हालात भयंकर रूप से खराब हो रहे हैं। आज ट्रेज़री पर ताला लगा हुआ है। ठेकेदारों की पेमेंट के टोकन मिल जाते हैं परंतु ट्रेज़री से पैसा तब जारी होता है जब ठेकेदार कमीशन देते हैं। इस टोकन माफिया की सुई मुख्य मंत्री कार्यालय तक जाती है। आज यह

19.03.2026/1435/RKS/YK-2

हालात इस प्रदेश में बने हुए हैं। ट्रेज़री से पैसा तब निकलता है जब वित्त विभाग से ट्रेज़री को फोन जाता है। आपने आज यह हालात प्रदेश में खड़े कर दिए हैं। फिर आप लोग कह रहे हैं कि हम प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। आप इस अभिभाषण में अपनी गारंटियों का जिक्र करना भूल गए हैं। इस अभिभाषण में गारंटियों, आत्मनिर्भर हिमाचल और व्यवस्था परिवर्तन की कोई चर्चा नहीं हुई है। क्या तीन साल बाद आपने अपना एजेंडा बदल दिया है? आपने कोई गारंटी पूरी नहीं की है इसलिए आपने सोचा कि अब चुप होकर बैठ जाओ ताकि लोगों को चुनाव में कुछ याद न आए। आप व्यवस्था परिवर्तन को भूल गए हैं। आपने वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात की थी। यह वर्ष 2026 चल रहा है और अगली साल वर्ष 2027 भी आ जाएगा लेकिन आपके इस अभिभाषण में तीनों शब्दों का जिक्र ही नहीं है। हम आपको इन गारंटियों की की याद दिलाते रहेंगे। आप इन गारंटियों के सहारे सत्ता में आए हैं और इन गारंटियों के कारण ही आप सत्ता से बाहर जाएंगे, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप सत्ता से बाहर इन्हीं गारंटियों के कारण होंगे। यहां पर आपदा के ऊपर चर्चा हुई। माननीय मुकेश जी कह रहे थे कि हमें केंद्र सरकार से आपदा राहत राशि प्राप्त नहीं हुई। आप तो मंत्री हैं इसलिए आप रिकॉर्ड पढ़ा करें। इस बार PDNA के अप्रूव्ड प्लान में 2006 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं जिसमें से सेंटर का शेयर 1504 करोड़ रुपये है और उसमें से एक हजार करोड़ रुपये प्रदेश को प्राप्त हो चुके हैं। अब आप अपना शेयर न दें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ...(व्यवधान) यह राशि वर्ष 2025 की है। इसी तरह NDRF में 254 करोड़ रुपये आ चुके हैं। SDRF में भी पैसा आ चुका है। मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। ...(व्यवधान) क्या 2006 करोड़ रुपये 1500 करोड़ रुपये से कम होत हैं? मेरे पास जो रिकॉर्ड है वह सरकार के पास भी है। NDRF में यह पैसा आया

है। सर, मैं एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केंद्र सरकार की नीतियों पर बना है। अगर इस अभिभाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा न हो तो यह अभिभाषण अधूरा रह जाएगा। आप देखेंगे इस अभिभाषण में प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा की गई है कि

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1440/बी.एस./वाई.के.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

उसमें मकान बनाए हैं। इस अभिभाषण में चर्चा होती है तो आयुष्मान योजना की कि 54 करोड़ रुपये इस साल आयुष्मान योजना में आये। इस अभिभाषण में चर्चा होती है तो स्वच्छ भारत मिशन की होती है, तो कहा क्या जाता है कि 4,529 व्यक्तिगत और 373 सामुदायिक शौचालय बना दिए। ये सब केंद्र से बने और श्रेय ले रही प्रदेश सरकार। लिखा है कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में 26,306 घर बना दिए। बने किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना में, यह किसकी योजना है? केन्द्र की। स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, आप कह रहे हैं 6 करोड़ रुपये में एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 के 399 मकान बने। यह किसकी योजना है? केंद्र की। आप कह रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 2,969 स्वास्थ्य समूह को 4 करोड़ रुपये दिए गये। यह किसकी योजना है? केंद्र की। ...(घंटी)...मनरेगा में जो 945 करोड़ रुपये आया वह किसका आया? केंद्र का। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के 3,667 करोड़ रुपये 19 प्रोजेक्ट्स के लिए आये। यह किसके आये? केंद्र से आये। परंतु आप श्रेय ले रहे हैं। ये बातें आप अभिभाषण में लिख रहे हैं, अगर ये न लिखते तो अभिभाषण क्या होता? आप उड़ान योजना का भी जिक्र कर रहे हैं। यह उड़ान योजना किसकी है? चार हेलीपैड बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये सेंटर से आया है। आप यहां पर चर्चा कर रहे हैं, स्वदेश दर्शन योजना की। जिसमें 5 करोड़ 63 लाख रुपये सेंटर से आया। आप चर्चा कर रहे हैं, अमृत योजना की। जिसमें 17 शहरों की जल आपूर्ति के लिए केंद्र ने पैसा दिया। आप चर्चा करें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। जिसमें 15 क्रिटिकल केयर सेंटर केन्द्र ने दिए। भाई जी, केंद्र का धन्यवाद तो कर दो। संघीय ढांचा

यह थोड़ी कहता कि अगर केंद्र आपको दिल खोल कर दे रहा है तो आप गाली दो। आप इसके लिए धन्यवाद तो कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कौन सी योजना है। आपकी सरकार को 3 साल हो गए, आपकी कौन सी योजना है जिसको लेकर आप चुनाव में जाना चाहते हैं?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

19.03.2025/1440/बी.एस./वाई.के.-2

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो सारा राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, यह अभिभाषण केंद्र की योजनाओं पर आधारित है। प्रदेश सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र यहां पर किया हो। इसलिए मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

19.03.2025/1440/बी.एस./वाई.के.-3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री केवल सिंह पठानियाः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मैं चर्चा के लिए खड़ा हूं और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण में खासकर जो नई परंपरा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में शुरू की, क्योंकि जब भी राज्यपाल का अभिभाषण हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में रखा गया है, और यह अभिभाषण किसी व्यक्ति विशेष का अभिभाषण नहीं था, किसी पार्टी का अभिभाषण नहीं था। यह तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख हिमाचलियों की भावना है।

(**श्री आशीष बुटेल** सभापति **पदासीन हुए।**)

उस भावना के प्रति जो बातें यहां रखी गईं, ठीक होता जो बातें इस अभिभाषण के अंदर रखी गईं और पहले भी महामहिम के अभिभाषण पर जो सरकार लेकर आती थीं। आज न केवल यहां परंतु देश के अंदर भी जहां-जहां गैर कांग्रेसी सरकारं हैं, हम महामहिम राज्यपाल का सम्मान करते हैं। परंतु ऐसा जो हुआ है, ठीक होता, माननीय सभापति महोदय इस अभिभाषण को पढ़ते और जहां तक इस अभिभाषण में जो पीछे 70 लाख हिमाचलियों की आर0डी0जी0 पर जो बहुत बड़ा अन्याय हिमाचलियों के साथ हुआ है, जिसमें लगभग 1952 से लेकर 2026 तक यह जो सरकारे चाहे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो। लगातार 70 लाख हिमाचलियों को यह आर0डी0जी0 मिलती रही है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1445/DT/AG-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोगों के लिए यह आर0डी0जी0 मिलती रही है। जहां तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसके उल्लेख की बात है इस सदन में ही नहीं अपितु लोक सभा व राज्य सभा यानी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां प्रदेश सरकार को आवश्यकता के अनुसार आर0डी0जी0 दी गई है। भारत देश की पार्लियामेंट के अंदर आज जो सत्ताधारी पार्टी है एक समय उनके एम0पी0 बहुत कम थे। भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यह भारत रत्न श्री भीम राव अंबेदकर जी द्वारा बनाए गये संविधान के द्वारा चलता है। एक समय था जब विपक्ष में सांसदों की संख्या कम होने पर भी नेता प्रतिपक्ष को रिकॉग्निशन दी जाती थी। भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक समय ऐसा भी आया जब विदेशों को डेलिगेशन भेजे जाते थे तो उस डेलिगेशन को लीड करने के लिए नेता प्रतिपक्ष को चुना जाता था। स्वर्गीय श्री अटल विहारी वाजपेयी जी इसका एक उदाहरण है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 100 करोड़ लोगों की भावना को समझते हुए और संविधान के प्रति जो उनके दिल में सम्मान था उसी के मद्देनजर श्री अटल विहारी वाजपेयी जी को

उस डेलिगेशन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। इसी से तो हमारा संविधान जिंदा रहेगा, तभी तो गुड गर्वनेंस रहेगी, तभी तो सरकारें चलेंगी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में संविधान की रिस्पैक्ट होनी चाहिए और हम तो यह चाहते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर संवैधानिक ढंग से ही चर्चा होनी चाहिए। सरकारे आयेंगी-जायेंगी लेकिन प्रजातंत्र में संवौधानिक प्रणाली से ही कार्य होना चाहिए।

इस सदन में आर0डी0जी0 पर भी बातें हुई हैं और उस पर विस्तार से चर्चा हुई। यह वही विचारधारा है जिसने प्रदेश में आई आपदाओं पर अपना स्टेंड नहीं रखा। यह वही विचाराधारा है जिसने 1 नवम्बर, 1966 को जब हिमाचल प्रदेश में कई अन्य जिले मिलाए गये थे और एक पहाड़ी राज्य बनाने की बात की गई थी तेा उसका विरोध किया गया। उस समय भी जिला कांगड़ा के मुख्यालय में खड़े होकर इस विचाराधारा के लोगों ने कहा था कि "स्टेटहुड मारो ठुड"। जिन अखबारों में यह बात छपी थी आज भी उनकी कटिंग मौजूद है। इस विचारधारा के लोगों ने कहा था कि स्टेटहुड हमें नहीं चाहिए इसलिए इन्होंने नारा दिया कि "स्टेटहुड मारो ठुड"। यह ऐसी विचाराधारा है जो हमेशा से हिमाचल प्रदेश के अधिकारों का विरोध करती आई है।

19.03.2026/1445/DT/AG-2

राज्यपाल के इस अभिभाषण में, जो माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविंद्र सिह सुक्खू जी के नेतृत्व में तीन साल पूर्व जो सरकार बनी थी उसके तीन सालों के कार्यों का उल्लेख किया गया है। मैं जिला कांगड़ा के संबंध में बात करना चाहूंगा। क्योंकि ऐसे भी आंकड़े हमारी विपक्ष के साथियों द्वारा दिए जा रहे थे कि प्रदेश में कुछ नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया जो भी आया है वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। मैं इस सदन में यह बात कहना चाहूंगा कि पहले ही बजट में मुख्य मंत्री जी ने कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी घोषित किया। जहां तक एयरपोर्ट का संबंध है वह एयरपोर्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। प्रदेश में बहुत सी सरकारें आई। देश के सम्मानीय प्रधान मंत्री जी प्रदेश में आए, देश के गृह मंत्री जी प्रदेश में आए और देश के सिविल एविऐशन मंत्री भी प्रदेश में आए। कांगड़ा के एयरपोर्ट की एक्शपेंशन की जाएगी यह बात सिर्फ अखबारों की सुर्खिया बन कर ही रही व्यावहारिक तौर पर इसमें कुछ नहीं किया गया और इस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन में एक

रुपया तक नहीं लगाया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगभग 936 करोड़ 33 लाख रुपया एयरपोर्ट के विस्तार व भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध करवाया। आने वाले समय में यह एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश का इकलौता एयरपोर्ट होगा क्योंकि शीघ्र ही इसके विस्तार का कार्य धरातल पर नजर आयेगा। न केवल यह एयरपोर्ट बल्कि पालमपुर का हैलिपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह 264 करोड़ रुपये का डेयरी मिल्क का एक बहुत बड़ा प्लांट जिला कागड़ा में लगाया गया है यानी जिला कांगड़ा के लिए जो दो बड़े प्रोजैक्टस हैं उनके लिए 936 करोड़ व 264 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है।

मैं सिर्फ जिला कांगड़ा की बात करूंगा। मैं यह भी कंपैरिजन करूंगा कि किस सरकार के समय कांगड़ा से बहुत से कार्यालय अन्य जिलों में गये। मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि कौन सी सरकार कांगड़ा जिले की हितैषी रही और कौन नहीं रही। इसी प्रकार कांगड़ा जिले के बनखंडी में जो 'जू' बनाया जा रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जू वहां पर डवलप किया जा रहा है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2026/1450/ए.जी.-एन.जी./1

श्री केवल सिंह पठानिया..... जारी

और उसका लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पर्यटन की राजधानी के तहत एशिया की सबसे बड़ी ज़िप लाइन नड्डी के अंदर बनने जा रही है। इससे पहले थाईलैंड के अंदर किंग कोंग ज़िप लाइन है, जोकि 3.8 किलोमीटर लंबी है। अभी कैबिनेट ने जो अप्रूव की है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और वह नड्डी ज़िप लाइन है। इस परियोजना पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ-साथ जिला कांगड़ा की करेरी झील, जोकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, उस पर पर्यटन की राजधानी के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेप्सी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट/कारखाना भी इन्दौरा विधान सभा क्षेत्र व जिला

कांगड़ा के अंदर स्थापित किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो बजट घोषणाएं हुई हैं, उनके तहत लगभग 1550 करोड़ रुपये के काम जिला कांगड़ा के अंदर पर्यटन की राजधानी के रूप में किए जा रहे हैं। एक समय वह भी था जब ई0एन0सी0 का ऑफिस, जोकि फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र में था, उसे रातों-रात जिला कांगड़ा से बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार एस0ई0 हिमुडा का कार्यालय, जोकि धर्मशाला में था, को भी रातों-रात स्थानांतरित कर दिया गया। मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों के अंदर लगभग 1500 करोड़ रुपये के कार्य पर्यटन और उद्योग के दृष्टिकोण से जिला कांगड़ा में हुए हैं।

सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत से सुधार किए गए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री और आदरणीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि सैकड़ों ऐसे स्कूल, जहां पर बच्चे नहीं थे, उन्हें बंद किया गया। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार के पांच साल में कई कॉलेज बिना प्रिंसिपल व प्रवक्ताओं के चल रहे थे।

19.03.2026/1450/ए.जी.-एन.जी./2

लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां प्रिंसिपल न हो। इसके लिए सरकार व विभाग ने तीन-तीन डीपीसी की, जिससे प्रदेश के कॉलेजों और स्कूलों में भी प्रधानाचार्य लगाए गए। इसके अलावा शिक्षा विभाग में हजारों पदों को भी भरा गया है। इसके साथ-साथ 156 सी0बी0एस0ई0 स्कूल भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत खोले जा रहे हैं ताकि हर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे स्कूल उपलब्ध हों। जब माननीय शिक्षा मंत्री, श्री रोहित ठाकुर जी ने कार्यभार संभाला था, उस समय हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के 28 राज्यों में से 21वें स्थान पर था। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि आज हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 5वें स्थान पर पहुंच गया है।

सभापति महोदय, इसके अलावा प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राजस्व विभाग में भी बहुत काम हुआ है। पहले लोग पटवारियों को ढूंढते थे लेकिन अब राजस्व अदालतों की शुरुआत की गई है। जहां तक म्यूटेशन की बात है तो कुल 4,82,168 म्यूटेशन किए गए हैं। यह असली व्यवस्था परिवर्तन है। इसके साथ-साथ पार्टिशन के 3911, डिमार्केशन के 53,636 और करेक्शन के 15,461 मामले निपटाए गए हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में कुल मिलाकर 5,82,176 मामलों का निपटारा राजस्व विभाग ने रेवेन्यू अदालतों के अंतर्गत किया है। इसके अलावा 645 पटवारियों के पद माननीय मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री ने सृजित किए हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। आज रोबोटिक सर्जरी और एम0आर0आई0 जैसी सुविधाओं की बात हो रही है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय ने बेहतरीन कामकाज किया है। मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री सुख-आश्रय योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का मूलमंत्र यही है कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है और मुख्य मंत्री जी ने इस योजना पर 30 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

19.03.2026/1450/ए.जी.-एन.जी./3

इसके अलावा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 22.5 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति और शिक्षा के लिए दिए हैं।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1455/ए.पी. /ए.एस. -1

श्री केवल सिंह पठानिया .....

अध्यक्ष महोदय, महामहीम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना का उल्लेख किया है। जिसकी आज बात हो रही थी। लेकिन आपको किसानों की बात बुरी लगती है और उनके साथ मज़ाक होता है। क्योंकि जो व्यक्ति खेत में नहीं जाता, वह किसानों की दशा क्या समझेगा। इसके अलावा हल्दी, गेहूं और मक्की की बात हुई। मैं कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मक्की 40 रुपये प्रति किलो, गेहूं 60 रुपये प्रति किलो, हल्दी 90 रुपये प्रति किलो और गाय व भैंस के दूध का समर्थन मूल्य क्रमशः 51 और 60 रुपये हमारी सरकार ने दिया है। यहीं नहीं जो सरकार अपने आप को गौ-रक्षक कहती है, उन्होंने भी गाय के दूध पर समर्थन मूल्य नहीं दिया। सभापति महोदय, पहले पतलीकूहल और बरोट को ट्राउट मछली पालन का हब कहा जाता था। लेकिन अब 3 करोड़ 84 लाख रुपये से जिला कांगड़ा के धारकंडी और द्रणी में ट्राउट मछली पालन का नया हब तैयार किया जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, प्रदेश में नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया है।

Chairman : Hon'ble Member Shri Kewal Singh Pathania ji, please wind-up.

श्री केवल सिंह पठानिया : जो बातें आप पुल के बारे में कर रहे हैं, मैं उनका भी उल्लेख करना चाहता हूं। जब मैं पहली बार विधायक बना था, उस समय हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो सात बार विधायक रहे हैं और प्रदेश का नेतृत्व भी कर चुके हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आए थे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हें वह पुल याद रहा जो पिछली बार आपदा के कारण बह गया था। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि जब मैंने उस समय पुल बह जाने की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सही था और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी मेरी बात को सही माना। आज भी उन्होंने इस सदन में उसका ज़िक्र किया। मैंने केवल पुल के लिए वीडियो कॉलिंग ही नहीं की थी, बल्कि उस पुल को अपने क्षेत्र के लोगों को समर्पित भी किया है। आज भी आपको उसकी चिंता है, इसके लिए मैं आपके इस कंसर्न का धन्यवाद करता हूं। मैं कहना

चाहता हूँ कि चलो पुल के बहाने ही सही, आपको मेरी याद तो है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

Speaker : Shri Kewal Singh Pathania ji, please wind-up now.

श्री केवल सिंह पठानिया : सभापति महोदय, मैं नशे के विषय पर कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिट्टे के खिलाफ प्रदेश में एंटी-चिट्टा अभियान चलाया है। जगह-जगह एंटी-चिट्टा रैलियां भी आयोजित की गई। इस अभियान के तहत 1224 लोगों की पहचान की गई और जो लोग प्रदेश में चिट्टे का व्यापार करते थे उनकी 3 वर्षों में लगभग 24 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री और पुलिस विभाग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नशे के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया। यही नहीं, जो 17 पुलिस कर्मी इसमें संलिप्त थे उन्हें भी निलंबित किया गया। इसके अलावा, मनरेगा की बात करें तो मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने मनरेगा का गला घोंटा है। पहले प्रदेश और केंद्र सरकार का अनुपात 90:10 था, जो अब घटकर 60:40 हो गया है। हिमाचल पूरे देश का पहला राज्य है जिसने मनरेगा के तहत दिहाड़ी को 320 रुपये किया है। यह सारी बातें माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में लिखी गई हैं। उन्होंने गारंटियों और ओ0पी0एस0 की भी चर्चा की है। हमारी सरकार ने अब तक 10 में से 7 गारंटियों को पूरा कर दिया है। विपक्ष ने कहा कि माननीय आयुष मंत्री ने मंत्री रहते हुए विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जब चंबा में मामला हुआ था, तब भी ऐसा हुआ था और उस समय भी वे संवैधानिक पद पर थे। इसलिए पहले यह देखना चाहिए कि ऐसा पहले भी हुआ है। जहां तक रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है, इसके लिए एक समिति बनाई गई है। मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि चाहे मुख्य मंत्री हो, मंत्री हों या फिर ब्यूरोक्रेसी, सभी को अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कारकेड के रूट में भी कटौती करनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा अधिकारी दौरे पर जाता है तो 6-7 या 10 गाड़ियां साथ जाती हैं, चाहे वे चीफ इंजीनियर हों, डी0सी0 हों या ए0डी0सी0 हों। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि आने वाले समय में

श्री ए0टी0 द्वारा जारी....

19.03.2026/1500/AT/AS/01

श्री केवल सिंह पठानिया जारी ...

जिस तरीके से आर्थिक संकट प्रदेश पर आया है ठीक ही कहा गया है। हमने तो पहली आपदा में भी कहा, दुसरी आपदा में भी कहा, बड़े भाई साहब नेता प्रतिपक्ष से भी कहा कि सरकारें आती-जाती रहेंगी लेकिन एक बार जो आर0डी0जी0 बंद हुई है वह हमारे साथ 70 लाख हिमाचलियों के साथ अन्याय हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर यहां खड़ा हुआ था और मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया आपका धन्यवाद।

सभापति : माननीय अध्यक्ष जी ने हर एक वक्ता को 10 मिनट का समय दिया है तो कृपया सभी वक्ता समय का ध्यान रखें। अब इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं श्री राकेश जम्वाल जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री राकेश जम्वालः सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चल रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का आईना होता है लेकिन 16 फरवरी को जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने यहां पढ़ा उसे उन्होंने लगभग 2 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया। जिस प्रकार से सरकार पर उस अभिभाषण पर टिप्पणियां की हैं उन पर भी सरकार को मंथन करना होगा।

पैरा नंबर 3 से लेकर 16 तक का जो जिक्र राज्यपाल महोदय ने किया उसमें उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के बारे में टिप्पणी की है जिसे मैं पढ़ना उचित नहीं समझता। सरकार को इस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए।

लगातार अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से, चाहे उप-मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री हों या विधायक, सभी एक ही बात पर फोकस कर रहे

हैं भारतीय जनता पार्टी और आर0डी0जी0। आर0डी0जी0 बंद हुई इसके लिए दोषी कौन है जिम्मेदार कौन है आप लगातार भारतीय जनता पार्टी और जय राम ठाकुर जी पर टिप्पणी की जा रही है।

19.03.2026/1500/AT/AS/02

जय राम ठाकुर जी दिल्ली जाते हैं इस पर भी सत्ता पक्ष परेशान है। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं और हिमाचल के हितों के लिए लगातार दिल्ली जाते हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्य मंत्री जी द्वारा यह कहना कि आप चलो हम आपके नेतृत्व में दिल्ली चलना चाहते हैं जब जय राम जी दिल्ली गए वित्त मंत्री से मिलकर आए तो कहा गया कि हमें नहीं बताया हमें भी साथ ले चलते। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस सदन के नेता हैं और आप अपने दायित्व से नहीं भाग सकते। सरकार आपकी है। आज अगर यह रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। आप वित्त आयोग के समक्ष अपना पक्ष ठीक प्रकार से नहीं रख पाए। लेकिन अभिभाषण को लेकर भी वित्त आयोग और केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणियां की गई हैं। यह हिमाचल के इतिहास की एक ऐसी सरकार है जो संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को नहीं मानती,राष्ट्रपति को नहीं मानती, प्रधानमंत्री को नहीं मानती, राज्यपाल महोदय को नहीं मानती, चुनाव आयोग को नहीं मानती और हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी नहीं मानती। बहुत दुख से मुझे इस सदन में यह कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल महोदय का यहां से स्थानांतरण हुआ। उनके विदाई समारोह में मुख्य मंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गए, लेकिन उनके जाने के पश्चात सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा उनके खिलाफ एक पत्रकार वार्ता की गई। लगातार हमारे मंत्री महोदय अनेक बातों का जिक्र करते हैं जिसमें वह कभी नियमों का हवाला देते हैं और कभी कानून का हवाला देते हैं

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1505/केएस/डीसी/1

श्री राकेश जम्वाल जारी ---

और गवर्नर महोदय पर टिप्पणी करने के साथ-साथ उन्होंने पत्रकार वार्ता में तो देश के प्रधान मंत्री, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में उप-प्रधान मंत्री रहे अडवानी जी के ऊपर भी टिप्पणी की। अडवानी जी को जब भारत रत्न दिया जा रहा था, उनकी उम्र 90 वर्ष से ऊपर थी और अगर उन्होंने वह अवार्ड बैठकर लिया तो कहा गया कि देखिए अडवानी जी तो बैठे ही हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी भी बैठे हैं। मंत्री जी को शायद प्रोटोकोल का ध्यान नहीं कि उस समारोह में किस प्रकार से पुरस्कार दिया जाता है। जब राष्ट्रपति महोदय पुरस्कार देते हैं तो लेने वाला और राष्ट्रपति ही वहां पर खड़े होते हैं बाकी सारे बैठे रहते हैं। लेकिन आप किसी को नहीं मानते। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय जो प्रदेश के मुखिया होते हैं, मुख्य मंत्री व मंत्रियों को शपथ दिलाने वाले, उनको भी नसीहत दी जाती है और उनको भी बहुत सी चीजों का पाठ पढ़ाने का काम हिमाचल सरकार के मंत्री कर रहे हैं। जैसे सारी बातों का ज्ञान केवल इन्हीं को है बाकी किसी को नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर बार-बार संघीय ढांचे का ज़िक्र आता है। बार-बार ये अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश मात्र आपका ही नहीं है। जितना यह प्रदेश आपका है, उतना ही हमारा भी है। हम अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से समझते हैं और हमारे नेता भी समझते हैं। जहां तक इस अभिभाषण का सम्बन्ध है, प्रदेश सरकार ने तीन वर्ष क्या किया, साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है, उसका ज़िक्र इसमें नहीं है। वहां से हमारे सत्ता पक्ष के लोग जब बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जय राम जी का ज़िक्र लगातार आ रहा है। मैं अभिभाषण पढ़ रहा था उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को ले कर सरकार ने कहा है कि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में गुणवत्ता एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत आपने उन संस्थानों में किया क्या, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं? योजना तो आपने चला दी, आपने उन संस्थानों को भी ले लिया लेकिन उनमें किया क्या? मेरे सुन्दरनगर चुनाव क्षेत्र का सिविल हॉस्पिटल आपने उसमें लिया है। पूर्व जय राम जी

की सरकार के समय उसका दर्जा बढ़ाया गया था और वहां पर भवन बनाए गए। केंद्र से नड्डा जी ने हमको मातृ-शिशु अस्पताल दिया। लेकिन आपने वहां पर क्या किया? जो भवनों

19.03.2026/1505/केएस/डीसी/2

का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जय राम जी की सरकार के समय शुरू हुआ था वह वहीं का वहीं आपने रोक रखा है। आप यहां पर स्वास्थ्य संस्थानों का ज़िक्र कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। पूर्व की जय राम जी की सरकार ने मेरे दुर्गम क्षेत्र में एक प्राइमरी हैल्थ सैंटर खोला था। उसके 45 किलोमीटर तक कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था लेकिन उसको भी डीनोटिफाई कर दिया गया। मैंने अनेकों बार वह मुद्दा उठाया। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम विचार करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है, दूर-दराज का क्षेत्र है तो हम उसको ज़रूर नोटिफाई करेंगे लेकिन आज तक वह संस्थान नहीं खुल पाया। आप स्वास्थ्य संस्थानों की बात कर रहे हैं। हिमकेयर का हाल हिमाचल प्रदेश में क्या है? जो पूर्व की जय राम जी की सरकार ने हिमकेयर और सहारा योजना चलाई थी, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है, हिमाचल का लगभग साढ़े 600 करोड़ रुपये की देनदारियां इन सारी योजनाओं में है। आप स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी मण्डी में गए और वहां पर रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन कर दिया। आज मेरा स्वास्थ्य विभाग से भी एक प्रश्न लगा था उसमें भी मैंने पूछना था। हमारे नेरचौक में आपने रोबोटिक सर्जरी का विधिवत उद्घाटन कर दिया लेकिन वहां पर रेडियोलॉजी डिपार्टमैंट बंद पड़ा है। कैथ लैब का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वह आज तक नहीं खुल पाई। आपने एम0आर0आई0 का ज़िक्र किया, आप जिस दिन से सत्ता में बैठे हैं, आपने कहा कि जय राम ने एम0आर0आई0 तक नहीं खोली। साढ़े तीन वर्ष का समय इस सरकार को होने का आ गया, आज भी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी एम0आर0आई0 लगा दी जाएगी। साढ़े तीन वर्ष तो निकल गए। आपने मैडिकल कॉलेज नेरचौक से एक मुश्त 40 से ज्यादा डॉक्टर स्थानांतरित कर दिए

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

19.03.2026/1510/av/dc/1

श्री राकेश जम्वाल------जारी

लेकिन आपने कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज, डी0एम0ई0 और डी0एच0एस0 का अलग-अलग कैडर बना दिया है। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर्ज के स्थानांतरण के बाद आपने वहां पर कितने डॉक्टर्ज की नियुक्तियां की हैं? आपने उस मेडिकल कॉलेज का हाल खराब कर दिया। सत्ता पक्ष के हमारे साथी बार-बार रोबोटिक सर्जरी का जिक्र करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां पर लोगों के अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे और रेडियोलॉजी डिपार्टमैंट बंद पड़ा है। प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, यहां पर उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। यहां पर जिक्र किया गया कि पूर्व की जय राम ठाकुर जी की नेतृत्व वाली सरकार के समय हिमाचल प्रदेश में 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के भवन बना दिए गए। पूर्व में श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में विकास के कार्य करवाने हेतु कृतसंकल्प थी। उस समय हमारी सरकार ने लगातार प्रयास करते हुए प्रत्येक विधान सभ क्षेत्र में स्कूल, होस्पिटल यानी जहां-जहां संस्थानों की जरूरत थी वहां पर भवन बनाने का काम किया गया। परंतु वहां से मुख्य मंत्री जी बार-बार जिक्र करते हैं कि ऐसे-ऐसे भवन बना दिए गए। मैं इस संदर्भ में अपने विधान सभा क्षेत्र सुन्दरनगर का जिक्र करना चाहता हूं। वहां पर सिविल होस्पिटल के स्टाफ हेतु रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन बनाई जा रही थी। उसका 70 प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका था परंतु वह काम बंद कर दिया गया। क्या यह लोगों की जरूरत नहीं थी, क्या यह भवन बनाना जरूरी नहीं था? डैहर में गवर्नमैंट आई0टी0आई0 का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के पश्चात आपने सत्ता में आने के बाद उसका काम भी रोक दिया। क्या यह भवन जरूरी नहीं था? आपने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तलैली और पौड़ा कोठी के भवनों के निर्माण कार्य रोक दिए, क्या ये भवन जरूरी नहीं थे? क्या ये स्कूल के भवन बनने नहीं चाहिए थे? निहरी मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक दुर्गम स्थान है जहां पर सी0एच0सी0 के भवन का निर्माण किया जा रहा था। परंतु आपने उस निर्माण कार्य को रोक दिया, क्या वह भवन

जरूरी नहीं था? आपने फार्मर ट्रेनिंग सेंटर के भवन का निर्माण कार्य रुकवा दिया, क्या यह गलत काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया?

यहां पर हमारे साथी कह रहे थे कि हमने नशे की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर बड़ी-बड़ी रैलियां कीं परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि रैलियां करने से यह नशा नहीं

19.03.2026/1510/av/dc/2

रुकेगा। इसके लिए सरकार को गम्भीर कदम उठाने पड़ेंगे। हमने कहा कि सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र में एक इन्डोर स्टेडियम बनना चाहिए। उस इन्डोर स्टेडियम का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उसका 10 प्रतिशत कार्य इसलिए रुका है क्योंकि वर्तमान सरकार उसके लिए पैसा नहीं दे रही। क्या जय राम ठाकुर जी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह इन्डोर स्टेडियम गलत बनाया था? सुन्दरनगर में जवाहर लाल नेहरु इंजीनियरिंग कॉलेज की रेजिडेंशियल अकॉमोडेशन का काम चला हुआ था परंतु उस काम को भी रोक दिया गया। क्या वह भवन गलत बनाया जा रहा था? आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए लगातार पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते आ रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने जिन गारंटीज का जिक्र किया था, उनका क्या हुआ? कागजों में तो कहा जा रहा है कि हमने सात गारंटीज पूरी कर दीं परंतु आने वाले समय में प्रदेश की जनता आपसे इस बारे में हिसाब लेगी। आपने जिस प्रकार से छल करके व जनता को ठग करके सत्ता हासिल की है, आने वाले समय में आप जनता के पास जाने के काबिल नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

सभापति महोदय, इस अभिभाषण के संदर्भ में माननीय श्री रणधीर शर्मा ने सही कहा क्योंकि इस अभिभाषण में केवलमात्र केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र है। केंद्र से जो योजनाएं आई हैं अगर उन योजनाओं को इससे निकाल दिया जाए तो इसमें प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। अच्छा होता कि इस अभिभाषण में आप केंद्र सरकार का भी दो शब्दों में धन्यवाद कर देते कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश को ये योजनाएं मिल रही हैं।

यहां पर माननीय लोक निर्माण मंत्री बैठे हैं, ये लगातार सच्चाई का जिक्र करते हैं। ये धन्यवाद करते हैं कि केंद्र से प्रधानमंत्री जी और आदरणीय नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश की सड़कों के लिए लगातार पैसे दे रहे हैं। अगर इस प्रकार से मुख्य मंत्री जी सहित इनके बाकी मंत्री भी धन्यवाद करते तो अच्छा होता। लेकिन सभापति महोदय, इस अभिभाषण में मात्र केंद्र सरकार और वित्तायोग को कोसने के अलावा कुछ नहीं लिखा गया है। इस अभिभाषण में केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र है। मैं सत्ता पक्ष के साथियों को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय को

19.03.2026/1510/av/dc/3

यह अभिभाषण पढ़ना चाहिए था। इस प्रकार से ये लोग राज्यपाल महोदय को भी डिक्टेट करना चाहते हैं परंतु इस अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है जिसका मैं समर्थन कर सकूं। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1515/**टी0सी0वी0/एच0के0-1**

श्री राकेश जम्वाल ... जारी

सभापति महोदय, मिर्ज़ा गालिब की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करुंगा जो इस प्रकार से है :-

उम्र भर मैं यह भूल करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा।

ये लाइन मेरी ओर से मुख्य मंत्री जी के लिए है, धन्यवाद।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : सभापति महोदय, जो अभिभाषण दिनांक 16 फरवरी, 2026 को महामहिम राज्यपाल द्वारा इस माननीय सदन में पढ़ा गया जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने मूव किया और माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने उसका अनुसमर्थन किया। मैं भी इस चर्चा में भाग लेने और उस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, वैसे तो इस अभिभाषण पर पक्ष व विपक्ष की ओर से बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस दस्तावेज में कुछ भी नहीं है, इसलिए वे इसका समर्थन नहीं कर सकते। यदि मान लिया जाए कि आपकी बात सही है, यह भी कहा गया कि इस अभिभाषण के बिंदु 3 से 16 तक माननीय राज्यपाल ने पढ़ने से इनकार किया।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में लगभग 130 बिंदु शामिल हैं। राज्यपाल महोदय ने 3 से 16 तक के बिंदुओं को किन कारणों से नहीं पढ़ा या इसके पीछे क्या कारण रहे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं । यहां पर यह भी कहा गया है कि इस दस्तावेज में सारी स्कीमें केन्द्र की हैं। यदि केन्द्र सरकार ने कोई नई स्कीम्ज दी हैं तो उसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह हमारा हक

है। जितनी भी केन्द्र में सरकारें बनी हैं, हम सभी सरकारों का धन्यवाद करते हैं। 1500 करोड़ रुपये की जो घोषणा की गई थी उसको तो आप ला नहीं पाए और न ही आर0डी0जी0 बंद करने के बारे में बात करते हैं।

इसके बाद यदि इस अभिभाषण में पैरा संख्या : 17 से आगे देखें तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मेरी सरकार ने आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रभावी उपाय किए हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के रेवेन्यू में पिछले 3 वर्षों के दौरान लगभग

3300 करोड़ रुपये तथा गैर-राजस्व मदों में लगभग 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। क्या आप इसको भी अस्वीकार करते हैं, क्या यह भी झूठ है। यदि यह सब कुछ झूठ है तो फिर सत्य क्या है? क्या केवल वही बातें सत्य हैं जो आप कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि विपक्ष का भाषण तो साइकोस्टाल है। इन्होंने सोच रखा है कि हमने तो अपोज ही करना है। इनके द्वारा यहां सदन में बतीस दांतों और घसे लगाने की बातें की जाती है। क्या जनता ने हमें इसलिए यहां पर भेज रखा है। हम यहां जनता की सेवा के लिए आए हैं, न कि केवल विरोध करने के लिए भेजे गए हैं। इस माननीय सदन में जिस तरह की बातें की जाती है, उससे इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है?

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1520/NS-HK/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा ------जारी

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कुछ माननीय सदस्यों को सुन रहा था और यह भी हो सकता है कि मैंने भी विषय से हटकर कुछ बोला हो। अब आपने बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं विषय से हट कर बोल रहा हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य अभिभाषण पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि आप तो केवल कोसने का काम कर रहे हैं कि किसी मंत्री ने यह कहा और दूसरे मंत्री ने यह कहा। जब मैं यहां पर आर0डी0जी0 की चर्चा पर बोल रहा था मैंने तब भी कहा था कि अगर हम ऐसे ही एक-दूसरे को कोसते रहेंगे तब देश प्रगति नहीं करेगा। अगर मैं पिछली सरकार की बात करूं और अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहूं तो पिछली सरकार के कार्यकाल के समय वहां पर एक भी फाउंडेशन स्टोन नहीं लगाया गया। वहां पर एक फाउंडेशन स्टोन लगाया और वह सब-तहसील, जांगला का था। अभी हमारी सरकार आई तो मैंने विभागीय अधिकारियों से संवीक्षा ली कि हमने सब-तहसील, जांगला की बिल्डिंग का काम शुरू करना है और इसके लिए टेंडर प्रोसैस शुरू की जाए। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर की प्रोसैस की और मैंने फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए तिथि निर्धारित की तो पता चला कि श्री जय राम

ठाकुर जी ने बिना बजट प्रावधान के फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। उन्होंने यह फाउंडेशन स्टोन पता नहीं शिमला से लगाया कि रोहडू से लगाया। क्या पता इन्होंने ऑनलाइन किया या जब रोहडू में इनका दौरा हुआ था तब किया था? मैं इसकी गहराई में नहीं जाना जाता हूं। इन्होंने यह एक फाउंडेशन स्टोन लगाया था और बिना बजट के लगाया था। इसके लिए बजट अब हमारी सरकार के समय में मिला।

सभापति महोदय, यहां पर उद्घाटन की बात कही गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में श्री जय राम ठाकुर जी के तीन दौरे हुए। इनका एक दौरा डोडरा-क्वार का हुआ और इन्होंने वहां पर कुछ नहीं दिया। इनके दो दौरे रोहडू के हुए और वहां पर इन्होंने उद्घाटन जरूर किए। मेरे क्षेत्र में एक सीमा कॉलेज है और ये कॉलेज श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम से जाना जाता है। जब श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उनके आशीर्वाद से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमें मिला था और मैं पहली बार विधायक बना तो उस समय उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। यह बात ठीक है कि यह हमारी सरकार के समय में तैयार नहीं हुआ और आपकी सरकार के समय में तैयार हुआ। आपने

19-3-2026/1520/NS-HK/2

उसका उद्घाटन किया। उसमें मेरा नाम तो क्यों लिखना था पर आपने उसमें औरों के नाम और यहां तक कि सांसद का भी नाम लिख दिया। मेरे क्षेत्र में एक समोली पुल था जिसको हमने बनाया और उद्घाटन आपने किया। आपने उसमें भी उनका नाम लिख दिया। हमने सिविल हॉस्पिटल, रोहडू की बिल्डिंग बनाई और यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इसके लिए मैं पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करता हूं और उनके आशीर्वाद से यह भवन बना लेकिन वहां उद्घाटन के लिए श्री जय राम ठाकुर जी चले गए। उस समय मैं शिमला में था और मैंने उस दिन ही रोहडू जाना था जिस दिन इन्होंने उद्घाटन किया। मैं इनके सभी नेताओं के लाइव भाषण सुनता रहा। वहां पर स्थानीय नेता ने भाषण दिया, फिर श्री सुरेश भारद्वाज जी ने भाषण दिया और फिर श्री जय राम ठाकुर जी ने भाषण दिया। इसके लिए पूर्व सरकार ने सिर्फ 5 करोड़ रुपये दिए बाकी पैसा तो हमने दिया। मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी सरकार ने उसके लिए आचार संहिता से पहले पैसा डिपोजिट कर दिया था। मैं जब खड़ापत्थर पहुंचा तो इनके भाषण समाप्त हो गए थे। मैंने रोहडू में लोक निर्माण विभाग का एक्सिअन बुलाया और उससे पूछा कि बताओ इसके

लिए कहां-कहां से पैसा आया है? वे भी इनकी भाषा बोलने लगे कि आपकी सरकार के समय में सिर्फ 5 करोड़ रुपये आए और बाकी पैसा तो हमने दिए। मैं बहुत परेशान हुआ और फिर मैंने अपने सूत्रों से पता किया। आपने उसके लिए थोड़े से पैसे बांटे हैं बाकी तो हमने दिए। आप हर बार झूठ न बोलें। आज श्री सुरेश भारद्वाज जी इस सदन में नहीं हैं और उनका बमनोली गांव है तथा वहां पर पानी की एक लिफ्ट स्कीम थी जिसका फाउंडेशन स्टोन मैंन माननीय वीरभद्र सिंह जी से रखवाया था, यह हमारी सरकार के समय में तैयार नहीं हुई थी। बाद में श्री सुरेश भारद्वाज जी ने उसका उद्घाटन किया और वहां बोल गए कि यहां का विधायक झूठ बोलता है। यह स्कीम जे0जे0एम0 के तहत बनी है। सभापति महोदय, वर्ष 2016 में जे0जे0एम0 आया भी नहीं था। हिमाचल में जे0जे0एम0 वर्ष 2016-17 में जे0जे0एम0 लागू ही नहीं हुआ था। हम झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं। उप-मुख्य मंत्री महोदय ने ठीक कहा कि आप झूठ बोल कर सत्ता में नहीं आएंगे तो इन्होंने ठीक कहा है। आप इस स्वपन में मत रहें। इसलिए काम करो और सच बोलो। जो काम किया है उसके बारे में सच बोलें। इतना भी क्या बोलना कि कुछ नहीं हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी व इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। यहां पर शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो सब कुछ आपके सामने है। हम

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

19.03.2026/1525/RKS/YK-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी....

शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर थे लेकिन आज हम इस क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आ गए हैं और इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। अगर मैं रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वहां पर कोई भी प्रमुख विकास कार्य नहीं हुए हैं। यह अलग बात है कि वहां थोड़े-बहुत रूटीन के कार्य हुए हैं। मैं वहां की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रदेश की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं। सारी बातें आपके समक्ष हैं इसलिए इन बातों का जिक्र करना जरूरी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वह सब कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। आज हमारे मुख्य मंत्री और इनकी पूरी टीम भी अच्छा कार्य कर रही

है। रोहडू में जो 25 करोड़ रुपये की लागत से 50 बैड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनने जा रहा है उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आज हमारा रोहडू-चिड़गांव-धमवाड़ी-डोडरा-क्वार रोड 20 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहा है। जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उनके आशीर्वाद से मैंने 8-10 सीनियर सेकेण्डरी स्कूल्ज के लिए पैसे स्वीकृत करवाए थे। कई भवनों का कार्य शुरू हो गया था और कुछ का शिलान्यास हो गया था। लेकिन जैसे ही श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार सत्ता में आई हमारे ये सब कार्य बंद हो गए। उस समय डोडरा-क्वार की विभिन्न योजनाओं के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वह पैसा भी खर्च नहीं हो पाया। अब हमारे लोक निर्माण मंत्री प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेस-1 में पैसा लाने की जदोजहद कर रहे हैं। आपसे तो स्वीकृत राशि भी खर्च नहीं हो पाई थी। हमें एक-दूसरे को कोसने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर मैं होर्टिकल्चर की बात करूं तो इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा। सेब का समर्थन मूल्य, यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था और आपके समय की जो देनदारियां थी उन्हें हमारी सरकार ने पूरा किया है लेकिन आप कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। आप हमें इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने नहीं देंगे और न ही आप इसे खुद पढ़ेंगे। श्री रणीधीर शर्मा और आपके अन्य सदस्यों ने केंद्र की एकाध स्कीम को पढ़ लिया और उसके बारे में यहां जिक्र करने लग गए। केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता है वह हमारा हक है। यह पैसा कोई पहली बार नहीं मिल रहा है।

19.03.2026/1525/RKS/YK-2

अगर हमें केंद्र से विशेष पैकेज मिले या 1500 करोड़ रुपये और आर0डी0जी0 का पैसा दिया जाए तो हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर केंद्र से 15-15 लाख रुपये भी मिल जाते हैं तो भी हम उनका धन्यवाद करेंगे। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने पिछली बार कहा था कि जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो महिलाएं मुझसे 1500 रुपये देने के बारे में पूछती है परंतु मैं उन्हें कहता हूं कि मैं 1500 रुपये देने वाला नहीं हूं। मैंने उन्हें कहा कि आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि आप तो 15 लाख रुपये देने वाले हैं इसलिए आप झूठ बोलना

छोड़ दीजिए। आप प्रदेश हित में आर0डी0जी0 को बहाल करवाइए और जो माननीय प्रधान मंत्री ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है उसे भी दिलवाइए। हमें प्रदेश हित में इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। राजनीति करने के तो और भी कई अखाड़े हैं इसलिए हमें प्रदेश हित में काम करना चाहिए। हमें एक-दूसरे पर छिंटाकशी नहीं करनी चाहिए। आप इतना भी झूठ मत बोलिए कि इस दस्तावेज में कुछ भी नहीं है। इस दस्तावेज में 130 पैराज हैं। हो सकता है 8-10 पैराज में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया हो परंतु यह पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी होता था। आप लोगों ने मनरेगा और कई अन्य योजनाओं का खत्म कर दिया है। आप सभी योजनाओं को खत्म करने में तुले हुए हैं। आर0डी0जी0 के ऊपर पहले चर्चा हो गई है इसलिए मैं इस मद पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1530/बी.एस./वाई.के.-1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी...

जो मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलना था, बोल दिया है। अभी बजट पेश होना है तो जो कुछ भी मेरे चुनाव क्षेत्र की दूसरी गतिविधियां होंगी और विकास की बातें होंगी उन्हें मैं बजट भाषण में उजागर करूंगा। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं इस अभिभाषण का भरपूर समर्थन करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद।

19.03.2025/1530/बी.एस./वाई.के.-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्माः सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो 16 फरवरी को इस माननीय सदन में हुआ था और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में तो पहली बार हुआ होगा कि 2 मिनट 11 सेकंड में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण समाप्त किया और साथ-ही-साथ जो अभिभाषण प्रदेश सरकार ने

बनाया था उस पर उन्होंने काफी टिप्पणियां की हैं कि जो केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रदेश में कार्य हो रहे हैं उनके बारे में अभिभाषण में कोई जिग्र नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने इसे पढ़ना ही ठीक नहीं समझा।

सभापति महोदय, इस माननीय सदन में पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी बातें रख रहा है परंतु दुःख इस बात का है कि जिस प्रदेश में एक भी कार्य प्रदेश सरकार के बजट से नहीं हो रहा है। आज सैंट्रल स्पॉन्सर्ड 196 स्कीमें हैं। इन 196 स्कीमों में हिमाचल प्रदेश को 90/10 से बजट आता है। केंद्र का जो टोटल बजट है वह 53 लाख करोड़ के करीब है उसका 40 प्रतिशत देश के 28 स्टेटों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को जाता है और उसमें 196 योजनाएं हैं। इन 196 योजनाओं में हिमाचल प्रदेश को भी सभी योजनाओं से पैसे आते हैं और 90/10 से आते हैं। दुःख इस बात का है कि इसमें एक भी योजना का नाम नहीं लिया है। अपना तो इनके पास कुछ नहीं था, इसलिए कुछ नहीं लिख सके। परंतु केंद्र की योजनाओं का लिख सकते थे, परंतु उसकी कोई टिप्पणी नहीं की है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आर0डी0एस0एस0 विद्युत विभाग में एक योजना चली है, हमारी गवर्नमेंट ने वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार को इसकी डी0पी0आर0 भेजी थी। उसमें 4,100 करोड़ रुपये के करीब सैंक्शन हुआ है और उसी योजना से हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफार्मर तारें, खंभे और स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं। परंतु इस अभिभाषण में कहीं भी इस योजना का नाम नहीं है। आज अगर विद्युत विभाग द्वारा गांव में काम हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार की योजना से हो रहे हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रदेश के लिए पैसे दे रहे हैं,

19.03.2025/1530/बी.एस./वाई.के.-3

उन्हीं योजनाओं से विद्युत विभाग में काम हो रहा है। प्रदेश के पास अपना कोई भी बजट नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले कहा था कि हम आदर्श संस्थान योजना खोलेंगे। मैं अपने चौपाल की बात कह रहा हूं। आज भी मेरे चौपाल में सिविल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन है, परंतु साढ़े तीन साल से कोई भी डॉक्टर

नहीं भेजा। यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है और मेरे नेरवा और चौपाल हॉस्पिटल में 14-14 डॉक्टर की वैकेंसी थी। आज तीन-तीन डॉक्टर हैं। दिसंबर, 2022 में जब हमारी सरकार थी तो वहां पर 12-12 डॉक्टर थे। परंतु आज सारे डॉक्टर मेरे चुनाव क्षेत्र से शिफ्ट करके जहां कांग्रेस के विधायक हैं, वहां शिफ्ट किए गए हैं।

मैं एकमात्र विपक्ष का विधायक हूं। मैं, सभापति महोदय, कह नहीं सकता कि कितना अत्याचार यह सरकार मेरे साथ कर रही है। सारा स्टाफ वहां से भेज रही है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जे0ई0 नहीं है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1535/DT/AG-1

श्री बलवीर सिंह वर्मा जारी..

जबकि वहां जे0ई0 के 11 पद सृजित हैं लेकिन उसमें से केवल 2 जे0ई0 ही वहां पर कार्यरत है। लोक निर्माण विभाग में जे0ई0 के 16 पद हैं और केवल तीन पद ही भरे हुए हैं। वहां लोक निर्माण विभाग के एस0डी0ओ0 तैनात नहीं हैं। जल शक्ति विभाग में जे0ई0 के 13 पद हैं और केवल 2 पद ही भरे हुए हैं। वहां का सारा स्टॉफ कही और ही सिफ्ट कर दिया गया है। इतना अन्याय तो मुगलों ने भारत के साथ नहीं किया होगा जितना अन्याय कांग्रेस ने चौपाल विधान सभा क्षेत्र के साथ किया है। आने वाले समय में चौपाल की जनता इसका जवाब आपको जरूर देगी।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा नैशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत पैसा प्रदेश सरकार को भेजा जा रहा है लेकिन उस पैसे का कहीं भी जिक्र प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया गया। हास्पिटल्स की बिल्डिंग्ज उन पैसों से बनाई जा रही है और उस पर प्रदेश सरकार द्वारा अपना फट्टा लगाया जा रहा है। लेकिन ये लोग केंद्र सरकार का धन्यवाद तक नहीं कर रहे। 700 करोड़ रुपये के करीब की धनराशि राज्य सरकार को नैशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत मिली है। केंद्र सरकार की योजनाओं का कोई भी जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है।

इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी बैठे हैं। ये हर जगह यह बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने 155 स्कूल्ज के लगभग सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध किए हैं, जिनमें से 4 चौपाल विधान सभा क्षेत्र के भी हैं। जो 155 स्कूल्ज सी0बी0एस0ई0 से संबद्ध किए वे केंद्र सरकार की योजना के तहत किया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहले से खुले 1300 स्कूल्ज जो बंद किये वह तो हिमाचल प्रदेश के ही थे। सी0बी0एस0ई0 से यहां के स्कूल्ज की संबद्धता का श्रेय प्रदेश सरकार ले रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में सी0बी0एस0ई0 से प्रदेश के स्कूल्ज की संबद्धता के लिए केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते तो हमें प्रसन्नता होती। समग्र शिक्षा के अंतर्गत 22 बार वर्तमान प्रदेश सरकार को पैसा प्राप्त हुआ है। यानी लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश को प्राप्त हुई। लेकिन उसके लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं किया गया। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भवन के उद्घाटन में अगर आप अपने नाम का फट्टा लगायें तो उस समय केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करें। इसलिए मैं पुनः यही कहना चाहता हूं कि जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है उसमें सारा पैसा केंद्र सरकार से ही प्राप्त हो रहा है। रूसा में भी केंद्र सरकार ही पैस दे रही है।

19.03.2026/1535/DT/AG-2

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश को सबसे अधिक पैसा मिला है। लेकिन इसका जिक्र कांग्रेस का कोई भी नेता कहीं नहीं करता। हर जगह यही बोला जाता है कि यह प्रदेश सरकार ने दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गरीब, वंचित और शोषित लोगों के लिए 90000 मकानों की एक मुश्त सैंक्शन दी गई। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्र में 65 वर्षो तक कांग्रेस की सरकार रही लेकिन इनकी सरकार द्वारा 1000 मकान भी नही दिए गये होंगे। लेकिन भाजपा की सरकार ने 90000 मकान एकमुश्त प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश को दिए हैं।

जल जीवन मिशन में भी प्रदेश में बहुत से काम हो रहे हैं। उसका भी इस अभिभाषण में जिक्र नहीं किया गया है। 3900 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार दे चुकि है। जल जीवन मिशन में आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी से मिले थे और इस बार जल जीवन मिशन में प्रदेश के लिए जो बजट है उसे बढ़ाया गया है

और वह पैसा प्रदेश सरकार को मिलेगा। लेकिन वह पैसा एक ही कंडिशन में मिलेगा जैसे जल जीवन मिशन में चौपाल विधान सभा के साथ प्रदेश सरकार द्वारा अन्याय किया गया है और एक भी पैसा इस मिशन के अंतर्गत चौपाल विधान सभा क्षेत्र में नहीं दिया गया, ऐसा अब नहीं हो। इसके विपरीत जल जीवन मिशन में जो कार्य पूर्व सरकार के समय में चले हुए थे उनको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अब जो पैसा केंद्र सरकार से इस मिशन में आयेगा उस पैसे में चौपाल विधान सभा क्षेत्र को भी पैसा प्रदेश सरकार को देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) मैं सड़कों के लिए भी धन्यवाद करूंगा ...(व्यवधान) शिक्षा के क्षेत्र भी काफी पैसा चौपाल विधान सभा को मिला है लेकिन यह पैसा केंद्र सरकार का है।

मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं और हमारे मंत्री महोदय ने भी इसके लिए काफी एफर्ट्स किए हैं, सड़कों के संबंध में मैं कई बार इनसे मिला हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपये मिला है। चौपाल विधान सभा क्षेत्र की जनता दिल की गहराई से माननीय प्रधान मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने यह बात कही थी जो वर्तमान सरकार ने झूठी गांरटियां दी हैं जिसके कारण अभी तक पंचायती राज के चुनाव में

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2026/1540/ए.जी.-एन.जी./1

श्री बलबीर सिंह वर्मा..... जारी

आप अपने कैंडिडेट्स खड़े नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की महिलाएं अपने 1500/- रुपये लेने के लिए डंडे लेकर खड़ी हैं। जब तक आप वर्ष 2022 से वर्ष 2026 तक का पूरा एरियर हर महिला को नहीं देंगे तब तक महिलाएं आपको एक भी वोट देने वाली नहीं हैं। मैं हमारी बहन MLA साहिबा (माननीय सदस्य, श्रीमती कमलेश ठाकुर की ओर देख कर कहा) से भी विनती करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को कहें कि बहनों के हक को मत छीनें

और उन्होंने 1500/- रुपये देने की जो बात अपने भाषण में कही थी कि पहली कैबिनेट में देंगे, वह जरूर दें नहीं तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में प्रदेश की महिलाएं आपको पूरा सबक सिखाएंगी।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वन माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया है, ये सारे माफिया जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं और जिस प्रकार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें दिन-दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि, वीरभूमि और सेबभूमि है। इसको जैसी है वैसी रखने के लिए हम सबको यानी के पक्ष-विपक्ष को मिलकर एक मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में बाहरी तत्व आकर बहुत गुंडागर्दी भी करते हैं। जिस तरह से प्रदेश के अंदर वन माफिया सक्रिय है और उनके लिए कोई सख्त कानून बनाने की जरूरत है नहीं तो हिमाचल प्रदेश में आने वाली पीढ़ी के लिए हम पेड़ नहीं बचा पाएंगे तथा इस माननीय सदन में बैठे हुए हम सभी इसके दोषी होंगे। आने वाली पीढ़ी हमें ही दोषी ठहराएगी कि हमने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, वे चाहे मंडी में कट रहे हों या सिरमौर में कट रहे हों। हर जगह लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन इस पर प्रदेश सरकार कोई मजबूत कानून नहीं बना रही है और न ही किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तथा न ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है।

19.03.2026/1540/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मेरी प्रदेश सरकार से विनती है कि इसके लिए जरूर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था, उसमें मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए की हो। अगर कोई चीज मिली है तो वह केंद्र सरकार से मिला पैसा है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सड़कें रिपेयर हो रही हैं, सड़कों में डंगे लग रहे हैं, जो सड़कें

आपदा में खत्म हुई थीं, उसके लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 1500/- करोड़ रुपये दिए हैं और उसी से काम हो रहा है। अगर वह 1500/- करोड़ रुपये नहीं आते तो आज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सड़कें बंद पड़ी रहती। लेकिन प्रदेश सरकार एक बार भी धन्यवाद नहीं करती कि वर्ष 2023 में जो आपदा आई थी, उसके लिए केंद्र सरकार ने विशेष सहायता दी है। हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है कि सारा पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है और केंद्र की योजनाओं के तहत ही से सारे काम हो रहे हैं। आपदा के बाद जितनी भी सड़कें खुल रही हैं या डंगे लग रहे हैं, वह सब केंद्र सरकार की योजना से हो रहा है। पूर्व की प्रदेश सरकार में श्री जय राम ठाकुर जी ने स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं बनाई थीं, जिसमें सहारा योजना आदि शामिल हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी योजनाएं थीं, वे सारी योजनाएं वर्तमान प्रदेश सरकार ने बंद कर दी हैं। आज जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। मेरी सरकार से विनती है कि जनहित की योजनाओं को दोबारा शुरू करें। जिन गरीब और बीमार लोगों के पास अपने साधन नहीं हैं, उन्हें इन योजनाओं से बहुत लाभ मिलता था लेकिन प्रदेश सरकार ने ये सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। हो सकता है कि आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नाम से इनको कोई दिक्कत होगी लेकिन प्रदेश सरकार इन योजनाओं का नाम कुछ और दे दे परन्तु इन योजनाओं को चालू कर दें, हम यही कहना चाहते हैं।

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया है। धन्यवाद।

19.03.2026/1540/ए.जी.-एन.जी./3

सभापति : अब माननीय सदस्य, श्री विनोद सुल्तानपुरी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।...(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलना चाहते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

सभापति महोदय, आज इस माननीय सदन में जो सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया गया है, अभी तक किसी भी माननीय सदस्य को उसकी कॉपी नहीं मिली है। 40,461/- करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है और मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि यह कुल बजट का लगभग 70 प्रतिशत बनता है, जबकि आज से पहले 18 प्रतिशत से ऊपर

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1545/ए.पी. /ए.एस. -1

श्री जय राम ठाकुर जारी .....

कभी भी सप्लीमेंट्री बजट 18 प्रतिशत से ऊपर नहीं गया था, लेकिन इस बार यह 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मैं ढूंढता रहा और सबसे पूछता रहा कि आज जो सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया, पारित हुआ है उसकी कॉपी हमें नहीं मिली है। नियम के अनुसार वह कॉपी बजट पास होने से पहले हमें दे दी जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं दी गई है। सभपति महोदय, यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है और ऐसा लगता है कि सरकार सारी चीजों को विपक्ष के साथ छुपा रही है। हमें मालूम है कि wage and means के अंतर्गत कई बार ट्रेजरी से सारे खर्चों को चलाने के लिए पैसा लिया जाता है। लेकिन इन्होंने तो आज तक का इतिहास ही तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश का बजट 58,000 करोड़ रुपये है, लेकिन उसमें से 40,000 करोड़ रुपये के लगभग सप्लीमेंट्री बजट पास किया है। यानी कुल मिलाकर 98,000 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ है। यह प्रश्न उठता है कि इतना पैसा खर्च हुआ, तो कहां खर्च हुआ। सदन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। सदन की अवमानना तो यह है ही इसके साथ ही यह प्रदेश के साथ बहुत बड़ा मज़ाक है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय को लेकर सभी बातें स्पष्ट करे। मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन उप-मुख्य मंत्री जी यहां पर है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी 18

प्रतिशत से ज्यादा सप्लीमेंट्री बजट नहीं हुआ था। इस बार 70 प्रतिशत को आपने टच कर दिया है। अगर इतना पैसा खर्च हुआ है तो यह पैसा कहां पर खर्च हुआ है? विकास के कार्य तो पूरी तरह से बंद हैं, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, पेंशनरों को वक्त पर पेंशन नहीं मिल रही, विकास की सारी योजनाएं बंद हो रही हैं। अभी यह सप्लीमेंट्री बजट को कही से डाउनलोड करके लाए हैं। हम तो यह मान कर चले थे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन अगर इस पर चर्चा नहीं हुई है तो यह बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है। मैं चाहता हूं कि इस सारी चीज को सरकार स्पष्ट करे। इस सारी चीज को छुपाने की क्या वजह है?

सभापति : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपका विषय आ गया है।

19.03.2026/1545/ए.पी. /ए.एस. -2

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इस दस्तावेज को हमें तुरंत उपलब्ध करवाया जाए क्योंकि जब मीडिया वाले हमसे पूछने के लिए आए तो हम क्या कहें, we know nothing because we are not having the documents. हमारे पास इसका कोई दस्तावेज ही नहीं था। इस सारी चीज को छुपा कर क्यों रखा गया? मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट जवाब दे ताकि प्रदेश की जनता के सामने सही बात रखी जा सके, धन्यवाद।

सभापति : माननीय संसदीय एवं कार्य मत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री : सभापति महोदय, अभी माननीय श्री जय राम जी ने जो विषय रखा है The Government has taken a note of it and what he has said I will convey it to the Government. जिस विषय पर वे बोल रहे हैं कि Supplementary Budget आज इस

माननीय सदन में रखा गया है और उसके आंकडे लगभग 40,000 करोड़ रुपये बताया जा रहे हैं, इस पर मुझसे भी मीडिया के लोगों ने पूछा कि Supplementary Budget लगभग 40,000 करोड़ रुपये का है। आप जो बोल रहे है आपको भी मीडिया के लोगों ने कहा है। मुझे नहीं लगता कि यह आंकड़े सही होंगे। हमारी आर0डी0जी0 वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2025-26 में 3,200 करोड़ रुपये रही। यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपये का अंतर केवल आर0डी0जी0 में ही हो गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह आंकड़ा सही होगा। आपकी बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश का Supplementary Budget सामान्यतः 10-12 या अधिकतम 15 प्रतिशत तक होता है। मुझे लगता है कि ये आंकड़े सही नहीं हैं। What he has said we have taken a note of it and we will find it out कि एक्चुअल में यह कितना है। मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं है। But we have taken a note of it and we will convey it to you.

(माननीय अध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए।)

श्री ए0टी0 द्वारा जारी.....

19.03.2026/1550 /AT/AS /01

अध्यक्षः माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब सप्लीमेंट्री बजट पेश हो रहा था और जब डिमांड को पारित किया गया तब आपको उसी समय ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। जो भी आपके ऑब्जेक्शन हैं यह अब आपका आफ्टर थॉट है। उसमें तो आपने हिस्सा नहीं लिया आप कोई भी सदस्य नहीं बोले। जब आज सुबह सप्लीमेंट्री बजट को यहां लाया गया तब आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि आप बिना तैयारी के आए आपने कुछ देखा भी नहीं। ...(व्यवधान) नहीं ऐसा है कि हर चीज का ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, एक मिनट। बोलने दीजिए। मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, आप बैठिए। मैं बताता हूं कि डॉक्यूमेंट कहां है। मैं इसलिए अपने चैम्बर से उठकर आया हूं। पहले माननीय उप-मुख्यमंत्री जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी छः बार के विधायक रहे हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। जब डिमांड पर चर्चा हुई where were you तब आप कहां थे? जब इस डिमांड को पास किया गया ...(व्यवधान) आपने डिमांड पढ़ी ही नहीं।

अध्यक्ष : वह NeVA में है।

उप-मुख्यमंत्री : जब यहां पर डिमांड रखी गई और स्पीकर साहब ने डिमांड को पास करवाया तब सबके सामने हां की हां में और ना की ना में बात हुई। आपने उस समय ...(व्यवधान)

Speaker : I will tell you. एक मिनट, आप बैठ जाइए।

उप-मुख्य मंत्री : यह भी कहा गया था कि कोई सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है तो रिकॉर्ड देख लिया जाए। ...(व्यवधान) सर, रिकॉर्ड निकाला जाए ...(व्यवधान) विधान सभा का रिकॉर्ड निकाला जाए।

अध्यक्षः एक मिनट, बैठ जाइए।

19.03.2026/1550 /AT/AS /02

उप-मुख्यमंत्री : आपसे एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह गंभीर चूक हुई है कि आपने इसमें भाग नहीं लिया।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, एक मिनट बैठिए। मैं इसी कारण अपने चैम्बर से आया था। डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। आप अपने मॉड्यूल पर देखें, NeVA पर देखें। ...(व्यवधान) यह

पहले से अपलोड है मैंने भी उसी से पढ़ा है। ...(व्यवधान) एक मिनट, please, take your seats. बैठ जाइए, मुझे बोलने दीजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के कुछेक सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।)

अब जो आपत्ति माननीय नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह सप्लीमेंट्री बजट आपके ई-मॉड्यूल और NeVA पर उपलब्ध है। आज सुबह जब यह बजट पास हो रहा था तब जो माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के यहां उपस्थित थे वे इस बात के साक्षी हैं कि मैंने बीच में समय दिया, पॉज़ दिया और पूछा कि क्या कोई सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है।

मैं कुछ सेकंड रूका, फिर मैंने कहा कि nobody wants to take part in the discussion उसके बाद ही यह पास हुआ।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1555/केएस/डीसी/1

Speaker continues -----

All the objections that have been raised by the Hon'ble Leader of the Opposition are baseless. However when the Supplementary Demand was being passed as referred by the Hon'ble Deputy Chief Minister; at that particular point of time none of the Members of the Opposition stood on their seats nor objected to any of the Demands and any of the Motions which were being discussed and passed in the House. So this is uncalled for, baseless and hereby rejected.

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जो जय राम जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने यहां पर विशेषकर आपके ऊपर आरोप लगाने का काम किया, वह बड़ा निंदनीय है। आप इस सदन को बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ चलाते हैं।

(**भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में वापिस आए**)

आप विपक्ष को हर मुद्दे पर उचित समय देते हैं जिसका हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब यह सप्लीमेंट्री बजट ...(व्यवधान)Sir, I am speaking. ...(Interruption).

अध्यक्ष : अगर यह नहीं खुला था तो आपको चाहिए था कि जब यह प्रेजेंट हो रहा था तो आप उसको ऑब्जैक्ट करते कि हमारे पास डॉक्युमैंट्स नहीं हैं। प्रेज़ेंट होने के समय तो आपने ऑब्जैक्ट किया नहीं। जब पास भी हो गया तो पता नहीं आपको कहां से यह जानकारी मिली और आप ऑब्जैक्शन ले रहे हैं? आपके 50 परसेंट माननीय सदस्य उस समय सदन में प्रेज़ेंट थे। जय राम ठाकुर जी उस वक्त नहीं थे लेकिन बाकी माननीय सदस्य सदन में प्रेज़ेंट थे और आपने ऑब्जैक्ट ही नहीं किया। ...(व्यवधान) आपने ऑब्जैक्ट नहीं किया, मैंने समय दिया। This is an afterthought, अब यह ओपन नहीं होगा, अब तो यह पास हो चुका है। ...(व्यवधान) आपके मॉड्यूल पर नहीं खुल रहा होगा, मेरे तो खुल रहा है। ...(व्यवधान) मान लिया कि अगर आपका नहीं खुला तो आपको चाहिए था कि जैसे ही मुख्य मंत्री जी को मैंने अनुपूरक मांगों को पास करने के लिए कॉल किया, आप अपने स्थान पर खड़ा हो कर कहते कि हमको इसका डॉक्युमैंट नहीं मिला है, तब तो मैं आपका यह ऑब्जैक्शन रजिस्टर करता। आपके आधे से ज्यादा माननीय सदस्य

बैठे थे, ठाकुर साहब आप तो उस वक्त हाउस में थे ही नहीं। मैंने विशेष रूप से अपोजीशन के बैंचिज़ की तरफ देखा कि कोई माननीय सदस्य इसका ऑब्जैक्शन तो नहीं लेना चाहता लेकिन जब आपने ऑब्जैक्शन ही नहीं लिया तो मैं रुकूंगा थोड़े ही कि आपके ऑब्जैक्शन इंवाइट करुंगा। मैंने तो डिस्कशन में जो डिमांड आ रही थी, ...(व्यवधान) जय राम ठाकुर जी, कृपया बैठ जाइए। सप्लीमेंट्री है, ये पास हो गया है। अगर आपने कुछ बोलना है तो पहले हर्षवर्धन चौहान जी को बोलने दीजिए फिर I will hear you. I will hear every Member.

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने कहा कि जब यहां पर मुख्य मंत्री जी ने सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, प्रोपोज़ किया और वॉइस वोट से उसको पास किया गया, आपने जो भी परम्पराएं हैं, एक सिस्टम है, उसके मुताबिक आपने कार्यवाही का संचालन किया। Now it is an afterthought कि ये सोच रहे हैं कि अब सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया। अब आपके कम्प्यूटर पर ऑनलाइन है। आज से कुछ समय पहले हमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाई जाती थी लेकिन अब हमें वह नहीं मिलती क्योंकि हमारी टैक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। आज जो हमारा बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है या प्रश्न हैं, वे तो आपको ऑनलाइन मिलते हैं। यह आरोप लगाना कि आपका कम्प्यूटर नहीं खुला, you should have objected. You should have requested.

अध्यक्ष : यहां तो खुलता है। आपकी ई-बुक खुल रही है।

संसदीय कार्य मंत्री : सर, पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। मुझे इस सदन में 30 साल हो गए, मेरी 6th term है। हम जानते हैं कि जितना समय आप विपक्ष को देते हैं, कोई भी नहीं देता और हमें एतराज़ भी नहीं है। आप इनको समय दो क्योंकि हम चाहते हैं कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा हो। पक्ष और विपक्ष उसमें तर्कसंगत बात रखे और जो भी आप फैसला लेते हैं वह हमें मानना पड़ता है। अब कल आपने हमारे एक माननीय विधायक के बारे में चर्चा की। आपने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्ज़ दिए, हम मानते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

19.03.2026/1600/av/dc/1

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री)------जारी

और he has been directed by the Hon'ble Chief Minister and by the CLP कि इस तरह का व्यवहार सदन का कोई भी सदस्य न करे। अगर हम गलत परम्पराओं को राजनीतिक आधार पर शह देकर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस माननीय सदन की स्वस्थ परम्पराओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

यह कोई मुद्दा भी नहीं है। सदन के अंदर अनुपूरक बजट पेश हुआ और पास हुआ तो यह पहली बार थोड़ी न हुआ। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर यहां पर 30 वर्षों से बजट और अनुपूरक बजट की विधि देख रहे हैं। इनको पता है कि बजट से पहले अनुपूरक बजट आएगा। अनुपूरक बजट मुख्य मंत्री पेश करेंगे। उस पर वॉइस वोटिंग होगी। ये लोग उस वक्त कहां सोये हुए थे? Now it is an afterthought. मैं खुद भी अभी ऑनलाइन देख रहा हूं। मुझे खुद भी पता नहीं था, मुझे भी मीडिया वालों ने पूछा। उसमें आपको सारी डिटेल दी गई है। राज्य स्कीमों के अंतर्गत 26194 रुपये वेज एण्ड मीन्ज तथा ओवरड्राफ्ट 4150 रुपये, इसमें ऑनलाइन सारी-की-सारी डिटेल दी गई है। हमें इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जो मुझे बोल रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं बोला, यह तो सारा ऑनलाइन खुल रहा है। इसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगों (प्रथम व अंतिम किस्त) पर चर्चा होगी जोकि आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान भी होगा। उसके उपरांत हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी पारित होगा। सदस्यगण चर्चा में भाग ले सकते हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री जिनके पास वित्त विभाग भी है, चर्चा का उत्तर देंगे।

इसके बाद मैंने बोला 'Anybody wants to speak?' पॉज दिया, 'Nobody wants to speak.' This is on the record. उसके बाद हमने अगली कार्रवाई की है।

अब माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बोलिए।

19.03.2026/1600/av/dc/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आज से पहले यह कंवेंशन रही है कि जब भी अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाता है साथ में उसकी कॉपी दी जाती है। इसके पीछे क्या वजह रही कि आज नहीं दी गई? वह इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसमें

आपका 70 प्रतिशत अनुपूरक बजट टच कर गया है। उसको कहीं-न-कहीं छिपाने की कोशिश की गई है।

अध्यक्ष : इसके बारे में मैं बताता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप नहीं बताएंगे। आप इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ रहे हैं। नेवा से डाउनलोड तब होता है जब कोई डॉक्यूमैंट यहां पर ले हो जाता है और उसके बारे में हमें यहां पर सूचना आती है कि 'documents are being downloaded'. इसमें ले होने के बाद डाउनलोडिंग की इंडीकेशन आती है और वह तब आती है जब आप ले करते हैं, सीधी-सी बात है।

अध्यक्ष महोदय, चलो थोड़ी देर के लिए आपकी ही बात मान लेते हैं। जिस बात पर प्रश्न उठा है कि आपने ले कर दिया और नेवा के माध्यम से आपके लैपटॉप पर आ गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसके बाद डाक्यूमैंट देने की परम्परा बंद कर दी गई है, आप मुझे यह बताइए? अभी जो बजट प्रस्तुत होने वाला है तो क्या हमें बजट के डॉक्यूमैंट उपलब्ध नहीं होंगे? ...(व्यवधान) आप हमें इस बात को स्पष्ट कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति हमारा सम्मान है परंतु सरकार की ओर से जो चालाकी की गई है उसका हिस्सा आप मत बनिए, मेरा आपसे इस बात के लिए निवेदन है। हम आपसे न्याय मांगते हैं क्योंकि अनुपूरक मांगों को पारित करने से पहले उसको ले किया जाता है तो उसको ले करने में क्या दिक्कत आई? यह इस बार ही क्यों हुआ जबकि यह हर बार दिया जाता था। आप यह बात स्पष्ट कर दीजिए। दूसरा मेरा यह कहना है कि सरकार प्रदेश को बहुत ज्यादा गुमराह कर रही है क्योंकि बजट 58 हजार करोड़ रुपये का है और आज आपने जो 40 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया उस हिसाब से हम 98 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं।

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1605/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री जय राम ठाकुर ... जारी

अब जब आप इस बात को पूछ रहे हैं तो आप देखिए यह वर्ष 2024-25 में 29.17 प्रतिशत, वर्ष 2023, 24 में 19.28 प्रतिशत, वर्ष 2022, 23 में 25.5 प्रतिशत था, वर्ष 2021, 22 में 4.33 प्रतिशत और 2020-21 में 18.75 था। लेकिन अबकी बार जब 69.1 प्रतिशत यानी लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचा है तो स्वाभाविक रूप से हमारा यह प्रश्न बनता है।

अध्यक्ष : प्लीज ठाकुर साहब, आपको बहुत कुछ जानने का अधिकार है लेकिन आपने उस समय नहीं पूछा। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि जो आप बोलेंगे वह रिकॉर्ड पर जाएगा और जो हम बोलेंगे उसे आप रिकॉर्ड से हटा भी सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने गलत किया है। परंतु आपने भी उस वक्त एक सांस में बोला है। हमें डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, हम उम्मीद कर रहे थे कि 4 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत तक इंक्रीज होगी, लेकिन यह इंक्रीज 70 प्रतिशत की हो गई जिससे पूरे प्रदेश के होश उड़ गए।

इसलिए हमारा विषय सिर्फ व्यवस्था से संबंधित है। सरकार ऐसी हरकत कर सकती है, सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार इस तरह की हरकत की है। इनकी आदत है झूठ बोलना, असत्य बोलना, प्रदेश को गुमराह करना और विधान सभा को गुमराह करना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमको आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है।

उप-मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कभी हुआ है कि कोई डिमांड पारित हो जाए और उसके बाद उस पर आपत्ति की जाए, यह संभव नहीं है ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है, आप सुनिए जब आप बोलते हैं तो हम आपको सुनते हैं लेकिन जब हम बोलते हैं तो आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं और सुनते ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, डिमांड यहां रखी गई, उस पर आपने बोलने का मौका दिया लेकिन इनसे यह गंभीर चूक हुई कि इन्होंने न उस पर कुछ बोला, न उसमें पार्टिसिपेट किया और न ही इन्होंने उस समय कहा कि मुझे लिखित डॉक्यूमैंट उपलब्ध करवाया

19.03.2026/1605/टी0सी0वी0/एच0के0-2

जाए क्योंकि मेरा सिस्टम चल नहीं रहा है लेकिन अब जब बिल पास हो गया, डिमांड पास हो गई, बजट पास हो गया, उसके बाद यह कहना कि मैं सहमत नहीं हूं, यह उचित नहीं है। यह कहा जा सकता था कि मैंने देखा नहीं और मुझसे गंभीर चूक हुई as a Leader of the Opposition लेकिन मैंने नहीं देखा और मेरे ध्यान में यह अब बात आई है तो बात अलग है। ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है। आपसे गंभीर चूक हुई है। माननीय सदस्यों का काम कानून बनाना और डिमाण्डज को देखना है लेकिन आपने वह नहीं देखा। परंतु डिमांड तो हाउस में पास हो गई है उसके बाद आप सत्ता पक्ष पर दोषारोपण करें कि इन्होंने छुपाया, स्पीकर साहब ने समय नहीं दिया, यह गलत है। आप अपना रेलिवेंट पक्ष रख रहे हैं, यह ठीक है, आपसे चूक हुई है, अब आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो कल मुख्य मंत्री जी आएंगे और आपको डिटेल में रिप्लाई मिल जाएगा।

Parliamentary Affairs Minister : Speaker, Sir, it is a very important issue. They want an explanation from the Hon'ble Chief Minister regarding it. I had a discussion with Hon'ble Chief Minister. He said that he will come and explain it to the House. Hon'ble Chief Minister is coming and he will explain it. वैसे तो इस पर कोई चर्चा नहीं बनती है

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1610/NS-HK/1

संसदीय कार्य मंत्री ------जारी

as the Supplementary Budget has been passed so, Sir, for their satisfaction, I have conveyed the opinion and sentiments of the House to the Hon'ble Chief Minister. He told me that he is coming and explain it to the House.

Speaker : I will put the record straight. मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा। मैं भी काफी समय तक वहां बैठा हूं। अब आप बोल रहे हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। आज के बिजनैस की डिटेल पिछल कल शाम को लोड हो जाती है। आपने उसमें देखा होगा कि यहां पर सप्लीमेंटरी बजट रखा जाएगा, पेश भी होगा और पास भी होगा। यह ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर है। अभी आपको सुबह इसकी प्रतिलिपियां नहीं मिलीं। आपको उसी समय चाहिए था जब मैंने कहा कि अब अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा होगी। मैंने एक-एक शब्द स्पीड से पढ़ा और बीच में पॉज भी दिया ताकि माननीय सदन का समय बचे तथा ज्यादा-से-ज्यादा माननीय सदस्य विषयों के ऊपर चर्चा कर सकें। आप उस वक्त उठते कि हमें कोई कॉपी नहीं मिली है। इसलिए आप हमें पहले कॉपी दें और फिर हम इसको प्रेजेंट करने की इजाजत देंगे। तब मैं आपकी बात मान लेता। अब जब सब कुछ हो गया, आप सभी माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ हैं और आपके 6-6 टर्म को हो गए हैं, आप स्पीकर भी रहे, मुख्य मंत्री रहे, मंत्री रहे तथा आगे आपको भगवान और चांस दे तथा आप अपने आप सोचो आप इस विषय को कब उठा रहे हैं? आप अपनी जग हंसाई कर रहे हैं। मीडिया देख रहा है और जो कुछ हुआ है वह सब रिकॉर्ड पर है। आप अब ऑब्जैक्शन कर रहे हैं तो you are trying to derogate yourself. This is shocking state of affairs. आप उस समय ऑब्जैक्शन करते तो मैं आपको उसी समय मौका देता। अब तो अनुपूरक बजट मेजोरिटी ऑफ वॉयस से पास हुआ और उस समय किसी ने न नहीं की। उस समय हां में हां ही रही है। इसलिए इस विषय को उठाने का कोई औचित्य नहीं था फिर भी मुख्य मंत्री जी आकर स्पष्टीकरण दे देंगे। आपको इसकी प्रतिलिपियां चाहिए होंगी तो मिल जाएंगी जब बजट में चर्चा होगी। कल फिर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी इश्यूज ओपन हैं। अभी कल भी चर्चा होनी है और कुछ माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से बोलेंगे और कुछ विपक्ष के बोलेंगे। You can meet these points at that relevant time. So saving the time of the

Hon'ble House, now I would request the next Member. श्री बलबीर सिंह वर्मा जी बोल बैठे हैं और सत्ता पक्ष से श्री विनोद सुल्तानपुरी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हालांकि, राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण को नहीं पढ़ा। इस अभिभाषण में हमारी सरकार ने इनोवेटिवली काम किया है और इसमें उसका विवरण है। आज जब हम धरातल पर देखते हैं तो हिमाचल आगे की तरफ बढ़ा है, प्रगति हो रही है। लेकिन विपक्ष की पॉलिटिकली मोटिवेशन यही रही है कि किस तरह से हमारी सरकार गिरे और इनका इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहा है। अधिकांश वॉकआउट हुए हैं और आज बारिश की वजह से वॉकआउट नहीं हो पाया लेकिन आज फिर से वॉकआउट करने की तैयारी थी। हमारी सरकार ने निर्णय लेकर इनोवेटिव तरीका आगे बढ़ने का ढूंढा है और वह सराहनीय है। इसमें चाहे एनर्जी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी हो या जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो उनको हम कैसे बेहतर कर सकें और इनको बेहतर करने का तरीका सरकार ने अपनाया है। सरकार इसके लिए हाईटैक मशीनरी का इस्तेमाल करने जा रही है। सरकार ने सारी पुरानी मशीनों को अपग्रेड किया है। रोबोटिक सर्जरी के ऊपर डिस्कशन हुआ है। एम0आर0आई0, पैट स्कैन के ऊपर बात हुई है।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

19.03.2026/1615/RKS/YK-1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी....

शिक्षा के क्षेत्र में पहले हम 21वें स्थान पर थे लेकिन आज हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर पहुंचे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में सही निर्णय लिए हैं। चाहे

आज हमारी इंटरोडक्शन रेशनलाइजेशन, CBSE के लिए किए गए प्रयास हों, या डे बोर्डिंग स्कूलों के बारे में विचार हो पर हम इस पायदान में पहुंचे हैं। एक्सपोजर टूअर के अंतर्गत अध्यापकों और बच्चों को विदेशों में भेजा गया। यह नये तरीके हैं और इन तरीकों के द्वारा हमारे हिमाचल के बच्चों को अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। पहले यह हीन भावना थी कि केवल अंग्रेजी स्कूल ही CBSE होते हैं लेकिन आज हमारा गरीब से गरीब बच्चा भी CBSE की एजुकेशन ले सकता है। हालांकि जो नए तरीके अपनाए गए हैं उनमें AI के लिए भी नई शुरुआत की गई है। कसौली निर्वाचन क्षेत्र के परवाणू में उद्योग विभाग के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत अच्छा आधुनिक संस्थान बनने जा रहा है जिसमें हमारे बच्चों की काबिलियत को बेहतर करने के लिए एजुकेशन दी जाएगी। आज हम यह भी देखते हैं कि जब हमारा प्रदेश आपदा से जूझ रहा था तब भी हमने सभी से अनुरोध किया कि हम दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी बात रखें और हिमाचल में हुई इस बड़ी त्रासदी के बारे में चर्चा करें। लेकिन जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो उस समय भी अंत में विपक्ष के लोगों ने वाकआउट कर दिया। फिर RGD के ऊपर जब चर्चा हुई तब भी आपने वाकआउट कर दिया। हमारे विपक्ष के लोगों को विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभानी चाहिए ताकि क्रिएटिवली हिमाचल के लोग आगे बढ़ सकें। हमें इस पर गहनता से विचार करना चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन यहां जो चर्चा हुई कि किसी को मार देंगे, किसी को खींच देंगे, किसी के दांत कितने हैं या नहीं, यह उचित नहीं है। मेरे गांव में अभी एक मेला है जहां कुश्ती का आयोजन भी किया जाएगा। मैं सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप सब वहां आएं, 32 दांत वाले भी वहां आए। वहां खुला मैदान होगा, हम सब लोग जलेबी भी खाएंगे और कुश्ती भी देख लेंगे। श्री बलबीर सिंह वर्मा जी यह मेला 26 तारीख को है और आप सादर आमंत्रित हैं। आपको हम माली ऐसे ही जीता देंगे। जब हम माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों को सुनते हैं तो हमें लगता है कि जब एक किसान का बेटा मुख्य मंत्री बनता है तो वह जमीन से जुड़े मुद्दों को समझता है। चाहे गेहूं हो, मक्की हो, हल्दी हो या फिशरिज की बात हो , इन सब चीजों को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए और किसानों को लाभ दिलाने के लिए

19.03.2026/1615/RKS/YK-2

मुख्य मंत्री जी ने minimum support price को निर्धारित किया। वह समय भी हमने देखा जब हमारे किसान दिल्ली गए और उनके सामने बड़े-बड़े barricades लगाए गए। आज हिमाचल आगे की ओर बढ़ रहा है और इस अभिभाषण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने किस प्रकार हिमाचल के हित में कार्य किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और यहां उपस्थित सभी कैबिनेट मंत्रियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके इन कार्यों को सफल बनाया है। आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 150 करोड़ रुपये सड़कों के लिए दिए गए हैं। सड़कों की स्ट्रेंथनिंग टूरिज्म के लिए आवश्यक थी और इसके लिए हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मैं इस कार्य के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो हमारी पानी की समस्या थी उसके समाधान के लिए माननीय उप-मुख्य मंत्री ने कौशल्या बांध से योजना लाने के लिए NABARD के तहत 21 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कार्य कर रही है और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूं। जब माननीय मुख्य मंत्री जी सोलन आए थे तो हमें उनके समक्ष अपनी क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका मिला। वहां 168 करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत सुंदर Center of Excellence for Special children बनने जा रहा है। इसी तरह मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना भी हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1620/बी.एस./वाई.के.-1

श्री विनोद सुल्तानपुरी जारी...

अब ये वोटर तो नहीं हैं, परंतु इन्हें जरूरत है और इस जरूरत को मुख्य मंत्री जी ने समझा है। जो गरीब से गरीब हैं और जो असहाय है, उन लोगों की मदद करने के लिए सरकार आगे आई है। जब उनसे आशीर्वाद मिलता है तो भरपूर आशीर्वाद मिलता है। आप अगर आज किसी असहाय की मदद करते हैं, तो वह आशीर्वाद के रूप में आपको मिलता है और इसी आशीर्वाद के चलते जो ऑपरेशन लोटस था, वह फेल हुआ था।

आज मैं धन्यवाद करता हूं, सर, और इस अभिभाषण के प्रस्ताव के पक्ष में बोलना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जो बीड़ा उठाया है, हिमाचल आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

19.03.2025/1620/बी.एस./वाई.के.-2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो 16 फरवरी को माननीय सदन में अभिभाषण दिया, उस पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं भी चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें जैसा माननीय सदस्य सुल्तानपुरी जी अभी बोल कर गए हैं, तो इनके पास भी बोलने के लिए मिटिरियल नहीं था। क्योंकि जैसा भाई रणधीर जी ने बीच में कहा कि कुछ एक चीजें तो गवर्नर साहब ही ब्लॉक कर गए थे कि इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक चीजें नहीं हैं। उसके बाद ये लोग भी छानबीन कर रहे थे कि कुछ तो बोलने के लिए मिले। जिस पर चर्चा की जा सके। घूम-फिर कर चाहे डिप्टी साहब आएं, चाहे सी0एम0 साहब आएं, ये सब आर0डी0जी0 पर ही आ जाते हैं। तो आर0डी0जी0 का फंडा क्लियर करना जरूरी है। मैं थोड़ी सी रोशनी इस पर डाल देता हूं।

क्या हुआ है कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिस तरह से यह रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट की मांग करते हैं, या जो हमारी जैसी स्टेट्स बनी, भारत सरकार ने उस समय सोचा था कि जो आर्थिक तरीके से राज्य स्वावलंबी नहीं हो सकते या अपने लिए इनकम नहीं जुटा सकते, उनके लिए हम कुछ न कुछ कंपेनसेट करते रहेंगे। ऐसा उन्होंने तब कहा था।

लेकिन यह 40 सालों का अरसा ऐसा रहा, एक इकोनॉमिक ब्लॉग किसी व्यक्ति ने अपलोड किया था, उसको मैंने ध्यान से सुना और देखा तो उसने बड़ा शानदार कहा। उसमें उन्होंने कहा कि अब जैसे हमारे यहां हिमाचल में मिड डे मील वर्ष 2003-2004 में शुरू हुआ और वर्ष 1995 से यह कवायद राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई थी। मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। लेकिन तमिलनाडु के के. कामराज करके एक चीफ मिनिस्टर हुए उन्होंने 1956 में इसकी शुरुआत कर दी थी। देखिए, जो विजनरी लीडर होते हैं या जो विजनरी

स्टेट्स होती हैं, वह शुरू से ही व्यवस्थाएं खड़ी करनी शुरू कर देती हैं। हम सब लोग अपना-अपना घर चलाते हैं। मतलब अड़ोस-पड़ोस में हमारी मान्यता हो इसके लिए हम संघर्ष भी करते हैं। लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल को उतना ही रखते हैं जितनी जरूरत होती है। मैं जो के. कामराज जी की बात कर रहा था, उन्होंने स्कूलों में इसीलिए मिड डे मील शुरू किया, उनको लगा कि अगर आज बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे, तो हमें लेबर के ही लोग मिलेंगे, मजदूर ही मिलेंगे।

19.03.2025/1620/बी.एस./वाई.के.-3

ये लोग जो आर0डी0जी0 की बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने कई जगह पर, मतलब यह तो जब 15वां फाइनेंस कमीशन लागू हुआ, उसी समय से मूल्यांकन शुरू हो गया था। आपने नॉर्थ और साउथ का झगड़ा सुना होगा। नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स का झगड़ा, उनका झगड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस पर है। साउथ वालों का कहना है कि सबसे ज्यादा कर जो इकट्ठा करते हैं वह हम लोग करते हैं। देश में जितना टैक्स इकट्ठा होता है, उसका 50 प्रतिशत हम लोग देते हैं। नॉर्थ के लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जिस एवज में हम लोग फंड भारत सरकार या केंद्र को भेजते हैं, उस एवज में वह रिटर्न में नहीं आता। तो हमें लॉसेस हो रहे हैं। हमारा 50 प्रतिशत का योगदान है और बदले में हमें लगभग 30 प्रतिशत ही रिटर्न में आ रहा है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1625/DT/AG-1

डॉ0 हंस राज जारी ...

साउथ के लोगों न उस समय सामाजिक, आर्थिक और अन्य तरीको से नार्थ के लोगों पर यह आरोप लगाये। पूरा देश एक साथ ही आजाद हुआ, लेकिन कुछ सरकारें ने इनिसिएटिव लिया और अपनी-अपनी स्टेट खड़ी करनी शुरू कर दी। आप दक्षिण में तमिलनाडू राज्य को ले लो, आन्ध्र प्रदेश को ले लो जहां कांग्रेस की सरकार है, जिन्होने खुल के मुखालफत की है कि है की आर0डी0जी0 जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। वे ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने शुरू में आरोप लगाये की आप देश की जनसांख्या को बढ़ा रहे हैं।

आपके यहां चुनाव होते हैं तो वह जातिगत आधार पर होते हैं। यूपी बिहार का उदाहरण उन्होंने उस व्लॉग में दिया है। वे कह रहे हैं कि अगर आप भारत सरकार को 100 रुपये दे रहे हैं तो हम भी 100 रुपये दे रहे हैं और उस 100 रुपये की एवज में हमें 15 रुपये रिर्टन में आ रहे हैं और तुम लोगों को 178 रुपये आ रहे हैं। ये अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको इसमें बदलाव करने पड़ेंगे। यह दवाब भारत सरकार में पहले से ही था। 17 राज्य जिनकी फिडिंग आर0डी0जी0 के द्वारा हो रही थी, उन राज्यों से बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैंने इस सदन के अपने पूर्व के भाषणों में भी कहा है कि हम लोग वास्तव में रिर्सोसिज को खड़ा करने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। मैंने कई उदाहरण भी दिए हैं। अब यह खबर तो बना देते हैं कि पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से आयेगी एक स्टेटमेंट दूसरी तरफ से आयेगी , लेकिन जो लोग निडर होकर पेड़ काट रहे हैं वह यह नहीं समझ पा रहे कि इससे जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। शिमला का मौसम ही देख लो जब मैं एक सप्ताह पहले यहां आया तो टी-शर्ट में घूम रहा था और आजकल लोगों को ओवरकोट पहनने पड़ रहे हैं। इसका कारण अवैध पेड़ कटान भी है। हम बोल रहे हैं सरकार नहीं सुन रही सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं और आप नहीं सुनते। हिमाचल की सरकारों ने कभी यह सोचा ही नहीं कि जब यह फंड खत्म हो जाएंगे या केंद्र सरकार जब यह फंड बंद कर देगी तो क्या होगा? जी0एस0टी0 लागू होने के बाद ही अलार्मिंग स्थिति के बारे में तो प्रदेश सरकार को बता दिया गया था और यह कह दिया गया था कि धिरे-धिरे यह फंड खत्म कर दिया जायेगा। फिर इस बारे में इतना बोलना ही क्यों? क्यों हम लोगों को इस बारे में बलग्रा रहे हैं? प्रदेश के बेरोजगार युवक रोजगार के लिए तीन सालों से सरकार की ओर देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जॉब्स मिलेंगी लेकिन जॉब्स आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं।

19.03.2026/1625/DT/AG-2

जो डवलपमेंट वर्क्स हैं, जैसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों की बात की गई- मैं इसमें पूरे हिमाचल की चर्चा नहीं करूंगा लेकिन प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थान हैं कहां? अध्यक्ष महोदय, कई बार आपने चंबा के स्वास्थ्य संस्थानों से संबंधित मसला उठाया । जैसे चंबा में

मेडिकल कॉलेज है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के हिसाब से जो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं है और वह मेडिकल कॉलेज सिर्फ रैफरल मेडिकल कॉलेज बन कर रह गया है। अभी इन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेन्थन करने के लिए सरकार ने 175 करोड़ रुपये दिए। ये राशि तो शुरू में ही दी जानी चाहिए थी ताकि जो ब्लॉक का काम रूका हुआ है वह बन जाता।

मैं चुराह विधान सभा का नेतृत्व करता हूं। पहले मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीसा में स्थापित सिविल हास्पिटल बहुत अच्छा चलता रहा है। लेकिन अब वहां पर केवल 3-4 डाक्टर्ज ही रह गये हैं जब कि यह हस्पताल 53 पंचायतों को फीड करता है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान आप खोलें या न खोलें वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन वेलफेयर स्टेट होने के नाते सरकार का जो दायित्व लोगों के प्रति बनता है वह तो हम लोगों को निभाना ही चाहिए। हम वह भी नहीं निभा पा रहे हैं। अपनी नकामयाबियों को दूसरों पर थोप देना यह कहां का न्याय है? इसलिए मेरा मानना यही है कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जब अपना अभिभाषण इस मान्य सदन में शुरू किया या उनको उसकी कॉपी दी गई होगी तो उन्हें कुछ तो लगा होगा जो उन्होंने अपनी ओर से एक्सपंज कर दिया कि मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें कुछ टिप्पणियां संवैधानिक संस्थानों पर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिन पर हम लोगों को विचार करना ही चाहिए। जब बजट प्रस्तुत हो जायेगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर हम क्या चर्चा करेंगे। यह भी चिंता का विषय है। हमारे पास रिर्सोसिज ही नहीं हैं। हमने उद्योगों को उस तरह से खड़ा ही नहीं होने दिया। शिक्षा मंत्री महोदय सी0बी0एस0ई0 के संबंध में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं इसके संबंध में एक ही उदाहरण देकर सी0बी0एस0ई0 के मॉडल को भी फेल कर देता हूं। हमारा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भंझाराडू, तीसा एक शानदरा स्कूल है। इस स्कूल में 1200 की स्ट्रेंथ है। यह इतना शानदार स्कूल है कि यहां से पढ़ कर कई विद्यार्थियों ने आई0ए0एस0 और एच0ए0एस0 की परीक्षाएं पास की हैं। मैं भी एक छात्र हूं जो वहां से पढ़ा है और आज यहां खड़े होकर भाषण दे पा रहा हूं। लेकिन अब उस स्कूल की ऐसी स्थिति है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

19.03.2026/1630/ए.जी.-एन.जी./1

डॉ0 हंस राज..... जारी

कि आपने सी0बी0एस0ई0 करके उसके बाहर का गत्ता ही बदला है और अंदर का सामान तो वही है। उसकी किताबें आप ही तो छाप रहे हैं। आपने अपना बोर्ड खत्तम करना शुरू कर दिया है और उस चीज़ का क्या लाभ है? आप उसमें अपना सिलेबस दे रहे हैं। हमारी एस0ई0आर0टी0 क्या कर रही है? हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्या कर रहा है? सी0बी0एस0ई0 तो राजस्थान में चार लोगों ने शुरू की थी और भारत सरकार को वह अच्छी लगी तथा उन्होंने उसका सिलेबस अपना लिया। उन्होंने एक नोटिफिकेशन के आधार पर आई0सी0एस0ई0 भी शुरू कर दी है। आप लोग उनकी नकल कर रहे हैं जिन्होंने कभी किसी की नकल मारी थी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड अपने आप में सक्षम बोर्ड है, जो आपको अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। यहां पर हमने देखा है कि सी0बी0एस0ई0 के पढ़े हुए विधायक भी हैं और आई0सी0एस0ई0 के पढ़े हुए भी विधायक हैं। हमने नहीं देखा कि उन विधायकों को सूर्ख-खाब के पर लगे हुए हैं और वे जो डिबेट करते हैं, उस डिबेट में हम लोग शामिल नहीं हो सकते। हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं और माननीय अध्यक्ष भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। मेरा मानना यह है कि हम अपने संस्थानों को निकम्मा और नकारा कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमैंट में इतना अवैध कटान हो रहा है कि आपको उसे रोकना चाहिए। यह मैंने शुरू में भी कहा था।

अध्यक्ष महोदय, आज मेरे क्षेत्र से कश्मल उखाड़ा जा रहा है और वह एक ऐसी संजीवनी बूटी है, जिससे सरकार को कोई भी राजस्व नहीं मिल रहा है। वहां पर तथाकथित ठेकेदार अलग-अलग राज्यों से आए हैं और उन्होंने वहां पर अपने बंदे मैनेज किए हुए हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हमने उन्हें लाइसेंस दिए हैं जो अपनी प्राइवेट लैंड पर कश्मल उखाड़ रहे हैं लेकिन वे सारे तो जंगलों से लेकर जा रहे हैं।...(घण्टी)...

मेरा सरकार से निवेदन है कि आप जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात सिर्फ़ किताबों में रखते हो, उसे यहां पर अक्षरशः लागू करना पड़ेगा। आपने इंडस्ट्री को जम्मू-कश्मीर की तरफ़ जाने दिया और सरकार ने उस पर कोई काम शुरू नहीं किया। मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर आपको सी0बी0एस0ई0 लागू करना है तो ठीक है लेकिन हमारे जो स्कूल अच्छे चल रहे हैं, उन्हें खराब मत कीजिए। मेरे क्षेत्र में बंजराड़ू बहुत अच्छा स्कूल चला हुआ है। यदि आपको करना ही है तो हिमगिरी का स्कूल, आएल का स्कूल, झज्जा, सनवाल, चांजू, चरड़ा या माणी, मसलूड़, झूलाड़ा, टिकरी आदि के स्कूलों पर लागू कीजिए लेकिन जो अच्छा स्कूल चल रहा है उसे खराब मत करो।

अध्यक्ष महोदय, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की भी यही बात है। तीसा में एक स्वास्थ्य संस्थान चल रहा था और उसे भी खराब कर दिया गया। उस समय हमने बड़ी मुश्किल से माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की कृपा से दो पी0एच0सी0 खोली थीं। हम लोग गप्पों के लिए तो गप्पे मार लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या दे रहे हैं? हमारी तीसा की सड़क आज भी बंद है। जैसे ही थोड़ी बारिश होती है, चांजू नाला, शेरला नाला और कई नाले ऐसे हैं, जोकि पूरे वेग में बहने लग जाते हैं। आपके पास जो पी0डी0एन0ए0 का पैसा आया, उसमें इतनी बंदरबांट हो रही है कि जो ठेकेदार कई सालों से दुःखी थे कि हमें काम नहीं मिला, उन्हें अचानक काम मिल गया क्योंकि पी0डी0एन0ए0 के पैसे से रातों-रात टेण्डर लगा दिए गए। वे लोग ऐसी-ऐसी जगहों पर डंगे लगा रहे हैं जहां पर ज़रूरत ही नहीं है। हमारे कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी सड़कें पूरी तरह नहीं खुली हैं और सरकार को उन पर काम करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि माननीय राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है, बाकी बातें तो हम बजट पेश होने के बाद कहेंगे क्योंकि यह दूसरा आख़िरी साल है

यानी के सरकार का मुख्ता साल है और अगले साल तो चुनावों की रणभेरी बज जाएगी तो हम यह व्यवस्था परिवर्तन कब करेंगे।

19.03.2026/1630/ए.जी.-एन.जी./3

मेरा कहना यह है कि प्रदेश सरकार को यह आर0डी0जी0 वाला रोना छोड़ देना चाहिए। मैं आपको वह सारा डेटा दे दूंगा जिसमें दक्षिण के राज्यों के लोगों ने कई बार कहा है कि आप लोग यह सब खत्तम कर दो। तुम लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम खां-म-खां के फ्री बीज़ खत्तम नहीं करते, यह 1500 वाली मुफ्त योजना का ड्रामा आदि योजनाओं की अब जरूरत नहीं है।...(घण्टी)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कंक्लूड कीजिए।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में कर रहा हूं। युवा लोग कई-कई सालों से लाइब्रेरी में बैठे हैं और आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप सरकारी नौकरियों को सिर्फ़ विज्ञापन में नहीं, बल्कि वास्तव में लागू करेंगे। पिछले कल माननीय सदस्य, श्री दीप राज जी ने जो विषय रखा था वह बहुत गंभीर था कि आपने रोस्टर को भी खत्म करना शुरू कर दिया। आपने पटवारियों के फॉर्म भरवाकर सभी से एकमुश्त 800-800 रुपये ले लिए। भाई, आप तो संविधान को भी नकार रहे हैं। मैं कल सुन रहा था कि उधर (सत्तापक्ष की ओर देख कर कहा) बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी कल्पना कर रहे थे।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1635/ए.पी. /ए.एस. -1

डॉ हंस राज जारी ...

आप जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, मैंने तो आउटसोर्स भर्ती का भी विरोध किया था। पता नहीं बाकी लोग करते हैं या नहीं। वहां भी रोस्टर नहीं होता था और ग्रास रूट की सच्चाई यह है कि शोषण आपके समय में ही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि महामहिम शिव प्रताप शुक्ल जी द्वारा जो अभिभाषण रखा गया था, उसमें वे कई बातें नहीं पढ़ पाए क्योंकि उसमें ऐसी टिप्पणियां थीं जो केन्द्र सरकार के खिलाफ थीं। लेकिन मैं माननीय राज्यपाल जी के उस अभिभाषण का, चाहे उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय, वैसे तो इश्यू सैटल हो गया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष : जब वे आ जाएंगे आप तब बोलना, तब तक हम चर्चा जारी रखते है। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैं तो बजट ही बना रहा था लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के दिमाग में जो बात है मैं उन्हें बताना चाह रहा था। वे 98,000 हजार करोड़ रुपये का बजट बोल रहे है। आप सभी विधायक निधि के लिए रो रहे हो।

अध्यक्ष : आप तब बोलना as and when he comes. माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा अब चर्चा को बढ़ायेगे। Thereafter Hon'ble Chief Minister can intervene.

श्री हरदीप सिंह बावा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में 16 फरवरी, 2026 को महामहीम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उस पर चर्चा हो रही है। मुझे भी आपने इस पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत से सदस्यों ने कहा, खास तौर पर विपक्ष के मेरे साथियों ने, कि जो महामहीम का अभिभाषण हुआ, वे केवल दो-तीन मिनट का रहा। मैं भी, पहली बार अपने विधान सभा क्षेत्र नालागढ़ से यहां अपने क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद के बदौलत चुनकर आया हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 14वीं विधान सभा में जो घटनाक्रम हुआ, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हमें एक विधायक के तौर पर आशा थी कि महामहीम राज्यपाल

महोदय अपना अभिभाषण देंगे और सरकार के vision document को पढ़ेंगे और उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए जो कुछ हुआ, वह हमारी सोच से परे था। यह हमारे लिए भी एक नया अनुभव था। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के दबाव के चलते महामहीम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा, वह सबके सामने है। मुझे लगता है कि भाजपा द्वारा उन्हें डिक्टेट किया गया था। इस vision document को पढ़ने के लिए उन्होंने मना किया होगा। इस vision document में आर0डी0जी0 और जी0एस0टी0 कंपनसेशन की बात कही गई थी मैं समझता हूं कि इसका केंद्र बिंदु आर0डी0जी0 और जी0एस0टी कंपनसेशन ही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपये का Revenue Deficit Grant जो प्रदेश को मिलता था, उसे शून्य कर दिया गया। विपक्ष के साथी कहें-न-कहें पर वे अपनी पार्टी के दबाव में हैं। यह आर0डी0जी0 के कारण जो घाटा हुआ है यह सरकार का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की जनता का घाटा है। इस पैसे से प्रदेश में अथाह विकास होना था, हमारे विधान सभा क्षेत्रों में प्रोजैक्ट लम्बित पड़े थे इस पैसे की अदायगी से वह पूर्ण होने थे और उन्हें जनता को समर्पित किया जाना था।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.03.2026/1640 /AT/AS/01

श्री हरदीप सिंह बावा जारी...

आज रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म होने से हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। मैं समझता हूं कि यह हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जी0एस0टी0 कम्पनसेशन भी बंद हो गया। मैं खुद इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूं। जब जी0एस0टी0 लागू किया गया और आज उसका व्यापक असर हमने देखा है। जी0एस0टी0 से पहले जो VAT होता था मैं समझता हूं कि वह हिमाचल प्रदेश के लिए ज्यादा फायदेमंद था। जी0एस0टी0 केंद्र सरकार का फैसला था और हिमाचल सरकार ने उसका स्वागत किया लेकिन केंद्र सरकार ने उसका कम्पनसेशन देना जरूरी नहीं समझा क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आज हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधान सभा में, वर्ष- 2023 में सरकार बनते ही जो त्रासदी हुई उसमें प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ। वर्ष-

2023 का एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन वर्ष -2024 में एक राजनीतिक त्रासदी भाजपा द्वारा की गई जिसकी बदौलत आज मैं खुद इस माननीय सदन में बोल रहा हूं। उसी के कारण मैं चुनकर आया। भाजपा ने मिशन लोटस चलाने की कोशिश की लेकिन वह भी धराशायी हुआ। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा कदम उठाया और इसमें भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। हम 40 सीटें लेकर फिर से सरकार में स्थापित हुए।

वर्ष 2025 में दोबारा त्रासदी हुई और इस त्रासदी मैं यह कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जो सोलन जिले के अंतर्गत है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र का हुआ।

आज वर्ष-2026 में जो यह वित्तीय त्रासदी आई है उसमें भाजपा वर्तमान सरकार को आर्थिक संकट में डालने का काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इस त्रासदी से भी उभरकर आएगें। और सरकार को अपने किए गए वादों से हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। सरकार ने जो फैसले किए चाहे वह OPS का फैसला हो या अन्य फैसले हो। मैं तो यह कहूंगा कि यहां बेवजह हर एक इश्यू पे इश्यू बनाना जैसे अभी नेवा के ऊपर भी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कहा गया कि यहां पर

19.03.2026/1640 /AT/AS/02

सप्लीमेंट्री बजट यहां नहीं रखा गया, खुला नहीं। यह ऐसी बात है जैसे एक व्यक्ति गाड़ी लेकर चला हुआ है और उसके पीछे दूसरा व्यक्ति गाड़ी लेकर चला आगे वाले ने इंडिकेटर दिया और मुड़ने की कोशिश की लेकिन पीछे वाले ने गाड़ी ठोक दी। जब दोनों गाड़ी से बाहर आए और बहस करने लगे, तो वहां पुलिस और ट्रैफिक सिग्नल दोनों मौजूद थे। यह साफ दिख रहा था कि इंडिकेटर दिया गया था लेकिन पीछे वाले व्यक्ति ने कहा इंडिकेटर तो दिया पर हाथ नहीं दिया। आज जब गाड़ी में इंडिकेटर है तो हाथ निकालने की जरूरत क्या है? उसी तरह, जब नेवा के माध्यम से डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में उपलब्ध है तो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों है? मैं यह कहना चाहता हूं कि अनावश्यक मुद्दों से हमारी

विधान सभा का समय खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहां हमारे छोटे भाई करसोग से विधायक माननीय दीप राज जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी जादूगर हैं। मैंने कहा जादूगर तो हैं और वह कहने लगे कि जादूगर है लेकिन थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में जो उन्होंने बात कही मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने प्राकृतिक खेती के बारे में विजन रखा तो उसे जमीन पर आने के लिए एक साल लगेगा। जब एक साल होगा तो किसान उस प्राकृतिक खेती की हल्दी को

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1645/केएस/डीसी/1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी ---

उगाएंगे और एक साल के बाद जो प्रोक्योरमेंट होगी, उसी की खरीद सरकार करेगी। फसल एक साल में तैयार होती है। यह फसल दो या तीन महीनों में तैयार होने वाली नहीं है। जहां तक आपने जादूगर की बात कही तो जो चौदहवीं विधान सभा में अभी तक हुआ, (***)अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में जो त्रासदी हुई, मैं उस समय विधायक नहीं था परंतु फिर भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के 36 परिवारों को टोटल लॉस का कंपनसेशन मौजूदा सरकार ने दिया। वर्ष 2025 की त्रासदी आई, सबसे ज्यादा नुकसान उसमें नालागढ़ को हुआ और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री का 68+14= 82 परिवारों को हमने टोटल लॉस की श्रेणी में लिया और लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपये दिए गए, 4-4 लाख रुपये की राशि दी गई। लगभग 213 परिवार हैं जो आंशिक रूप से डैमेज हुए जिन्हें एक से डेढ़ लाख रुपये तक की राशि मिलनी है। वह भी लिस्ट आउट हो चुकी है और जल्दी ही उनके अकाउंट में वह राशि डाल दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इलीगल माइनिंग की बात की गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में वहां पर इलीगल माइनिंग नहीं हुआ करती थी। जिन लोगों ने वहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़े उनको आज माइनिंग माफिया कहा जाता है और यह रिकॉर्ड में है।

उसका नुकसान क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ा है जिसकी वजह से आज वे लोग घर पर बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैक्सिमम केसिज़ इलीगल माइनिंग के रजिस्टर हुए, मैक्सिमम चालान रजिस्टर हुए जो कि रिकॉर्ड है और वह कोई भी निकाल सकता है। वर्ष 2012 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र में आर0टी0ओ0 ऑफिस खुला, सब तहसील पंजेरा खुली, तहसील रामशहर खुली, रामशहर का कॉलेज खुला, पी0एच0सी0 से सी0एच0सी0 रामशहर हुआ। ऐसे कई और भी संस्थान खुले परंतु वर्ष 2017 से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक रुपया भी इन

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

19.03.2026/1645/केएस/डीसी/2

संस्थानों के लिए पांच सालों में नहीं दिया। मैं मौजूदा सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी अभी 22 तारीख़ को उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। सब तहसील पंजेरा, तहसील रामशहर और राम शहर कॉलेज के लिए मुख्य मंत्री जी ने 13 करोड़ रुपये दिए और इन तीनों संस्थानों का लगभग 70 से 80 परसेंट काम पूरा हो गया है। इनकी सरकार के समय पांच सालों में एक रुपया बजट भी इन संस्थाओं के लिए नहीं दिया गया। आज वे संस्थान बनकर जल्दी ही जनता को समर्पित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारा विधान सभा क्षेत्र मैदानी इलाका है, किसान किसानी से जुड़ा है। वर्ष 2012 से 2017 तक की कांग्रेस सरकार के समय 68 सिंचाई के बोर किए गए। उस वक्त के मुख्य मंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने उनका शिलान्यास किया था। इसके अतिरिक्त 10 चैक डैम्ज़ का शिलान्यास किया, 16 पीने के पानी की स्कीमों का उन्होंने शिलान्यास किया लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में एक भी स्कीम को नहीं चलाया गया। मैं उप-मुख्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि 13 जुलाई को मैं विधायक बना और 14 दिसम्बर, 2024 को

माननीय उप-मुख्य मंत्री द्वारा 12 सिंचाई की स्कीमों का उद्घाटन हुआ, 6 वाटर सप्लाई की स्कीमों का उद्घाटन हुआ और उसके अगले दिन मुख्य मंत्री जी द्वारा 8 इरिगेशन और चार सिंचाई की स्कीमों का उद्घाटन किया गया। अभी इसी महीने लगभग 15 सिंचाई की स्कीमों और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

19.03.2026/1650/av/dc/1

श्री हरदीप सिंह बावा------जारी

1 पेयजल स्कीम का उद्घाटन किया जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये उद्घाटन पिछले पांच वर्षों में भी हो सकते थे परंतु उस समय किसी भी स्कीम का उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन आज ये स्कीम्ज लोगों को समर्पित की जा चुकी हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुए उसके अंतर्गत 1227 करोड़ रुपये की अदायगी आज भी नहीं की गई है जिसका नुकसान प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र सहित मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे नाबार्ड के अंतर्गत 11 ट्यूबवैल मिले हैं जिनका शिलान्यास मुख्य मंत्री जी जल्दी ही करेंगे।

यहां पर श्री नैना देवीजी से विधायक श्री रणधीर शर्मा जी एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के बारे में बोल रहे थे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं हुआ, एस0डी0आर0एफ0 और एन0डी0आर0एफ0 हमारा हक है जोकि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और इसीलिए हमें यह फण्ड दिया गया।

हमारे युवा काँग्रेस साथी जिन्होंने दिल्ली के अंदर नग्न होकर प्रोटैस्ट किया, वह उनका अधिकार था। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें यातनाएं दी गईं और उन्हें अरेस्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिए बिना दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग करने की कोशिश की, उसके ऊपर जो माननीय मुख्य मंत्री ने कार्रवाई की मैं

उसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए आपकी सराहना भी करता हूं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी व्यक्ति ...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी, हिमाचल का हो या किसी और राज्य का हो उसके लिए लोकल पुलिस स्टेशन को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी होता है। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना जरूरी होता है।

आर0डी0जी0 का जो आने वाले समय में असर होगा, मैं समझता हूं कि वह हम सबको बराबर झेलने को मिलेगा। उसमें चाहे हम हैं या प्रतिपक्ष के विधायक हैं, इसके कारण हम सभी के निर्वाचन क्षेत्रों का कॉलैक्टिव नुकसान हो रहा है। आर0डी0जी0

19.03.2026/1650/av/dc/2

और जी0एस0टी0 कम्पनसेशन के ऊपर आपका स्टेण्ड क्लीयर नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें माननीय मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में दिल्ली जाने की बात कही वहीं से हिमाचल प्रदेश की जनता को आपके स्टेण्ड के बारे में क्लीयर हुआ।

यहां पर टोल टैक्स की बात भी हुई और वह मुद्दा मैंने खुद जीरो आवर के माध्यम से उठाया है। मैंने सरकार से आग्रह किया क्योंकि मैं मैदानी बोर्डर एरिया से विधायक हूं। यह मुद्दा मेरे साथ और विधायकों ने भी उठाया परंतु इसकी जड़ कहां से शुरू हुई? मैं बताना चाहता हूं कि यह टोल टैक्स/एंट्री टैक्स भाजपा की श्री प्रेम कुमार धूमल जी की नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2001-02 में लगाया था।

मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री टोल टैक्स के विषय पर बात अवश्य करेंगे और इस संदर्भ में पंजाब सरकार के मुख्य मंत्री से भी बात करेंगे ताकि वे भी किसी रियेक्शन में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय नालागढ़।

19.03.2026/1650/av/dc/3

Speaker : Now Hon'ble Chief Minister wants to intervene to clarify a situation.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब अनुपूरक बजट पास हो रहा था तो माननीय नेता प्रतिपक्ष अंदर थे और तब इन्होंने इसको देखा नहीं तथा बाद में कहा कि प्रदेश का बजट 98,000 करोड़ रुपये कैसे हो गया। आप तो खुद वित्त मंत्री रहे हैं और आप सब कुछ जानते भी हैं। फिर आप बोलते हैं कि ज्ञान के भण्डार आपके पास ही हैं। ...(व्यवधान) मैं ज्ञान के भण्डार की बात नहीं कर रहा हूं अपितु तथ्यों की बात कर रहा हूं। कानूनी प्रावधान है कि अनुपूरक बजट को विधान सभा में रखना पड़ता है और उसमें हर चीज का व्याख्यान किया जाता है।

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1655/टी0सी0वी0/एच0के0-1

मुख्य मंत्री ... जारी

अध्यक्ष महोदय, ने सबसे पूछा कि माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं? लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने चर्चा में भाग नहीं लिया और उसके बाद यह अनुपूरक बजट पास हुआ। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि आपने अनुपूरक बजट पढ़ा होगा लेकिन आप बीच में न बोलें। शायद आपको किसी पत्रकार ने बोल दिया होगा कि यह अनुपूरक बजट कैसे पास हो गया। आप पत्रकारों की बातें थोड़ी कम सुना करें तो अच्छा रहेगा। मैं 40000 करोड़ रुपये की बात बताना चाहता हूं। जब हमारी आर0डी0जी0 खत्म हुई तो सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता पर कोई कष्ट नहीं आना चाहिए और उसके लिए तरीका ढूंढा गया। इसमें हमें एक तरीका वेज एंड मीन्स का नजर आया। वित्त मंत्री जी जानते हैं, वेज एंड मीन्स के बाद ओवरड्राफ्ट होता है यानी जिस तरह एक लिमिट होती है, उस लिमिट को एक हफ्ते के लिए लिया जाता है उसके बाद उसे वापस किया जाता है। हम वेज एंड मीन्स में गए फिर ओवरड्राफ्ट में गए। उसके एक दिन बाद, दो दिन बाद, जैसे

ही हमें अपनी रिसिप्ट आती रही हमने 26000 और 27000 करोड़ रुपये जो लिया था उसको वापस भी किया ।

अभी जो हमने आपको सप्लीमेंट्री बजट में जो प्रक्रिया दिखाई है उसके तहत यह जो सारा पैसा लिया है, वह हमने दिखाया। हमने एक्सपेंडिचर किस-किस चीज में किया यह भी दिखाया। वर्ष 2026-27 के बजट में जो हमारे पास रिसिप्ट आती है उसको दर्शाया जाता है कि हमारे पास इतना टोटल पैसा आया। इस तरह से हमने 26000, 27000 करोड़ रुपये वेज एंड मीन्स के तहत लिए गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब 7 दिन में हमने ट्रेजरी को सैटल करने की बात की थी, उस समय हमने कहा था कि 8 तारीख को सैलरी मिलेगी तो बड़ा शोर मचा था लेकिन इस बार इस लोन को लेने के लिए भी हम वेज एंड मीन्स में गए और 34000 करोड़ रुपये का हमने इंटरेस्ट पे किया। जब हम वेज एंड मीन्स में होते हैं तो लगभग 5.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट दिया जाता है और जब ओवरड्राफ्ट में चले जाते हैं तो लगभग 10.5 प्रतिशत का इंटरेस्ट देना पड़ता है।

19.03.2026/1655/टी0सी0वी0/एच0के0-2

मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट सिर्फ वही होता है जो प्रस्तुत किया जाता है। उस बजट के जो आंकड़े होते हैं, उसकी जो रिसिप्ट आती है, वह हमेशा से एक प्रक्रिया के तहत दिखाई जाती है। 98000 करोड़ रुपये का कोई बजट नहीं है अगर इतना बड़ा बजट होता तो प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाता। आपकी जो इंस्टॉलमेंट पैंडिंग है वह भी मिल जाती। इसलिए हमने लोन लिया और उस लोन को उसी दिन या अगले दिन वापस कर दिया।

19.03.2026/1655/टी0सी0वी0/एच0के0-3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इसका एक पार्ट थोड़ा एक्सप्लेन किया लेकिन हमारी बेसिक बात यह थी कि जब सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया गया,

उसकी कॉपी हमें उपलब्ध नहीं हुई, न हमें मिली, न मीडिया को मिली और न ही डाउनलोड हो पाई। हमने यह मानकर चले कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे होंगे। ...(व्यवधान) लेकिन ऑनलाइन ले करने के बाद होता है, पहले नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसी माननीय सदन में मैंने एक बार नहीं, अनेक बार सप्लीमेंट्री बजट को पूरा पढ़कर भी सुनाया है, व्यवस्था यह भी रही है। आपने पढ़कर नहीं सुनाया, अगर पढ़कर सुनाया होता तो हमें डॉक्यूमैंट की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंट से फिगर्स का पता चलता और हमें जानकारी मिल जाती। इसके साथ ही मीडिया को भी जानकारी मिल जाती यानी हम सबको इसके बारे में जानकारी मिल जाती। हमारे कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी इंक्रीज है, आपने कहा कि वेज एंड मीन्स के अंतर्गत लिया क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और अगर मार्केट से लोन लिया जाता तो स्वाभाविक रूप से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता, यह बात समझ में आती है। जो भी फाइनेंस से संबंधित है वह समझ सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि या तो हमें पहले बता दिया जाता कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो क्या आप चर्चा करना चाहते हैं या नहीं, जब डॉक्यूमेंट ही उपलब्ध नहीं था तो we were not knowing एक्सैक्टली इसमें क्या है? हम यह मानकर चल रहे थे कि अधिकतम 25 से 28 प्रतिशत तक इंक्रीज होगी जो आमतौर पर होती है, लेकिन यह इंक्रीज 70 प्रतिशत तक चली गई ।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1700/NS-HK/1

श्री जय राम ठाकुर------जारी

यह हमारे लिए चिंता का विषय तब हुआ जब हमें मालूम पड़ा कि यह बहुत बड़ा इन्क्रीज है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष आप एक मिनट बैठे, मैं सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा लेता हूं। सत्ता पक्ष से 2 माननीय सदस्य और विपक्ष से 5 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और इसके लिए 1 घंटा का समय लगेगा तथा अभी आपने भी बोलना है।

(अब इस माननीय सदन की बैठक सायं 06.30 बजे तक बढ़ाई जाती है।)

श्री जय राम ठाकुर : जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी अब्सैंस में बात कही तो उन्होंने ने भी इस पर हैरानी जाहिर की कि मुझे लगता है कि यह फिगर गलता है this is part of the record. उन्होंने भी यहां ऐसा बोला है। जब सबको यह लग रहा था तो हमें लगा कि यह डॉक्यूमैंट पहले देना चाहिए था और ऐसी परम्परा भी रही है, नियम भी रहे हैं या तो फिर आप इसको पढ़ कर सुनाते तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान वहीं हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बाद में हमने इस इश्यू को रेज किया। सरकार का सप्लीमेंटरी बजट तो पारित होना ही था क्योंकि मेजोरिटी आपके पास है। हम विरोध करते तो भी पास होना था। हम सिर्फ चर्चा करके अपनी बात कहते तो भी पास होना था। मुझे लगता है कि इस परम्परा को हटाना नहीं चाहिए था। आपको इसे पढ़ कर सुनाना चाहिए था या यह डॉक्यूमैंट सबको उपलब्ध करवाना चाहिए था, तब इसमें पारदर्शिता रहती। भरोसा कैसे टूटता है? जब आप चीजों को छिपाने की कोशिश करते हैं तब भरोसा टूटता है। जब भरोसा टूटता है तो फिर प्रश्न खड़े होते हैं। हमारी बात सिर्फ इतनी है। जहां तक आप Fiscal Prudence Or Fiscal Discipline की बात कहते हैं तो ये सारी चीजें धरी की धरी रह गईं। मैं देख रहा हूं कि लगभग 3.98 प्रतिशत आपके पास विकास कार्यों के लिए पैसा है जबकि आज से पहले बजट का 8 से 10 प्रतिशत भाग विकास कार्यों पर खर्च होता था और यह आपका 4 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। यह प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। जब यह फिगर आई है हम तो तब बोल रहे हैं। हमें जब डॉक्यूमैंट उपलब्ध हुआ हम तो तब बोल रहे हैं। हम जब आपकी अब्सैंस में बोलने के लिए खड़े हुए तब बोलते कि आप इस पर बोल ही नहीं सकते। ये वे बात कर रहे थे क्योंकि अब यह पारित हो गया और अब इस पर चर्चा नहीं हो सकती।

19-3-2026/1700/NS-HK/2

लोकतंत्र में चर्चा का हमेशा अभिनंदन व स्वागत होना चाहिए। गलती आपसे हुई है या हमसे हुई है उसको आने वाले समय में कहां ठीक किया जा सकता है, यह देखना जरूरी है। इससे कम-से-कम एक चीज तो तय हुई है कि आने वाले समय में हम इन चीजों को तय कर सकते हैं कि डॉक्यूमैंट पहले देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बजट

प्रस्तुत करते समय भाषण पढ़ कर चले जाएंगे और हमें डॉक्यूमैंट नहीं मिलेगा, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अभी तक हम टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ़ नहीं हुए हैं कि हम सब विषयों को कंप्यूटर पर देख सकते हैं। यह ठीक है कि यह तकनीक गुजारे लायक चल रही है और हम इस माननीय सदन में लैपटोप में प्रश्न और बिजनैस को देख सकते हैं। इसके सिवाए तो जब अध्यक्ष महोदय का आदेश होता है तब जा कर प्रश्न डाउनलोड होते हैं। इसमें सूचना आती है कि पेपर डाउनलोड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस पर अवलेबल होगा। जो ऑलरेडी इस पर है वह तो होगा ही लेकिन बिजनैस डिटेल में तब डाउनलोड होता है जब प्रोसीडिंग या प्रोसैस शुरू होती है। कुल मिला करके हमारा प्रश्न व्यवस्था से संबंधित था और हमने कोई गलत बात नहीं की। हमने प्रश्न चाहे पहले उठाया होता तो भी उसका सम्मान होना चाहिए और अगर हमने प्रश्न बाद में उठाया तो भी उसका सम्मान होना चाहिए। यह त्रुटि हुई है और इसको जानबूझ कर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा आरोप है। इसको छिपाना नहीं चाहिए, इसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। कागज कहीं नहीं छिपता, न हम छिपा पाए और न ही आप छिपा पाएंगे। आप कागज को कुछ मिनट तक ही छिपा सकते हैं। आप कुछ मिनटों तक ही कागज छिपा पाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं छिपा पाए। अब तो सबको मालूम हो गया। इसलिए इसका कुछ फायदा नहीं है। आप खुले मन से काम करें और पारदर्शिता रखें, यह बहुत आवश्यक है।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

19.03.2026/1705/RKS/YK-1

श्री जय राम ठाकुर जारी....

अध्यक्ष महोदय, नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र से हमारे माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी ने (***) शब्द का इस्तेमाल किया है। जो (***) शब्द कहा गया है that is part of the record. You should removed it. ...(व्यवधान) इन्होंने (***) शब्द बोला है। इन्होंने कहा कि जादूगर हैं। ...(व्यवधान) इन्होंने विपक्ष को (***) कहा है।

Speaker : I will check the record and in any case अगर (***) शब्द का उपयोग हुआ होगा तो उसे किस संदर्भ में कहा गया है, उसे कार्यवाही में रखना है या नहीं इसका निर्णय मैं करूंगा, already a ruling has come.

श्री जय राम ठाकुर : आप इस शब्द को रिकॉर्ड से हटाएं अन्यथा जब हम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। धन्यवाद।

Speaker : I will check the record. माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपने सप्लीमेंट्री बजट को पढा क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय आपने तो खुद विपक्ष को चर्चा के लिए कहा था। ये स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं और ये किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं हैं। आप सब चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि अब सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत होना है। आप सत्तापक्ष और विपक्ष के बारे में भी जानते हैं। जब मैं यहां उपस्थित नहीं था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा उसमें मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह एक प्रक्रिया है। मुझसे भी पत्रकार बंधुओं ने 40 हजार करोड़ रुपये के बारे में पूछा था। आप तो स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं इसलिए आपको पता है कि किस प्रक्रिया से हमको पैसा आएगा। जब मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करूंगा तो उसमें पिछले वर्ष की प्राप्तियां भी प्रदर्शित होंगी। दूसरा, मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने दल के विधायकों को भी समझाएं। जो विधायक पहली बार आए हैं मुझे लगता है उन्हें दूसरी बार विधान सभा में आने की उम्मीद नहीं है। ...(व्यवधान) आप चिंता मत करिए। अगर श्री हरदीप सिंह बावा ने (***) शब्द कहा है तो उधर से भी इन्होंने कुछ गलत शब्द कहे हैं। इन्हें सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सही शब्दों का उपयोग करना चाहिए।

19.03.2026/1705/RKS/YK-2

Speaker : I will check the record, if there is any undesirable word, the same will be removed from the proceedings.

मुख्य मंत्री : आप निश्चिंत रहिए, आप गुस्सा मत हो। आपको सोच-समझकर तथ्य पर बोलना चाहिए। आपने हल्दी खरीदने की बात कही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हल्दी कोई रिजर्वेशन से खरीदी जाती है? जो किसान आर्गेनिक हल्दी पैदा करेंगे उसे हिमाचल प्रदेश सरकार खरीदेगी। गेहूं और दूध को भी हमारी सरकार खरीदेगी। धन्यवाद।

19.03.2026/1705/RKS/YK-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार चर्चा में भाग लेंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी, 2026 को जो राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढ़ा गया उस पर चर्चा करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी यहां से चले गए हैं, मैं चाहूंगा कि वह मेरी बात सुन लें। यह बड़ी चिंता का विषय है कि जब 1 अगस्त, 2024 को समेज में फ्लड आया था तो उसमें 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस फ्लड में 33 लोग शिमला जिला से और 3 लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मरे थे। वहां पर ग्रीन गो कंपनी प्रोजैक्ट चलाती है। वहां के कामकाज का सारा कार्यभार शिमला जिला के उपायुक्त महोदय और एस0पी0 साहब के पास था। कुल्लू और बागा-सराहण में मैंने मुख्य मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी थी। मुख्य मंत्री जी ने विधायक प्राथमिकता की बैठक में यह कहा था कि 10 दिन के भीतर यह पैसा मिल जाएगा लेकिन अभी तक हमें एक रुपया भी नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्री पवन कुमार, श्रीमती नुरमा देवी, श्री प्रेमचंद, श्री हरदयाल, श्री चांदन सिंह , श्री सतपाल और श्री धर्मपाल जी के मकान आंशिक रूप से गिरे हैं। इनको इसका एक-एक लाख रुपये मुआवजा मिलना था लेकिन उन्हें यह राशि अभी तक नहीं मिली है। श्रीमती नेवता देवी, श्री वेद राम और श्री जिया राम को दो-दो लाख रुपये मिलने थे उन्हें भी यह राशि नहीं मिली है जबकि शिमला जिला के सब लोगों को कुछ पैसा मिल गया है। शिमला जिला के जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को सारा मुआवजा मिल गया है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1710/बी.एस./वाई.के.-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

आखिर जिला कुल्लू के आनी विधान सभा क्षेत्र से क्या दिक्कत है? मैं यह पूछना चाहता हूं। अभी सी0एम0 साहब बोलकर बाहर निकले हैं। अब दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, यह जनता तय करेगी कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। सिर्फ हवाई बातें करने से चीजें नहीं होंगी। अभी कोई बोल रहे थे कि मुख्य मंत्री जी किसान बेटे हैं। परंतु आज किसानों और बागवानों के क्या हालत हैं, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की कि दूध के साथ हम अर्थव्यवस्था को बड़ा मजबूत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि अभी 31 मार्च से पहले हमारे विधान सभा और दूसरी जगह मिल्क फेड के द्वारा कैंप करवाए जा रहे हैं कि गाय का दूध कैसे बेहतर हो।

इस बारे में मेरा प्रश्न सुबह भी लगा था और प्रश्न का जवाब भी मुझे आया है। लोगों को जनवरी और फरवरी के पैसे नहीं मिले हैं। लोगों के पास चोकर खरीदने के लिए पैसा नहीं है और इनके सपने में प्रतिदिन शाम को आता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और इनकी मंशा क्या है? हम भी विधायक बनकर आए हैं। हमें भी एक-डेढ़ लाख लोगों ने चुनकर भेजा है। चाहे आदरणीय दीप राज जी हैं या मैं आनी से विधायक हूं और भी बहुत सारे नये विधायक चुनकर आए हैं। परंतु नये लोगों से दिक्कत क्या है? हम यहां अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को उठा रहे हैं और जो कार्य वहां नहीं हो रहे हैं, जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, उसके बारे में हम यहां कह रहे हैं। मेरे वहां पर लोगों को जनवरी-फरवरी के पैसे नहीं मिले हैं। मार्च खत्म होने वाला है, परंतु पैसा नहीं मिला है। आज मिथर के क्षेत्र में कैंप था और दो दिन पहले आनी में था। उससे पहले निरमंड में था। कैंपों में डॉक्टर और स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं कि गाय का दूध ऐसा होना चाहिए, यहां पर सिंधी नस्ल होनी चाहिए, यहां पर जर्सी होनी चाहिए, परंतु कौन उस जर्सी नस्ल को देगा?

मैं आपको वेटरनरी हॉस्पिटलों डिटेल बता देता हूं कि मेरे क्षेत्र मे क्या हाल है? निरमंड, कसौली में एक डॉक्टर है जिसके पास नौ पंचायत हैं। सरगा में दो पोस्टें हैं दोनों खाली हैं। बडारी में दो पोस्ट हैं, दोनों खाली हैं। खरगा में दो पोस्ट हैं, एक भरी है, एक खाली है। चाटी में एक पोस्ट खाली है। कसौली में एक खाली है। मजडां का वेटरनरी हॉस्पिटल खोला था वह बंद कर दिया गया।

19.03.2025/1710/बी.एस./वाई.के.-2

यह मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं जिसको मजबूत करने की बात आप कर रहे हैं। आनी में खाणाग बंद है, टिहणी खाली है। बिशावल खाली है। कनेरी खाली है। टीम खाली है। हरिपुर खाली है और ढहर खाली है। जब गाय नए दूध होती है, तो उसको इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन लगाने वाला कोई फार्मासिस्ट नहीं है और डॉक्टर नहीं है। आनी के क्षेत्र में जो डिटेल आई है, सरकारी उपक्रम द्वारा 28,000 लीटर दूध आता है और 5000 लीटर प्राइवेट में आता है। हम सबसे ज्यादा दूध आउटर सिराज भेज रहे हैं और आउटर सिराज से ही मिल्कफैड के चेयरमैन हैं। वे यह तो बता रहे हैं कि आपने दूध अच्छा देना है, पतला नहीं देना है। वैज्ञानिक रूप से यह है कि अभी आने वाले समय में बरसात होनी है, हरा घास लगता है। हम लोगों के भी पशु हैं। जब आप हरा घास खिलाएंगे तो जिस तरह के डिग्री और एस0एन0एफ0 के बारे में यहां बात कर रहे हैं, वह डिग्री और एस0एन0एफ0 नहीं आती है।

आप क्या चाहते हैं, आप जगह-जगह भाषण दे रहे हैं कि अच्छा दूध दो। आप क्या बोलना चाहता हैं कि गांव के लोग उसमें पानी डाल रहे हैं या गांव के लोग करप्शन कर रहे हैं? जो महिला, माता सुबह 4:00 बजे उठकर गाय की सेवा करती है और रात के 8-9 बजे तक गाय के साथ ही रहती है उसके ऊपर आप लोग इस तरीके से गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा दूध नहीं दे रहे। आप दूध के अंदर गलतियां कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का दूध नहीं बिकेगा। मुझे यहां पर बताया जाए। मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमारे आनी में आकर मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष जी ने बोला है कि एक किसान का 20 लीटर से

ज्यादा दूध नहीं लिया जाएगा जो दूध बेचने वाला है। जबकि लोग दूध के अंदर पहले से कम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम आ रही हैं। उसके ऊपर हम गाय खरीद रहे हैं, डेयरी खोल रहे हैं। आप मुझे स्पष्ट करें कि 20 लीटर से ज्यादा दूध खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? वह सिर्फ मिल्क फेडरेशन का बयान है या फिर सरकार की सोची-समझी चाल है। यह आप हमें इस हाउस के अंदर बताएं ताकि किसान वहां पर दिक्कत में न रहे, परेशान न हो क्योंकि बहुत सारी आर्थिक स्थिति उनकी दूध से जुड़ी हई है। उनके बच्चे शिमला में पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, वे बच्चे दूध के ऊपर भी निर्भर हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1715/डीटी/एजी-1

श्री लोकेन्दर कुमार... जारी

मैं दोबारा से किसानों की समस्या के ऊपर आता हूं। मेरा विधान सभा प्रश्न भी लगा था। माननीय मंत्री जी हमने सेब का एक-एक दाना कॉलैक्शन सैंटर पर पहुंचाया। आनी में HPMC के द्वारा 84,054 हज़ार बैग खरीदे गए और मुझे लगता है कि यह भी झूठा आंकड़ा दिया होगा। इनमें से 45,553 बैग सड़ गए थे। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं बरसात के समय उधर जा रहा था तो मुझे लगता है कि हर जगह इतने बैग कहीं नहीं पहुंचे होंगे। आप किस हिसाब से बोल रहे हैं कि हमारे पास सेब पहुंचा है? किसान पर्चियां लेकर जगह-जगह पर जा रहे हैं कि उन्हें HPMC द्वारा क्रय किए गए सेबों का पैसा दे दिया जाए या फिर उन्हें जूस ही पिला दो। उन्हें अपनी फसल का कोई दाम नहीं मिल रहा है। हम गांव की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पिछले आठ-आठ, नौ-नौ महीनों से बसों के रूट बंद हो गए हैं। अभी यहां माननीय मंत्री जी उपस्थित नहीं है। जब हम नये लोग बोलने के लिए खड़े होते हैं तो हमारे वरिष्ठ सदस्य यहां से उठना शुरू कर देते हैं। या तो उनको हमारे क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है या उनके लिए कुछ लिमिटिड सीटें ऐसी हैं कि हम उनका ही जवाब देंगे। आप हमें स्पष्ट करें कि मेरे क्षेत्र में डुघा-शियान जगह में बस नहीं चल रही है। करसोग में जो नावीधार बस जाती है, वह नहीं चल रही है। बांशा मुश्किल से छह- सात महीने बाद चल रही है। लेकिन कल से फिर उस बस को बंद कर दिया गया।

बीसर के लिए जो बस चली थी उसे फिर से बंद कर दिया गया। आनी की त्राला बस जो सवा 12:00 बजे जाती थी वह भी बंद है। पनेयो बस बंद है। आनी- रामपुर साढ़े 12:00 बजे बस जाती है, वह भी बंद है। पोखरी बस बंद है। रामपुर- छतरी- आनी बस जो रामपुर-दलास बाया बागी जाती है वह भी बंद है। बागीपुल से ठारला पुल बस भी बंद है। तुनड़ रोड की बस बंद है। इससे ज्यादा और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। सड़कें अभी तक बड़ी मुश्किल से खोली गई हैं। जैसे यहां पर श्री दीप राज जी ने बोला कि पैसा दो, टोकन लो, पैसा दो पेमेंट लो। यहां पर मंत्री जी बैठे हैं। ठेकेदारों ने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। PDNA के पैसे से पूरे प्रदेश के रोडों को खोला गया परंतु आज ठेकेदार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने ठेकेदारों के लिए काम किया। क्या ये ठेकेदार कहीं बाहर से आए

19.03.2026/1715/डीटी/एजी-2

हैं? वे मेहनत करके सड़कें खोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको पेमंट नहीं मिल रही है। जब पैसा दे रहे हैं तो उसके बाद उनको टोकन मिल रहे हैं। यह स्थिति है यहां पर और फिर आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। हम बता आपको बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहां-कहां हो रहा है। हम आपको पंचायतों के नाम गिना देंगे, आप वहां पर कार्रवाई कीजिए। मेरी बहना पंचायत में टिप्पर की जगर जे0सी0बी0 का नम्बर लगा दिया गया।

(माननीय सभापति श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए।)

वहां पर पेनल्टी लगाई गई लेकिन प्रधान उस पेनल्टी को को नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से उनको किसी का आशीर्वाद मिल रहा है। वे मुख्य मंत्री जी के खास बनकर फिरते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत सारी और भी दिक्कतें हैं। ये शिक्षा की बड़ी बातें कर रहे हैं। आनी में सिर्फ दो ही स्कूल CBSE हुए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। एक आनी और दूसरा बागाशरान स्कूल CBSE हुआ है जहां मुख्य मंत्री साहब गए हैं। भौगोलिक रूप से मेरा बहुत बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक और पंचायत बढ़ गई है। जिन लोगों को पंचायत की जरूरत है और रझेड़ी पंचायत से जो एक पंचायत अलग होनी थी उसको अलग नहीं किया गया।

उन लोगों का पंचायत की जरूरत थी। जहां पर किसी सगे आदमी ने बोला वह पंचायत अलग कर दी। हम उसका भी स्वागत करते हैं कि वह पंचायत अलग कर दी यह अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को 60-60, 70-70 किलोमीटर फेरा लगाकर आना पड़ रहा है उनकी पंचायत को भी अलग करना चाहिए था। CBSE School आनी और बागाशरान में बनाये गए। उर्चू में CBSE School इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि हम दोस्त हैं, हमने अच्छी जगह सरकार को पहुंचाया है, उनके किसी रिश्तेदार का वहां पर Private School है। अगर वहां पर CBSE स्कूल बन जाएगा तो वहां प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगा। वहां किस तरीके से भाई भतीजावाद हो रहा है। निर्मंड का मेन स्कूल काफी पुराना स्कूल है लेकिन उसको CBSE नहीं बनाया गया। वहां पर बच्चों की बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। हमारा आरसू का स्कूल 200 साल पुराना है। मंत्री जी वहां पर एक कार्यक्रम में गए थे। उस स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसको CBSE नहीं किया। दलास का स्कूल भी बहुत पुरान है जो आनी Block के अंदर आता है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

19.03.2026/1720/ए.जी.-एन.जी./1

श्री लोकेन्दर कुमार..... जारी

आनी ब्लॉक के अंदर आता है। इसी प्रकार कुंगस, लगोटी व निथर का स्कूल है और निथर के स्कूल में तो पूर्व विधायक श्री ईश्वर दास जी भी पढ़ा करते थे। इन स्कूलों को नहीं बनाया गया बल्कि जो चहेते लोगों ने बोला उन स्कूलों को बनाया गया। मैं यहां से मांग करता हूं कि मैंने जिन स्कूलों के नाम लिए हैं जैसे लगोटी, डीगेड़ व खुन्न का स्कूल है, इन स्कूलों को भी सी0बी0एस0ई0 बनाया जाए ताकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो पैसे दे रहे हैं, वे बच्चे भी इन स्कूलों की ओर जाएं और वहां पर पढ़ाई-लिखाई करें। यह नहीं होना चाहिए कि वहां पर जो सरकार ने अपने नुमाइंदे बनाए हुए हैं, हो सकता है कि वे अजीज मित्र हों, अच्छी बात है, परंतु यह नहीं होना चाहिए कि वे

जो बोल रहे हैं, उन्हीं के अनुसार चलें। जिन विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी भी बातों को सुना जाए और यह मैं इस मंच से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं जब से विधायक बना हूं तब से लगातार बोल रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं। वहां पर चिट्टा और भांग पैर पसार चुका है। वहां पर दिन-प्रतिदिन हालात खराब होते जा रहे हैं। वहां पर 25-30 लड़के जोकि 21 से 25 साल के थे, वे ओवरडोज के कारण मर गए हैं। हमने कहा है कि वहां पर पुलिस फोर्स बढ़ाई जाए लेकिन अभी तक नहीं बढ़ी। वहां पर ट्रैफिक की स्थिति दयनीय है और अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। मैंने बोला था कि हमें अलग से ट्रैफिक विंग दिया जाए लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसके बाद भी सरकार के लोग किसके लिए और कौन-सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? मैं जिस विधान सभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वह एक आरक्षित विधान सभा क्षेत्र है। मैं आनी विधान सभा क्षेत्र यानी के आउटर सिराज के लोगों की वजह से यहां पर खड़ा हूं और बोल रहा हूं। मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारा आउटर सिराज क्षेत्र बहुत खूबसूरत है और आउटर सिराज का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश की सरकार को चलाने में रहा है और आगे भी रहेगा।

19.03.2026/1720/ए.जी.-एन.जी./2

पूर्व की सरकारों ने भी बहुत सारे काम किए हैं पर वर्तमान सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। अभी मैं देख रहा था कि फायर के लिए कुछ दिया है शायद एक करोड़ रुपये दिए हैं लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर बोल रहे हैं कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो जो 250-300 किलोमीटर के विधान सभा क्षेत्र हैं, उनकी स्थिति को भी देखें। इस भावना से न आएं कि वहां पर विधायक बीजेपी का है तो इसे अगली बार बताते हैं। यह सब भूल जाएं क्योंकि यह सब जनता तय करेगी। यह मुख्य मंत्री तय नहीं करेंगे कि किस क्षेत्र से किस व्यक्ति को

जिताना है। मेरा कहना है कि बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए, उसमें चाहे भाजपा का विधायक हो, कांग्रेस पार्टी का हो या अन्य किसी दल का हो। मुझे लगता है कि जनता ने उसको चुनकर भेजा है और हम यहां पर जनता की आवाज को ही उठाते हैं। मेरा मानना है कि जनता का काम होना चाहिए और यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

सभापति महादेय, मैंने आज माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से बात की कि आनी और निरमंड, दोनों जगह एक्स-रे मशीन नहीं है।...(घण्टी)...

सभापति : माननीय सदस्य, वाइंड-अप कीजिए।

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, लोगों को एक्स-रे करवाने के लिए दूर-दूर जाना पड़ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी-से-जल्दी जो भी आपकी टेंडर प्रक्रिया है, उसे पूरा करें और वहां पर एक्स-रे प्लांट लगाया जाए ताकि लोगों के एक्स-रे वहीं हो सकें और उन्हें प्राइवेट जगहों पर न जाना पड़े।

सभापति महोदय, बाकी बहुत सारी बातें हैं, उनको हम बाद में कहेंगे। यहां पर हमारे सत्ता पक्ष के साथी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, कानून की, संविधान की।

19.03.2026/1720/ए.जी.-एन.जी./3

मैं कहना चाहता हूं कि मैंने विधान सभा में बात रखी कि जल शक्ति विभाग की ओर से आनी खड्ड की चैनेलाइजेशन के लिए 13 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाई जानी है। आनी बहुत बड़ा कस्बा बन गया है और वहां पर उस खड्ड के कारण दिक्कत है क्योंकि कभी भी बादल फट सकता है या अन्य कुछ भी हो सकता है इसलिए उस खड्ड की

चैनेलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन अभी तक वह डी0पी0आर0 आगे नहीं बढ़ पाई है। उसमें अनावश्यक ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि वहां के बागी पुल के लिए पैसा दे दिया है लेकिन केगस वालों को भी भी पैसा मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में बड़िंगचा का इलाका है और वहां से श्रीखंड की यात्रा शुरू होती है, वहां भी पैसा मिलना चाहिए। अभी तक वहां पर पैदल पुल नहीं लगे हैं। बच्चों को बरसात के समय में स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मुझे क्या मिला, (एक पत्र दिखाते हुए) मुझे यह नोटिस मिला है। कांग्रेस के लोग यह बातें कह रहे हैं कि आपने हमारे लोगों को अंदर किया और रोहड़ू से दिल्ली लेकर चले गए। मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 18 मार्च, 2015 का दिन था और पूरे प्रदेश के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जॉइंट मूवमेंट हुआ था। मैं भी उस छात्र आंदोलन में शामिल था। उस दिन इस विधान सभा के बाहर इतनी बुरी तरह से लाठीचार्ज हुआ था कि तीन महीने के लिए हम बैड पर रहे और दो महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री लोकेन्दर कुमार, कृपया वाइंड-अप कीजिए।

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें यहां पर बोलनी हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि जिस जगह से मैं यहां नुमाइंदा बनकर आया हूं तो मुझे डोमिनेट करने की कोशिश न करें। मुझे डराने की कोशिश

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1725/ए.पी. /ए.एस. -1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी .....

न करें। हमारे क्षेत्र को भी उसी नजरिये से देखा जाए जिस नजरिये से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को देखा जा रहा है। जिस नजरिये से कुल्लू, लाहौल-स्पिति, रामपुर और किन्नौर को देखा

जा रहा है, उसी नजरिये से मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी और आउटर सिराज को भी देखा जाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि यह अभिभाषण झूठ-मूठ का पुनिंदा है। यही मुझे कहना था। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

जय हिन्द, जय हिमाचल प्रदेश, जय आउटर सिराज।

सभापति : माननीय कृषि मंत्री महोदय।

कृषि मंत्री : सभापति महोदय, बड़े लंबे समय तक आनी विधान सभा क्षेत्र से श्री ईश्वर दास जी हमारे एम0एल0ए0 रहे हैं। आजकल माननीय श्री लोकेन्द्र जी वहां से एम0एल0ए0 हैं। ऐसी बात नहीं है कि आनी विधान सभा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि आनी और रामपुर साथ-साथ ही लगते हैं। माननीय श्री ईश्वर दास जी ने भी अपने समय में काफी काम किया है। इस सदन में माननीय श्री लोकेन्द्र जी ने जो दूध से संबंधित बात रखी है, **मैं आपको बता दूं कि दिनांक 31 जनवरी 2026 तक दूध के सारे भुगतान हमने कर दिये हैं। फरवरी और मार्च का भी अभी बहुत जल्द भुगतान कर दिया जाएगा और फिर भी अगर किसी समिति या कमेटी से कोई भुगतान रह जाता है तो आप मुझे इस बारे में अवगत करवा दें, हम बहुत जल्दी उसका पैसा आपको दे देंगे। धन्यवाद।**

19.03.2026/1725/ए.पी. /ए.एस. -2

सभापति : माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : आदरणीय सभापति महोदय, the younger Legislature has raised the problem of manpower and x-ray machine**. बहुत जल्द उनके विधान सभा क्षेत्र में एक्स-से मशीन पहुंच जाएगी और मैन पावर की कमी भी पूरी कर दी जाएगी।**

सभापति : माननीय कृषि मंत्री जी।

कृषि मंत्री : सभापति महोदय, 10 लीटर दूध प्रति व्यक्ति हमें दे सकता है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो भी हम कलेक्ट करेंगे और जहां तक आपने कहा कि दूध में पानी मिलाते हैं, यह बात सही नहीं है। **मैं आपको बता दूं कि अगर आप बरसात में दूध लेंगे तो उसमें फैट्स कम होंगे जबकि सर्दियों और गर्मियों में दूध के फैट्स ज्यादा होंगे। इसलिए दूध में फैट्स की माप करके ही हम लोगों को भुगतान करते हैं।** यह मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं।

19.03.2026/1725/ए.पी. /ए.एस. -3

सभापति : श्री विवेक शर्मा जी अब चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विवेक शर्मा : सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। काफी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है और सभी ने अपनी-अपनी बात रखी है। मगर मैं देख रहा हूं कि कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं जिसे विपक्ष भी मान रहा है कि कुछ बातें सही हैं। अब बात आती है कि हमारी जो ग्रांट बंद हुई है, उस पर भी सभी ने चर्चा की। इस ग्रांट की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई और संविधान में 275 (1) अनुच्छेद बनाया गया जिसके तहत सभी ऐसे छोटे राज्यों को सहायता दी जाती थी जिनके पास अपनी आय के स्रोत पर्याप्त नहीं थे। उन सभी राज्यों की सहायता के लिए इस ग्रांट को दिया जाता था। इसके माध्यम से राज्यों को सहयोग मिलता रहा और इस पर चर्चा भी होती रही। विपक्ष के लोग भी इस विषय पर बात कर रहे थे और उन्हें पहले से ही पता था कि यह ग्रांट बंद होगी। लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस बारे में यह भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस ग्रांट को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब हम दूसरे राज्यों के साथ तुलना करते है

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) जारी...

तो यह बात भी स्पष्ट होती है कि मुख्य मंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उन पर आप हमारा अधिकार दें, तो हम ग्रांट की बात करते ही नहीं है। बाकी राज्यों के पास अपने संसाधन हैं और वे अपने संसाधनों पर काम कर रहे हैं जिससे उन्हें आय भी हो रही है। लेकिन हमारा पहाड़ी राज्य है हमारे पास आय के साधन इतने अधिक नहीं हैं। फिर भी हमारा प्रदेश एक वेलफेयर स्टेट हैं। हम लोगों को यहां पर नौकरियां भी दे रहे हैं शिक्षा के संस्थान दूर-दराज के क्षेत्रों तक खुले हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में हर सुविधा दूर-दराज के क्षेत्रों तक दी जा रही है। जब यह ग्रांट दी जा रही थी उसी समय उन सभी कार्यों के लिए पैसा भी दिया जाता था। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या अधिक है उन्हें वेतन देना होता है और पेंशन भी देनी है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में पहले भी कई मुख्य मंत्री बने, लेकिन श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू पहले ऐसे मुख्य मंत्री जिन्होंने यह कहा कि वह हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 से वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने की सोच के तहत काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को यह बात पहले दिन से मंजूर नहीं हो रही है। उसी के तहत पक्ष इस बात में लगा है कि हमने आत्मनिर्भर बनना है और उस के तहत पोलिसी बनाई जा रही है। मगर विपक्ष इस बात के लिए लगा है कि ये जो बात कह रहे हैं कि इस बात को हमने पूरा नहीं होने देना है। उसके लिए कटौती कहां-कहां पर लग सकती है। वह चीज कैसे हो सकती है उसके ऊपर विपक्ष लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है।

आपने देखा कि वर्ष 2023 में त्रासदी आई और वर्ष 2024 में भी आई। इन दोनों त्रासदियों का आकलन केंद्र की टीमों ने खुद आकर किया और उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान का आकलन मंडी और पुरे हिमाचल में आई त्रासदी का किया है। आकलन के बाद जो पैसा केंद्र से मिलना था उसके लिए मुख्य मंत्री ने बार-बार कहा कि अगर जरूरत हो तो हम केंद्र में जाकर आपके नेतृत्व में भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद, आज तक हिमाचल प्रदेश से संबंधित सांसदों ने चाहे वे पहले विपक्ष में

थे या अब केंद्र में सत्ता पक्ष में हैं उन सभी ने इस मुद्दे को सही तरीके से नहीं रखा कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है। आज विपक्ष के नेता श्री जय राम जी, जो पूर्व मुख्य

19.03.2026/1730 /AT/AS /02

मंत्री थे और वह मंडी से संबंध रखते हैं, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उन्होंने भी इस बात को कभी नहीं रखा। ठीक कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने इस बात की बात रखी कि कभी ये बताएं कि जो केन्द्र में जाकर वह प्रदेश की बात करते हैं तो उन्होंने कब इस बात को कहा कि हमने किसके पास जाकर यह बात रखी की हिमाचल का जो हक है वह हमें मिलना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां इनकी करनी और कथनी में अंतर दिखाई देता है। या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें विरोध करना है या समर्थन करना है।

यह जो इतनी बड़ी किताब छापी गई है उसमें पहले 15 प्वाईंट स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं और ग्रांट का भी जिक्र किया गया है। कुल 130 प्वाईंटस हैं। जिसमें राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी सरकार ने यह काम किए। जब ये सरकार ने यह काम किए। अब बात आ रही है कि गलत टिप्पणियां लेकर ये सामने आते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। हम कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गारंटियों को पूरा कर रहे हैं। मगर यहां पर देखा जा रहा है कि गारंटियों को पूरा करने के लिए हिमाचल के लोगों के लिए हमने ओ0पी0एस0 (OPS) लागू करने की बात की और हम ओ0पी0एस0 के बात के ऊपर खड़े हैं, मगर यहां पर यह दबाव डाला जा रहा है कि आप ओ0पी0एस0 को बंद करें। अगर हमने दूध का मूल्य तय किया गया है तो उसके ऊपर हम वह दूध ले रहे हैं और अगर हम कच्ची हल्दी की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मगर यह बात कि कुछ नहीं हो रहा है। और धरातल पर जाकर आप देखेंगे तो धरातल में आज हर चीज सामने नजर आ रही है कि आज किसान और बागवान इस बात को लेकर खुश है कि कहीं-न-कहीं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अगर आज आप गांवों में जाकर देखेंगे, तो इसका प्रमाण साबित होता है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो वहां 32 वर्षों से लगातार भाजपा के विधायक थे। लेकिन पहली बार जब मुख्यमंत्री कुटलेहड़ के दौरे पर आए, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1735/केएस/डीसी/1

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) जारी ---

उन्होंने कुटलैहड़ के लोगों की जितनी भी मांगे थीं, एक दौरे में आ कर उनको पूरा किया। कुटलैहड़ के लोगों की 32 वर्षों की मांगों को पूरा किया गया। आज कुटलैहड़ को सब जज कोर्ट मिला, डी0एस0पी0 का कार्यालय मिला और इसी तरह से हमारी पी0एच0सीज़0 और सब सैंटर्ज़ को प्रोमोट किया गया। मुझे याद है कि भारतीय जनता पाटी की सरकार के समय जय राम जी दो बार कुटलैहड़ गए. मगर वहां टैंट लगे रह गए, ये वहां पर नहीं आए। 32 वर्षों में कुटलैहड़ में क्या विकास हुआ वह सामने नज़र आ रहा है। पहले जहां बंगाणा में एक भी डॉक्टर नहीं होता था आज वहां पर सभी डॉक्टर उपलब्ध हैं। नर्सिंग स्टाफ है। आदर्श हॉस्पिटल थानाकलां में भी आज सभी डॉक्टर्ज़ और नर्सिज़ हैं। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि ये यही बात करते हैं कि कहीं पर स्टाफ नहीं है या कहीं एक्सरे मशीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सिर्फ तीन सालों में ही हुआ? तीन साल पहले जब आपकी सरकार थी, क्या उस समय वह स्टाफ था? इस बात का भी स्पष्टीकरण दें कि अगर तीन साल पहले वहां स्टाफ था तो अब वह कहां चला गया? अगर वहां पर एक्सरे मशीन पड़ी थी तो अब वह कहां चली गई? तीन साल पहले जब आपका पांच साल का कार्यकाल था उस समय आपने वे चीजें उन अस्पतालों में क्यों मुहैया नहीं करवाई? प्रत्येक चीज़ के लिए आप मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। मगर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार, मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने जितनी भी बातें कहीं हैं, साधन ना होने के बावजूद भी लगातार उनको पूरा कर रहे हैं। आज नियुक्तियां भी हो रही हैं। वन मित्रों की नियुक्ति हुई, मल्टी टास्क वर्कज़ रखे गए और किसी ना किसी विभाग में लगातार नियुक्ति की जा रही है। विपक्ष के लोग बताएं कि आपने अपने समय में कितने लोगों को नौकरियां दीं? आप 1500 रुपये की बात कर रहे हैं। जब वर्ष 2014 में पहली बार आप केंद्र में सत्ता में आए तो आपने कहा था कि 15 लाख रुपये देंगे तो कौन से वर्ग को 15 लाख रुपये दिए, आप यह भी बताएं? जब हम नए-नए यहां पर आए तो बात चलती थी कि 1500 रुपये एक

भी महिला को नहीं दिए। आज तो हमने कई जिलों में 1500 रुपये दे दिए मगर 15 लाख रुपये लेने वाले लोग कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति तो बताएं जिसके खाते में 15 लाख रुपये गए

19.03.2026/1735/केएस/डीसी/2

हों। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। सत्ता पक्ष की हर चीज़ के ऊपर तो आप टिप्पणी कर रहे हो मगर आप यह नहीं बता पा रहे हैं कि आपने अपने समय में इस प्रदेश के लिए क्या किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री ने कभी कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा प्रदेश आने वाले समय में दुनिया में नम्बर-1 बने? आपने क्या कभी साधन जुटाने की कोशिश की? सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि वर्ष 2032 तक मैं आत्मनिर्भर प्रदेश बनाऊंगा और यहां के लोगों की आर्थिकी मज़बूत करुंगा।

सभापति महोदय, मैं यही कहूंगा कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए, वह ना निभाकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की जा रही है और यहां पर किसी भी चीज़ का प्रमाण ही नहीं है। यहां पर टोल बैरियर्ज़ की बात चल रही थी। मेरा चुनाव क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है। टोल बैरियर की शुरूआत किसने की? सबसे पहले टोल बैरियर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वर्ष 2001-02 में लगाया गया। आज यहां पर आप इस बात की निंदा तो कर रहे हैं कि टोल बैरियर लगा, मगर क्या आप जानते हैं कि अगर ऊना से एक बस पंजाब में एंट्री करती है तो उसको वहां पर 3 हजार रुपये देने पड़ते हैं। वही पंजाब की बस अगर हिमाचल में आती है तो 1 हजार रुपये देती है। यह बात तो हमारे लोग नहीं रखते। आज हिमाचल के हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, आज वहां पर पंजाब और चंडीगढ़ से टूरिस्ट वहां पर क्यों आता है क्योंकि हमारी बस जब पंजाब जाती है तो हमें प्रति सीट ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी चाहिए और पंजाब से बात करनी चाहिए कि आप भी हमारा टैक्स कम करें। हमारे लोगों की आर्थिकी पर तो यहां पर आपकी नज़र है । अगर आपको लगता है तो आप टोल बैरियर्ज़ के बारे में केंद्र में बात करें कि प्रत्येक प्रदेश को समानता की नज़र से देखा जाए। जो हमारी ग्रांट है, प्रदेश को पैसा नहीं देंगे तो प्रदेश को तो अपनी आर्थिकी को मज़बूत करना है। उसको तो अपने लोगों को पैसा देना है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

19.03.2026/1740/av/dc/1

श्री विवेक शर्मा------जारी

इसलिए प्रदेश को किसी-न-किसी ढंग से अपने संसाधन जनरेट करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणी न हो तो आप केंद्र सरकार से बात करें और कहें कि हमारा हक हमें दें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय कुटलैहड़।

19.03.2026/1740/av/dc/2

सभापति : अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, आपने मुझे दिनांक 16 फरवरी, 2026 को राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का नीति पत्र होता है। जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों, नीतियों और जवाबदेही का प्रमाण देती है। जब यह अभिभाषण हुआ तो मैंने इसको पढ़ा और इसको पढ़ने के उपरांत कुछ बातें मेरे ध्यान में आईं। यह सरकार नीड बेस्ड और चरणबद्ध तरीके से काम करने का दावा करती है। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता चाहूंगा।

CAG Report 2025 and State Finances Audit Report 2023-2024 जिसमें हिमाचल की वित्तीय स्थिति को ' heavily stressed' बताते हुए गम्भीर सिफारिशें की गई हैं। मैं यहां पर केवल सिफारिशों के बिन्दुओं पर बात करूंगा और इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा।

पहला बिन्दु यह है कि अपनी आय को तेजी से बढ़ाए। दूसरा, निवेश पर अपर्याप्त रिटर्न का आंकलन और सुधार। तीसरा, अधूरे प्रोजैक्ट समयबद्ध तरीके से पूरे करें। यहां पर जैसे कल माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा कह रहे थे कि 300 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट शायद 3100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसी प्रकार से फिन्ना सिंह नहर का प्रोजैक्ट मेरे जिले का भी है। उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा लग गया है। चौथा, मिस्एप्रोप्रिएशन, नुकसान और चोरी पर त्वरित कार्रवाई। पांचवा, बजट लेखा और सुधार तथा छठा, अनधिकृत और बिना प्रावधान के व्यय को रोका जाए। उसके बाद इन सिफारिशों में कहा गया है कि अगर इन सिफारिशों को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास प्रभावित होगा जोकि आज हो रहा है। यह कैग की रिपोर्ट है, यह सब भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। उसके बाद प्रत्येक बजट में यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बना देंगे और वर्ष 2032 तक हमारा प्रदेश देश के दूसरे राज्यों में सबसे अमीर बन जाएगा। जबकि यहां पर रोना यह रोया जा रहा है कि केंद्र ने आर0डी0जी0 बंद कर दी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपका यह एजेण्डा जोकि हिमाचल को आत्मनिर्भर और सबसे अमीर बनाने का था; क्या यह केंद्र सरकार की जेब पर आधारित था। यहां पर इसी बात को लेकर

19.03.2026/1740/av/dc/3

इस बार बजट के पहले सत्र में तीन दिन की चर्चा रखी गई। ठीक है, उस बजट सत्र के दौरान आपने कहा कि हम केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। हमने भी उस चर्चा में भाग लिया और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। लेकिन आपने इस बिन्दु पर तो चर्चा की ही नहीं कि अगर आपके प्रस्ताव को केंद्र सरकार नहीं मानती तो आप क्या करेंगे। उस बारे में तो कोई बात नहीं हुई। ...(व्यवधान) हम हिमाचल के साथ हैं, काँग्रेस पार्टी के साथ नहीं हैं।

सभापति महोदय, विकास सबका होना चाहिए और यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है उसमें चाहे केंद्र सरकार की बात हो या किसी भी राज्य की सरकार हो। परंतु यहां केवल चुनिन्दा लोगों व चुनिन्दा क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है जोकि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं क्योंकि प्रदेश में कुछ स्कूल्ज बंद कर दिए गए। मिड डे मील वर्कर्ज जोकि काँग्रेस पार्टी की विचारधारा से संबंधित थे

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1745/टी0सी0वी0/एच0के0-1

डॉ0 जनक राज ... जारी

उनको आपने कहीं न कहीं इंगेज कर दिया लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में उनको ऐसे ही छोड़ दिया। अब वे महिलाओं मेरे पास आकर कहती हैं कि आप फोन कर दो क्योंकि हमें कहा गया है कि विधायक से फोन कराएंगे तो हम रखेंगे, ऐसे हम नहीं रखेंगे, यह क्या तरीका चला हुआ है।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करुं तो वहां अधिकारियों के पद खाली पड़े हुए हैं। मैं इस विषय को प्रायोरिटी और ट्रायबल एडवाइजरी कांउसिल (टी0ए0सी0) की मीटिंग और इस विधान सभा में बार-बार उठाता रहा हूं। मेरे क्षेत्र में सड़कें टूटी हैं, सड़कों में गड्ढे हैं और सामने बोर्ड लगा है, व्यवस्था परिवर्तन, खुशहाल हिमाचल। मैंने पहले भी कहा था कि इन बोर्डों को हटा दो और इस पर दुःखता हिमाचल लिख दो। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो झटके लगते हैं और सामने लिखा होता है 'खुशहाल हिमाचल'। सरकार ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली कि बोर्ड और कॉरपोरेशन के चेयरमैन सैलरी में 20 प्रतिशत कटौती कर दी जाएगी और उनके कैबिनेट रैंक हटा दिए गए। सरकार ने पहले तो अपने चहेतों को कोट पहनाए और अब उनको लंगोट में पहुंचा दिया है। मैं एक बात सरकार से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे हिमाचल से पूछना चाहता हूं कि क्या मूंछों के बाल काटने से लाश का वजन कम होगा? इतनी छोटी-छोटी चीजों को रोकने से कुछ नहीं होगा? जो आपको रोकना है वह मिसएप्रोप्रिएशन रोकना है, जो आपकी प्रोजैक्ट एक वर्ष

में पूरे न होकर 5, 10 वर्ष तक लटक रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसा कि माननीय सदस्य प्रकाश राणा जी ने कहा था।

19.03.2026/1745/टी0सी0वी0/एच0के0-2

सभापति महोदय, आपकी सरकार ने मेडिकल इक्यूपमैंट खरीदने के लिए एक मेडिकल कॉरपोरेशन बनाया। अभी माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी यहां पर बैठे नहीं है। इनके पास सामाजिक न्याय का भी दायित्व है परंतु मुझे दुःख इस बात का है कि यह मेरे जनजातीय लोगों के साथ भी न्याय नहीं कर पाए। इस मेडिकल कॉरपोरेशन ने एक भी इक्यूपमैंट मेरे ट्राइबल क्षेत्र के अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं दिया और न ही इन्होंने स्वास्थ्य संस्थान खोले। जबकि ये मेडिकल कॉरपोरेशन की अध्यक्ष भी है लेकिन इन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ नहीं किया। इसके बाद जनजातीय लोगों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इस बात का पता इससे चलाता है कि भारत के संविधान में इन मामलों के लिए केंद्र और प्रदेश में अलग मंत्रालय होता है। हमारे 68 विधान सभा क्षेत्र में 3 जनजातीय क्षेत्र आरक्षित हैं और एक मंत्री उसके लिए होता है। जनजातीय क्षेत्र की हालत यह है कि वहां मैक्सिमम पावर प्रोजैक्ट हैं। मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत बड़ा बिजली उत्पादन करने वाला क्षेत्र है लेकिन मेरे चुनाव क्षेत्र में कुंर, धरवेटा, बडग्रां, तुंदा, होली, बकाण, जिडू जैसे गांव के लोग एक ट्रांसफार्मर के लिए तरस रहे हैं। उनका छोटा-मोटा निजी व्यवसाय, आटा चक्की, आरा मशीन हैं। वहां शाम को मोबाइल तकचार्ज नहीं होते हैं। मुझे भरमौर से बाहर रहते हुए वर्ष 1991 के बाद वर्ष 2022 तक लगभग 31 वर्ष हो गए हैं जब मैं वापस गया तो वहां आज भी बिजली की वही स्थिति है जो वर्ष 1991 में थी। यह बहुत बड़ा दुःख का विषय है।

सभापति महोदय, मैं प्रदेश सरकार के इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद माननीय कृषि मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के 432 किसानों से 1239 क्विंटल गोबर खरीद कर उन्हें 862 रुपये का आर्थिक लाभ दिया लेकिन मेरे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को इससे वंचित रखा गया।

19.03.2026/1745/टी0सी0वी0/एच0के0-3

मेरे क्षेत्र में जड़ी-बूटियां और घास खाने वाले पशु हैं उनके गोबर में अधिक न्यूट्रीशन वैल्यू हो सकती है फिर वहां से क्यों गोबर नहीं खरीदा गया? यह 862 रुपये का सालाना आर्थिक लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को भी मिलना चाहिए था। क्या उन्होंने भाजपा के विधायक को चुनने की गलती की है, नहीं वहां से 25650 लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया है, उन्ही से गोबर खरीद लेते।

सभापति महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है, पिछले बजट में मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि एक वर्ष बाद पूछना कि हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? ये रिकॉर्ड में

श्रीमती एन0एस0 द्वारा ... जारी

19-3-2026/1750/NS-HK/1

डॉ0 जनक राज------जारी

यह रिकॉर्ड में है। आज मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों के बाद हम स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करेंगे और केवल 2 ही मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं तथा बाकी मेडिकल

कॉलेजों की हालत बहुत बुरी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन कॉलेजों की हालत किसने ठीक करनी है? सभापति महोदय, आज अस्पताल इलाज के केंद्र नहीं बल्कि यातना केंद्र बन चुके हैं जहां पर लोगों को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लम्बी डेट, ऑपरेशन के लिए लम्बी डेट, डॉक्टर से मिलने के लिए लम्बी डेट मिल रही है और जो डॉक्टर वहां पर उपलब्ध है उससे मिलने के लिए भी लम्बी डेट मिल रही है। मैंने बार-बार कहा और मैं सुझाव देने के लिए भी तैयार हूं और मैं स्वास्थ्य के विषय में कभी भी राजनैतिक चश्मा पहन कर बात नहीं करूंगा। हमारे पास डॉक्टर्ज उपलब्ध हैं लेकिन हम उनसे काम ही नहीं ले पा रहे हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता लेकिन हमारे पास ऐसे-ऐसे डॉक्टर्ज हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी कि मैंने भी ऑपरेशन करना है। आज अस्पतालों में यह हालात बने हुए हैं, इसको कौन ठीक करेगा?

सभापति महोदय, मैं अब कुछ बातें अपने विधान सभा क्षेत्र की कहना चाहूंगा। मैंने ये बातें विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी कही हैं और Tribal Advisory Council की मीटिंग में भी कहा कि भरमौर से अगर कोई आदमी मेडिकल कॉलेज, टांडा में एंबुलैंस लेकर आता है तो वह एंबुलैंस 18 घंटो तक दूसरे मरीज को नहीं मिल सकती है क्योंकि एंबुलैंस मरीज को टांडा छोड़ने जाएगी फिर वापिस आएगी और फिर ड्राईवर चेंज होगा तब दूसरे मरीज को लेकर जाएगी। हमने कहा था और उस समय मुख्य मंत्री जी ने सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देश भी दिए थे कि ऐसे-ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में एंबुलैंस की संख्या को बढ़ाया जाए। अगर सरकार के पास संसाधन नहीं हैं तो वहां पर इतने पॉवर प्रोजैक्टस हैं आप उनको एंबुलैंस देने के लिए बोलें। यह केवल पांगी या भरमौर की बात नहीं है जो भी दूरदराज के क्षेत्र हैं जहां से रेफरल सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए 6 से 8 घंटे लगते हैं वहां पर एंबुलैंस की संख्या कम-से-कम 4 या 5 होनी चाहिए ताकि एक मरीज को ले जाने के बाद दूसरे मरीज को एंबुलैंस आसानी से मिल जाए। इसमें हमारा कुछ नहीं है

19-3-2026/1750/NS-HK/2

क्योंकि हम तो संघर्ष करते हैं लेकिन सरकार की किरकिरी होती है कि हमें एंबुलैंस नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि कूर, जगत, छतराड़ी में स्वास्थ्य केंद्र खाली हैं। वहां पर बिजली की समस्या है। चम्बा मेडिकल कॉलेज में जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उनको पिछले तीन महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। पांगी में 60 नर्सरी वर्कर्ज पिछले दो सालों से अपनी दिहाड़ी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। यह कितनी शर्म की बात है। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो निचले स्तर पर है और हमारी पार्टी की विचारधारा है कि हम पंक्ति के अंत में बैठे व्यक्ति का उत्थान करने के लिए वचनबद्ध एवं प्रतिबद्ध हैं। शायद यह आपकी पार्टी की विचारधारा नहीं है। इसीलिए आप इन गरीब लोगों को दो वर्षों तक अपनी की हुई मेहनत का पैसा देने में असमर्थ हैं। चूड़ी अस्पताल में एक डॉक्टर है। भरमौर, छतराड़ी, गरोला, मैहला में सीवरेज का कार्य पूर्व में श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार जहां तक करके आई थी वहां तक ही हुआ है और वर्तमान सरकार के समय मे यह कार्य एक फुट भी नहीं हुआ है। मैं बार-बार अधिकारियों से बात करता हूं कि इस काम को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? तब वे कहते हैं कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। जब मैंने ठेकेदार से बात की कि आप काम क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं? वह कहता है कि पैसे नहीं हैं। मैं इसका सरकार से जवाब चाहूंगा। सरकार या तो इन टेंडर्ज को रद्द करे या फिर दूसरे नए ठेकेदार को टेंडर दे या फिर कहीं से भी बजट का प्रावधान करके इन कार्यों को शुरू करें क्योंकि यह जनहित की बात है और पूर्व सरकार में सेंक्शन्ड किए हुए कार्य हैं। मेडिकल ब्लॉक, भरमौर में हैल्थ वर्कर्ज के जो काम करने के सेंटर्ज होते हैं वहां 19 सब-सेंटर्ज में से 14 सब-सेंटर्ज खाली हैं। पांगी में 16 में से 10 सब-सेंटर्ज खाली हैं। पांगी में डॉक्टरों के 10 पद खाली हैं। धरवास पुर्थी में पी0एच0सी0 खाली है। चूड़ी में 30 में से 13 पद खाली पड़े हुए हैं। वहां पर हालात ये हैं कि हम सब लोगों को वर्ष 1970 से वर्ष 1990 के दशक में जो नियमित टीकाकरण लगता था तो आज लोगों को वह भी नहीं लग रहा है। प्रसूता महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पर उठाकर बारिश में

19-3-2026/1750/NS-HK/3

पथरीले रास्तों पर कई किलोमीटर पैदल जाकर हॉस्पिटल में टीके लगवाती हैं। आज हिमाचल प्रदेश की ये परिस्थितियां हैं और फिर कहते हैं कि हमने रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी है। सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय और दें

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

19.03.2026/1755/RKS/YK-1

डॉ0 जनक राज जारी.....

सभापति महोदय, आप मुझे बस दो मिनट और बोलने का समय दीजिए। ...(व्यवधान) हमने अगर कुछ गलतियां की हैं तभी हम इधर बैठे हैं। सभापति महोदय, मैं PWD विभाग की विशेष तौर पर बात करना चाहूंगा। लोक निर्माण मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं है। शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच रही होगी। PWD विभाग में XEn के पद खाली पड़े हैं। एक ही आदमी को बार-बार XEn के पद पर बिठाया जा रहा है। किसी भी शासन-प्रशासन की सबसे बढ़िया credibility इससे पता लगती है कि उनके द्वारा किए गए आदेशों का अक्षरशः पालन हुआ है या नहीं। यह सरकार की कमजोरी नहीं है तो और क्या है? आपने पिछले तीन सालों में 6 बार XEn की ट्रांसफर की और 6 बार नये XEn लगाए। लेकिन क्या एक XEn ने भी वहां ज्वाइन नहीं किया? इसके क्या कारण हैं? फिर आप कहते हैं कि हम जनजातीय क्षेत्रों का समान रूप से काम कर रहे हैं। पांगी में भी यही हालत है। भरमौर और मेहला में BDO नहीं है। पांगी में XEn नहीं है। पांगी में SDM को आर0सी0 का चार्ज दे रखा है। भरमौर में ADM को SDM का चार्ज दे रखा है। आपका जो नीड बेस्ड का नारा है और जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां आप सबसे कम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मैं लोक निर्माण विभाग भरमौर की बात करता हूं। केंद्र सरकार की योजनाओं के जो करोड़ों रुपये के काम PMGSY या नाबार्ड के तहत चल रहे

हैं उनकी सुपरविजन के लिए एस0डी0ओ0 और जे0ई0 नहीं है। बेलदार को टेंडर अवार्ड की सीट पर बिठाया गया है और जो अधीक्षक है उसको कहा गया है कि आप सिर्फ डाक का कार्य देखें। क्या यह आपका व्यवस्था परिवर्तन है? मैं प्रत्यक्ष तौर पर लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगा रहा हूं। वहां पर अधिकारी नहीं बल्कि collection agent बिठाए गए हैं। अगर मुझे अनुमति दी जाए तो मैं इसके सबूत वीडियो के साथ जारी कर सकता हूं। उन अधिकारियों को कैसे ठेकेदार पैसे पकड़ा रहे हैं और वे कैसे आगे टेंडर अवार्ड कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है। यह आप लोगों का कौन सा तरीका है? मैंने कई बार माननीय लोक निर्माण मंत्री और माननीय जनजातीय मंत्री से आग्रह किया है। सभापति महोदय, मुझे बस दो मिनट और दे दीजिए। धरवाला में पार्किंग निर्माण का कार्य दो सालों से लटका हुआ है। वहां पर अभी तक एक ही डंगा लगा हुआ है। सुनारा-कुंडी-गुराड़-डुलाड़ रोड बंद है। सियूर स्कूल का माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन

19.03.2026/1755/RKS/YK-2

करके चले गए लेकिन उस स्कूल को जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। घट, कंडी, मिंद्रा, त्यूला, राम्भो, गरोला और ग्वाड़ सड़क का कार्य अधूरा पड़ा है। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन उन बातों का जिक्र मैं बजट की चर्चा के दौरान करूंगा। यहां पर एक बात कही गई थी कि हमने SCDP प्लान में 1228 करोड़ रुपए खर्च किए। माननीय विधान सभा अध्यक्ष हमारे जिला से आते हैं। SCDP प्लान में आपने मेरे जिला के लिए एक रुपया भी नहीं दिया। आपने 1228 करोड़ रुपये कहां खर्च कर दिए? मुझे अंत में यह कहना है किः-

'जैसा दिखाने की करते हो कोशिशें, मैं बखूबी जानता हूं कि ऐसे नहीं हो तुम।

यह अभिभाषण नहीं है बल्कि यह केंद्र सरकार की आलोचना का एक माध्यम मात्र है जिसमें सरकार अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का प्रयास कर रही है। रूठी हुई बिल्ली की चर्चा हर बार हो रही है। परंतु उस बिल्ली के द्वारा गिराए गए दूध और फैलाए गए रायते की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। उस पर सब खामोश है। यही हाल आज हिमाचल की सरकार का है जहां सुधारों पर नहीं बल्कि राजनीतिक शोर पर तवज्जो दी जा रही है। सभापति

महोदय, मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

19.03.2026/1755/RKS/YK-3

कृषि मंत्री : डॉ0 जनक राज जी ने कुछ बातें यहां पर रखी है। इन्होंने कहा है कि जब मैं पढ़ता था तो उस समय वहां पर बिजली नहीं थी। वर्ष 2004 में मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट था। उस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत 90:10 के हिसाब से सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए पैसा जारी किया जाता था। यानी पोल, कंडक्टर और ट्रांसफर मुहैया करवाने के लिए अगर सबसे पहला जिला चुना गया तो वह चंबा और सिरमौर जिले थे। दूर-दराज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जहां बिजली नहीं पहुंची। चाहे वह पांगी हो या भरमौर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बिजली या ट्रांसफार्मर पहुंचाए गए। वहां पर सौ प्रतिशत rural electrification का काम हुआ है। यह कह देना कि वहां पर काम ही नहीं हुआ है, यह उचित नहीं है। मैं वर्ष 2004 की बात कर रहा हूं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

19.03.2025/1800/बी.एस./वाई.के.-1

कृषि मंत्री जारी...

क्योंकि मैं खुद पार्लियामैंट मिनिस्ट्री में था। उस वक्त 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, 90 प्रतिशत ग्रांट और 10 प्रतिशत लोन पर यह कार्य हुआ था। वह भी सारा उस वक्त भारत सरकार ने दिया। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो हम ऑर्गेनिक मैन्योरिंग लोगों से खरीद रहे हैं, इनके तो मैक्सिमम लोग माइग्रेटरी शेफर्ड्स हैं। इनकी भेड़-बकरी तो गांव में नहीं रहती हैं। गर्मियों के दिनों में वह सारी भेड़ें अलपाईन पास की तरफ चली जाती हैं और सर्दियों में वापस आ जाती हैं। ज्यादा करके लोग जो अपनी गाय वगैरह रखते हैं, उन्हीं का जो भी गोबर होता है या मैन्योरिंग होती है, वह अपने खेतों में डालते हैं और इसीलिए हमने पांगी को 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक बनाया है। अगर उनकी

भेड़-बकरियां वहां पर रहती भी हैं तो वह स्थायी नहीं हैं, क्योंकि यह माइग्रेट करती हैं। यह कहना कि हमारा कोई खरीदने वाला नहीं है, यह ठीक नहीं है।

हमने तो यह कहा था कि अगर 3 रुपये किलो कोई ऑर्गेनिक मैन्योरिंग देने को तैयार है तो हम ले रहे हैं और हम लेकर उसको आगे अपने एग्रीकल्चर फार्म में, प्राकृतिक खेती की तरफ डेवलप कर रहे हैं। जो बाकी गोबर है हम दिल्ली से इकट्ठा करके लाते हैं अगर यहां लेने चाहे तो तैयार हैं तो जितने भी बागवानी वाले हैं, चाहे वह भरमौर के हों, कुल्लू-मनाली के हों, रामपुर के हों, शिमला के हों या जुब्बल-कोटखाई के हों, वह हमारे पास आकर ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मैन्योरिंग पड़ी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम खरीदने के लिए भी तैयार हैं। परंतु किसान कह रहे हैं कि हम इस रेट पर नहीं देंगे। हमने तो लोगों से वादा किया था। हमने 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये किया और 5 रुपये उसमें केरिज भी कर दिया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके लोग माइग्रेट करते हैं और वहां भेड़ें रहती ही नहीं हैं। मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

19.03.2025/1800/बी.एस./वाई.के.-2

सभापति : अब माननीय सदस्य कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : सभापति जी, आपने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा हमारी सरकार ने पिछले 3 साल से कार्य शुरू किया है और मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए हैं, यह बहुत ही सराहनीय हैं। जैसे

खेती के ऊपर जोर दिया जा रहा है, बागवानी के ऊपर जोर दिया जा रहा है ताकि जनता आत्मनिर्भर बन सके। आज से 20-25 साल पहले खेती में चाहे मक्की होती थी, चाहे गेहूं होती थी। उसमें यूरिया नहीं डाली जाती थी तो कैंसर जैसी बीमारियां हमारे समाज में नहीं होती थीं। अभी भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में दूसरे नंबर पर है। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं और हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं। मैं अपनी सुजानपुर की जनता की तरफ से और इस सदन की तरफ से भी मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

दूसरा, नशे को रोकने के लिए जो युवाओं की रैलियां की गई हैं, चाहे वह शिमला में हों, धर्मशाला में हों या हमीरपुर में हों, वह बहुत ही सराहनीय हैं। क्योंकि इस समय हमारा युवा प्रदेश की रिड़ की हड्डी है। अगर ये नशे से बचे रहेंगे तो हमारा प्रदेश उन्नति करेगा और ये नशे में चले जाएंगे तो हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इस बारे में सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं कि वे खेलों की ओर अपना ध्यान दें और नशे से दूर रहें। इसमें चाहे हॉस्पिटल की सुविधा हो। अभी मैं सुन रहा था कि अस्पताल में डॉक्टर्ज नहीं हैं। क्या ये डॉक्टर तीन साल से नहीं हैं?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

19.03.2026/1805/DT/AG-1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा जारी...

क्या वहां पर तीन साल से ही डाक्टर नहीं हैं? जो पहले वहां डाक्टर थे वे कहा चले गये? मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सुजानपुर हस्पताल में केवल 2 डाक्टर थे। आज वहां पर 8 स्पैशलिस्ट डाक्टर्ज हैं और 5 जनरल फिजिशियन्स हैं यानी कुल 13 डाक्टर्ज हैं। 16 नर्सिज हैं। अब वहां कैसे काम हो रहा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, बागवानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी सरकार के द्वारा पूरा जोर लगाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान समय में कोई पोस्ट खाली नहीं है। वहां पर इनकी पार्टी के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वे बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री का नाम ले कर कहा था कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश का बेड़ागर्क कर दिया। ऐस शब्द विडियों रिकॉर्डिंग में पड़े हुए हैं।

उन्होंने यह भी बोला की भाजपा सरकार के समय पुलिस की भर्ती के लिए हुई परीक्षा के प्रश्न पत्र सड़कों पर बेचे गये- और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। युवाओं को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और सड़को पर प्रश्न पत्र बेच कर पैसे कमायें जा रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं कहा ये तो इनके नेता के शब्द हैं।

मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार के पांच साल में विकास के नाम पर एक भी ईंट सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र में नहीं लगाई गई। अगर विपक्ष के साथी यह बता देंगे की सुजानपुर में इनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक भी ईंट विकास के नाम पर लगाई गई है तो मैं मान जाऊंगा। राज्य सरकार के अधिकार यदि केंद्र सरकार नहीं देगी तो प्रदेश कैसे चलेगा? हिमाचल प्रदेश भी इसी देश का एक राज्य है। मेरे विधान सभा में विकास के कार्य पिछले एक साल से हो रहे हैं उसमें चाहे डे-बोर्डिंग का काम हो, चाहे वह बस स्टैंड का काम हो, चाहे वह संधोल से लेकर सुजानपुर की सड़क का काम हो, चाहे अखलंबर वाली सड़क का काम हो, चाहे लोहारडा-डुखराल की सड़क का काम हो, चाहे टौणी देवी से सुजानपुर-जंगल बेरी की सड़क का काम हो। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो अी0डी0जी0 और जी0एस0टी0 और अग्निवीर, मनरेगा और जल जीवन मिशन ...(व्यवधान)

Chairman : Hon'ble Leader of Opposition, Sir, he is not yielding. आप ने जो भी क्लेरिफिकेशन देनी होगी इसके बाद दे देना। माननीय नेता प्रतिपक्ष जैसे माननीय सदस्य अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे उसके बाद आप बोल लीजिए। आप उसके बाद

19.03.2026/1805/DT/AG-2

कोंट्राडिक्ट कर लेना। उसके बाद आप को समय दे देंगे। He is not yielding. वे अपना वक्तव्य खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आप को समय दे दिया जायेगा।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : सभापति महोदय, मैंने व्यक्तिगत रूप में किसी का नाम नहीं लिया है। जो इनके सुजानपुर के नेता के द्वारा बोला गया है वहीं मैं बता रहा हूं।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक 15 लाख रुपया किसी के खाते में नहीं आया है। 5 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई।

सभापति : माननीय सदस्य श्री राणा जी आप कृपया बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य जैसे ही अपना वक्तव्य खत्म करते हैं उसके बाद आप को समय दे दिया जायेगा। आप जो भी बात कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उनको अपना वक्तव्य तो खत्म करने दीजिए। अब उनको शायद 2 मीनट ही लगेंगे। मेरे ख्याल से उनका वक्तव्य समाप्त होने ही वाला है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप कृपया आप बैठ जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष अब आप अपनी बात रख सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष एन0जी0 द्वारा जारी...

19.03.2026/1810/ए.जी.-एन.जी./1

सभापति महोदय के पश्चात..... जारी

श्री जय राम ठाकुर : सभापति महोदय, कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी नए नहीं रहे हैं और पुराने हो गए हैं। इनको 3 साल होने वाले हैं और इन्हें कब तक नया रखेंगे?...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता था कि एक सैनिक होने के नाते ये जो भी बात कहेंगे, वह सत्य कहेंगे। ये अपने विधान सभा क्षेत्र का जिक्र करते तो हैं लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त ये वहां पर रहते नहीं होंगे। लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि...(व्यवधान) पार्टी का टिकट हमने ही दिया था। बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और विचारिक दृष्टि से मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। कोई आदमी एक जगह खड़ा होता है लेकिन यह तो बदलते रहे हैं। इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ये दल बदल करके जीते हैं।

सभापति महोदय, ये जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो मैं बताना चाहता हूं कि इनके क्षेत्र में हमारी सरकार ने दो-दो डिविजन दिए थे। हमारी सरकार ने इनके विधान सभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिविजन दिया।...(व्यवधान) आपने ही बंद किए। दो डिविजन देने के बाद भी आपकी कांग्रेस की

सरकार ने आते ही वे बंद कर दिए और बंद करने के बाद अभी खोले हैं। आप कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए और आप विधायक बन गए। हम लोकतंत्र में आपका सम्मान करते हैं लेकिन कम-से-कम सत्य तो बोलो। आप कहिए कि दो डिविजन दिए थे लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें बंद कर दिया और उसके बाद अभी दोबारा खोल दिए हैं क्योंकि अब आप कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार के दौरान करोड़ों रुपये के काम हुए थे। जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग में, हमारे पार्टी के नेता जो भी कहते थे, वह हम करते थे। इसलिए एक सैनिक होने के नाते असत्य मत बोलो। सेना के प्रति हमारा बहुत बड़ा सम्मान है और इस नाते थोड़ा बहुत आपके प्रति भी है इसलिए मेहरबानी करके झूठ मत बोलिए।

19.03.2026/1810/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति : माननीय राजस्व मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार एक प्रश्न उठता है कि जब भी कोई माननीय सदस्य बोल रहे होते हैं तो दूसरों को बीच में इंटरप्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी यहां पर सत्त पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जी हर बात पर बीच में इंटरप्ट करते हैं। इस प्रकार से तो एक नया तरीका या नया कानून बनाना पड़ेगा। यदि ऐसे वाद-विवाद चलेगा तो फिर विषय खत्म ही नहीं होगा। इस तरीके को रोकना पड़ेगा क्योंकि यह तरीका बिल्कुल गलत है। नेता प्रतिपक्ष जी इनको धमका रहे हैं कि आप सैनिक हैं इसलिए आप सच बोलो। यह किस तरह की बात है? इनके बोलने की एक लय बनी हुई है और उसी को ये बीच में रोक रहे हैं ताकि इनको डायवर्ट करें। यह तरीका गलत है। जब यहां पर विपक्ष के लोग या नेता प्रतिपक्ष जी बोलते हैं तो हम एक

मिनट या एक सेकंड के लिए भी इनको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन जब हम बोलना शुरू करते हैं तो बीच में इनको पता नहीं क्या हो जाता है? यह डेकोरम रखना पड़ेगा और जो नियम इस माननीय सदन ने बनाया है, उसको चलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हर प्वाइंट पर हमने एक-दूसरे पर कटाक्ष करना है तो फिर हम भी इनके साथ ऐसे ही करेंगे और फिर बोलने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।

19.03.2026/1810/ए.जी.-एन.जी./3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कैप्टन रणजीत सिंह राणा, आप आपना वक्तव्य पूरा कीजिए।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी बोलने के लिए बीच में थोड़ा रोका गया था।

अध्यक्ष : आपको तो इम्पोर्टेंस मिल गई है कि नेता प्रतिपक्ष आपको इंटरप्ट कर रहे हैं।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला कि इलेक्ट्रिकल और जल शक्ति विभाग का डिविजन जो उस टाइम खोला था, वह इन्होंने जाते-जाते घोषणा की थी लेकिन वे खुले नहीं थे।...(व्यवधान) उसके लिए न कोई बिल्डिंग थी और न ही उसके लिए कोई स्टाफ था तथा वहां पर कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ था।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

19.03.2026/1815/ए.पी. /ए.एस. -1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा जारी .....

इसके अलावा आर0डी0जी0, जी0एस0टी0, अग्निवीर, मनरेगा और जे0जे0एम0 की स्कीमें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी आर0डी0जी0 से ही हमें इतना घाटा पड़ गया कि हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह हिमाचल प्रदेश की

जनता का नुकसान है। इससे लगभग 10,000 करोड़ का घाटा है और अगले पांच सालों में यह और बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए भी विपक्ष ने समर्थन नहीं किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने संसाधनों से कई विकास कार्य करवा रहे हैं। इसके बाद जी0एस0टी0 पर भी केन्द्र सरकार ने कट लगा दिया गया। अब मैं अग्निवीर योजना पर कहना चाहता हूं। मैं स्वयं अग्निवीर नहीं हूं, लेकिन जो युवा इस योजना में भर्ती हुए हैं उन्हें चार साल बाद वापस आना पड़ेगा। उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर उनकी टांग कट जाती है तो भी उनको स्थायी सहायता नहीं मिलेगी और न ही कोई बोर्ड पेंशन मिलेगी, जोकि हमारे समय पर मिलती थी। दूसरी बात यह कि उन्हें कोई शहीदी का दर्जा भी नहीं मिलेगा और न ही कोई एक्स-सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर 60 प्रतिशत हमारे प्रदेश के जवान देश के लिए भर्ती होते थे। इसलिए हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि कहा जाता था। इस पर भी केन्द्र सरकार ने अंकुश लगा दिया। हमारे दूसरे भी पहाड़ी राज्य हैं जैसे उत्तराखण्ड। लेकिन उत्तराखण्ड का आधे से ज्यादा क्षेत्र प्लेन में आता है। जिससे की वहां पर फैक्ट्रीयां और यूनिवर्सिटीयां बहुत ज्यादा हैं। जिससे की वहां के लोग फैक्टरियों औरी यूनिवर्सिटीज आदि में नौकरी कर लेते है। लेकिन हमारे हिमाचल के लोगों के पास एकमात्र रास्ता भर्ती था, इसके इलावा कोई चारा ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता वर्ष 2027 में इसका कर्ज, ऋण के साथ हमारे विपक्ष के साथियों को वापिस करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2027 में हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। क्योंकि हिमाचल में विपक्ष ने इस विषय पर कोई मुद्दा नहीं उठाया है। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और इस प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर कोटा न दिया जाए, क्योंकि हमारे पास नौकरी का कोई संसाधन नहीं है। इसलिए इन्होंने हमारे सैनिकों के साथ भी धोखा किया है। ...(व्यवधान)

Speaker : No disturbance please.

19.03.2026/1815/ए.पी. /ए.एस. -2

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हिमाचल ने तकरीबन हर लड़ाई में भाग लिया है। तभी तो हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि कहा जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा,

जो पहले परमवीर चक्र विजेता, हमीरपुर से थे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश वीर भूमि और सैनिको की भूमि है। लेकिन अग्निवीर योजना लाकर सैनिकों का अपमान किया गया है। आप ही बताओं कि जो चार साल बाद के वापिस आएगा उसको कौन-सी नौकरी मिलेगी? वह अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ...(व्यवधान)

Speaker : No interruption please.

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : वह अपने परिवार का पालन पौषण कैसे करेगा। केन्द्र सरकार ने एक काम किया है अग्निवीरों के लिए, जैसे उन्होंने आर0डी0जी0 बंद की उसी तरह से अग्निवीरों के लिए किया। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा में भी 60-40 का नियम लागू कर दिया गया है। कहा गया कि फसल के समय दिहाड़ी नहीं मिलेगी, बरसात के समय दिहाड़ी नहीं लगेगी तो आप ही बताईये की जो रोज दिहाड़ी लगा कर कमाता है, रोज़ाना मेहनत करके शाम को खाना खाते हैं, वे सात महीने तक कैसे जिएंगे? आपने मनरेगा में, आर0डी0जी0, अग्निवीर में और जी0एस0टी0 अंकुश लगा दिया। जे0जे0एम0 के जो टैंक बने हुए थें उनको तीन साल हो गये है ठेकेदारों को पैसा लुठाया गया लेकिन उनकी पाईप लाईने ही नहीं पड़ी। अभी भी जे0जे0एम0 का काम अधूरा है। उन टैंकों की पाईपे नालों और खड्डों में रखी थीं वे सारी बह गई। अगर इस हालत में विपक्ष, सत्ता पक्ष का साथ नहीं देगा तो हमारा हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, जो हमारे मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार ले रही है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

19.03.2026/1820 /AT/AS /01

कैप्टन रणजीत सिंह राणा जारी...

जो मदद मिल रही है वह मैंने यहां बताई है आर0डी0जी0 बंद, अग्निवीर शुरू, मनरेगा खत्म, और जे0जे0एम0 के टैंक अधूरे पड़े हुए हैं और फट भी गए हैं। ठेकेदारों को पैसा लूटने के लिए अंधाधुंध बिल्डिंग बना दी गईं। इनके समय में 70,000 करोड़ रुपये मिले।

अगर इनमें से 20,000 करोड़ रुपये भी कर्ज वापस कर देते तो आज हिमाचल प्रदेश की यह दशा नहीं होती। इनका यह फर्ज नहीं था। जब इनका समय था तब हर दो-तीन महीने में जश्न मनाए गए और पूरा पैसा खर्च कर दिया। अब हमें कोस रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं।..... (व्यवधान) मंडी में जो हुआ वह हमने नहीं किया। हम तो आपदा के दौरान उन लोगों को चेक देने गए थे जिनके घर आपदा में गिर गए थे। उन्हें मंडी में बुलाया गया था। अगर इनके समय में आधा पैसा भी वापस कर दिया जाता तो आज यह हालत नहीं होती। कर्मचारियों का एरियर दे देते, डी0ए0 दे देते, पेंशन का भुगतान कर देते, तो आज हिमाचल प्रदेश सुखी होता। इनकी वजह से ही आज हिमाचल की यह स्थिति है। इसका जवाब जनता वर्ष-2027 में देगी। इनके नेता पहले भी कहते रहे थे कि 15 लाख रुपये खाते में नहीं आए, 5 करोड़ नौकरियां नहीं मिलीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता के बीच जाकर काम कर रही है। जनता इससे खुश है। आपने मेरी बात सुनी और मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः परमार साहब, राणा साहब कह रहे थे कि मैंने इन्हें बहुत समझाया कि जश्न मत करो,मत करो। यही वह कह रहे थे कि जब मैं इनके साथ था तब भी यह नहीं माने। बाद में ऐसा हुआ कि मैं यहां आ गया और ये खुद वहीं के वहीं रह गए। अब इंद्र सिंह गांधी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इंद्र सिंह गांधीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

19.03.2026/1820 /AT/AS /02

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य विभाग पर आता हूं। माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी 6 तारीख को मंडी के मेडिकल कॉलेज में गए थे। वहां उन्होंने

सभी विभागाध्यक्षों से समीक्षा बैठक की और चाहे वे सर्जरी, ई0एन0टी0 या ऑर्थो का था और पूछा कि आपके विभाग में कौन सा डॉक्टर या कर्मचारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपको चुटकी में डॉक्टर भेज दूंगा। आज 19 तारीख हो गई है लेकिन वह चुटकी अभी तक नहीं आई।

माननीय मुख्य मंत्री ने अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर को टांडा से भेजने के लिए कहा गया था कि वह अगले दिन वह डॉक्टर आ जाएगा। लेकिन वह डॉक्टर टांडा होते हुए चंबा पहुंच गया, जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान होते हुए आ रहा है पर वह अभी तक नहीं पहुंचा है। यह मेडिकल कॉलेज नेर चौक की व्यवस्था है। पता नहीं टांडा का डॉक्टर कहां गया। लोग बाहर अल्ट्रासाउंड, एम0आर0आई0 और सी0टी0 स्कैन करवा रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है? माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने वर्ष- 2022 में एम0आर0आई0 का टेंडर लगाया था लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही उस टेंडर को रद्द कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि हमने टेंडर लगा दिया है। तीन साल से टेंडर ही लग रहे हैं क्या अभी तक टेंडर पूरा नहीं लगा? आज यहां स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं और पूर्व मुख्य मंत्री भी उपस्थित हैं। वर्ष-2022 में टेंडर लगा और सत्ता में आते ही वर्ष-2023 इनकी सरकार ने यह टेंडर खत्म कर दिया ।

श्रीमती के0एस0द्वारा जारी .....

19.03.2026/1825/केएस/डीसी/1

श्री इन्द्र सिंह गांधी जारी ---

लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मैडिकल कॉलेज नेरचौक की क्या हालत है? आज सहारा योजना बंद है। आयुष्मान भारत कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा है। एक पूर्व प्रधान लक्ष्मण कुमार बैड पर सोया और उसकी 1 लाख 55 हजार रुपये की राशि बनी लेकिन मैडिकल कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको केवल 55 हजार रुपये ही मिलेंगे। यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है, यह बात कहां से आ गई? जबकि उसको 5 लाख रुपये तो मिलने

चाहिए क्योंकि वह एडमिट भी है। ऐसा नहीं है कि वह कहीं बाहर से दवाइयां ले रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे 1 लाख 55 हजार की जगह 55 हजार ही क्यों दे रहे हैं? वहां पर एक सिराज का व्यक्ति था, उसने मुझे शिकायत की, मैं हफ्ते में एक बार हमेशा हॉस्पिटल का चक्र लगाता हूं। ऐसी और भी बहुत सी शिकायतें हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमकेयर योजना भी नहीं चल रही है साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या जिन्होंने बाहर अल्ट्रासाउंड मशीन या सीटी स्केन की मशीन लगाई है, वे गरीब लोगों को लूट रहे हैं। ये कहते हैं कि हम करीब लोगों की चिंता कर रहे हैं,उनकी सेवा कर रहे हैं लेकिन ये कौन सी सेवा है जो आज लूट-घसूट के साथ यह प्रदेश चल रहा है? बाहर जो प्राइवेट डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं उनके साथ सीधी डील होती है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को संभालिए अन्यथा मैंने कहा कि मेरे 32 दांत हैं। जल शक्ति मंत्री पता नहीं कहां चले गए? वे कहीं जल-जंतु तो नहीं बन गए? उन्होंने कहा कि इंद्र सिंह गांधी कहता है कि मेरे 32 दांत हैं। 32 दांत होना कोई बूरी बात नहीं है और मेरे पास तो 32 गोलियां भी हैं। इसके लिए किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि लोटस होना है। यह मार्च, 2023 की बात है जब यहां सैशन चला था, उसके बाद मैंने कहा था कि लोटस होना है और वह हुआ भी। आपकी गर्दन तो यहां टेबल के नीचे घीसी बिल्ली की तरह घुस गई थी। अध्यक्ष जी, वह तो आपने संभाल लिया नहीं तो आज हम सत्ता पक्ष में होते और ये विपक्ष में होते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये तो यहां घीसी बिल्ली की तरह बैठे होते। मैं सच्चाई बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी ने जो समीक्षा की, वे अभी यहां नहीं हैं, कहीं बैठ

19.03.2026/1825/केएस/डीसी/2

कर सुन रहे होंगे, मैं चाहता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि जो आपने वहां डॉक्टरों की घोषणा की है, 45 डॉक्टर पहले वहां से भेज दिए, स्थानांतरित कर दिए और बाद में आंसू

पोंछने आ गए कि हम आपको एक-एक विभाग में और डॉक्टर देंगे। एक भी डॉक्टर नहीं पहुंचा और आज वैसी की वैसी व्यवस्था उस मैडिकल कॉलेज की बनी है। वर्ष 2022 में आदरणीय जय राम ठाकुर ने ओ0पी0डी0 चलाई थी, अच्छी व्यवस्था की थी लेकिन आज ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि लोगों को दवाइयों और टैस्ट करवाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ये कहते हैं कि हम तो स्वास्थ्य सुविधाओं का उचित प्रबन्ध कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री एक बार भी मेरे मैडिकल कॉलेज में नहीं आए। आप कभी बैठक करते, डॉक्टरों की क्लास लेते, एच0ओ0डी0 की क्लास लेते कि वह कॉलेज किस तरह से चल रहा है लेकिन आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। मुख्य मंत्री तो आए लेकिन आप वहां नहीं आए। मुझे भी बुलाया, मैं गया लेकिन जब डॉक्टरों की घोषणा करने लगे तो मैंने पूछा कि आपने यहां से 45 डॉक्टर क्यों भेजे? अब आ कर आंसू क्यों पोंछ रहे हो? स्वास्थ्य मंत्री जी आपको भी स्वास्थ्य के प्रति चिंता करनी चाहिए। जल शक्ति मंत्री जी की बात कहूं तो इनके विभाग में तो इतना बुरा हाल है पी0सी0 हैबिटेशन बटाण में 14 दिन से पानी नहीं है। यह हमारी एक स्कीम है वहां 14 दिन से पानी नहीं है। रियूर में और सरकीधार में 8-9 दिन से पानी नहीं है। मंत्री जी यहां पर नहीं हैं।

अध्यक्ष : गांधी जी, एक मिनट बैठिए। अब इस माननीय सदन की बैठक सांय 6.45 बजे तक 15 मिनट और बढ़ाई जाती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ...

19.03.2026/1830/av/dc/1

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे कनैड़ा में पानी नहीं है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दांगड़ा बस्ती में ब्राह्मण रहते हैं परंतु वहां भी पानी नहीं है। सम्लोह्ल, गुगा मंदिर बुशैर में भी पानी नहीं है। यहां पर अभी अगर जल शक्ति मंत्री जी होते तो मैं उनको बताता कि पानी कैसे दिया जाता है। मैं भी जल शक्ति विभाग में रहा हूं परंतु वे आज यहां से चले गए हैं। वहां पर सारी-की-सारी मोटर्ज खराब हैं। वहां पर जितना मोटर्ज की मरम्मत करने में पैसा लग गया उससे अच्छा तो नयी खरीदते तो वे कई वर्ष निकालती परंतु फिर

ठेकेदारों को पैसा कैसे मिलना था? मैं यह कहना चाहता हूं कि जल शक्ति विभाग में बहुत ज्यादा घपले हैं। वहां से एक एक्सियन तो हटा दिया है परंतु यहां पर आज जैसे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को हम बख्शेंगे नहीं। आज उस एक्सियन को भी नहीं बख्शना चाहिए जिसने 600 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट किया था। उसने यह कैसे किया था इस बारे में माननीय उप-मुख्य मंत्री से पूछना चाहिए। ...(व्यवधान) यहां पर बैठे ही नहीं हैं, किससे पूछना? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ख्यूरी नामक एक बहुत बड़ा गांव है जहां पर पीने का पानी नहीं है। ड्यूरा-कुम्बी में भी पानी नहीं है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राइट और लैफ्ट बैंक की दोनों सिंचाई स्कीम्ज चरमरा गई हैं। वहां कूलहों में पानी नहीं है। उन दोनों स्कीम्ज पर अरबों रुपये की राशि खर्च की गई है। वहां पर मेन कनाल जगह-जगह से टूटी हुई है। वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2025 तक जल शक्ति विभाग ने बहुत पैसा दिया परंतु वह किसको दिया गया, मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं। वहां नहर टूटने से किसी को पानी नहीं मिला। मैंने जो विधायक प्राथमिकता में एल0डब्ल्यू0एस मल्वाणा स्कीम डाली उसका कार्य भी वर्ष 2022 से चला हुआ है परंतु वह भी आज दिन तक मुक्कमल नहीं हो पाई है। उसके बारे में भी विभाग या हमारे उप-मुख्य मंत्री जी को कोई चिंता नहीं है।

बल्ह को मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। वहां पर अनेकों प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। परंतु पानी कमी की वजह से आज वहां पर किसान तरस रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले की तरह पैसा नहीं मिल रहा है। वहां पर ऐसा राइट व लैफ्ट दोनों बैंक्स की तरफ हो रहा है। वहां पर पम्प हाउसिज की इतनी बुरी हालत है कि वे एक टांग पर खड़े हुए हैं। जिस प्रकार से अंगद जी खड़े होते थे वहां पर वे पम्प हाउसिज वर्ष 2023 की आपदा के बाद उस प्रकार से टेढ़े खड़े हैं। परंतु उनकी सुद्ध कोई नहीं

19.03.2026/1830/av/dc/2

ले रहा है। ...(व्यवधान) मैं यहां पर बल्ह की बात कर रहा हूं। वहां पर खड्ड के किनारे जो तीन-चार पम्प हाउसिज बने हैं वे टेढ़े खड़े हैं परंतु मंत्री जी को उसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि उनको सीधा किया जाए।

माननीय उप-मुख्य मंत्री के पास परिवहन विभाग भी है। मेरी वहां पर सात बसिज बंद कर दी गई हैं। वहां एक बस बाया मण्डी से गागल-चण्डीगढ़-दिल्ली जाती थी। वह 26 वर्ष पुरानी बस थी जिसको बंद कर दिया गया। उसमें हमारे बच्चे व मरीज चण्डीगढ़ जाते थे। परंतु माननीय मंत्री को कोई चिंता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वे मेरी बात को अवश्य सुन रहे होंगे और यहां मेरी बातें नोट भी हो रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरी जो बसिज बंद की गई हैं उनको सुचारु रूप से चलाया जाए। वहां पर आरदणीय श्री जय राम ठाकुर ने अपने कार्यकाल में एक मुद्रिका बस चलाई थी। हमारे नेरचौक में स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। वहां पर हमारे एस0डी0एम0, बी0डी0ओ0 और तहसीलदार के कार्यालय हैं। उसके लिए 8-9 पंचायतों के लिए श्री जय राम ठाकुर जी ने एक मुद्रिका बस चलाई थी। वहां लोगों को उसकी बहुत सुविधा होती थी क्योंकि वे अपने कार्य से कार्यालयों में 9-10 बजे तक पहुंच जाते थे। परंतु उसके बंद होने से आज लोगों को वहां पहुंचने के लिए जगह-जगह पर बसें बदलनी पड़ती है जिसकी वजह से वे वहां 11-12 बजे पहुंचते हैं, तब तक डॉक्टर्ज और ऑफिसर्ज अपनी सीट से उठ जाते हैं। मेरा उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि आप उस बस को दोबारा से शुरू करें ताकि वहां पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष महोदय, कल्याण विभाग में मकान को सैंक्शन करवाने में 5000 रुपये की पत्ती लगती है। 5000 रुपये से सैंक्शन होने के बाद फिर एक किस्त मिलती है। एक किस्त के बाद अढ़ाई वर्ष तक उस व्यक्ति के बार-बार चक्कर लगवाने के बाद कहा जाता है कि यह तो टाइम-बार्ड हो गया।

टी सी द्वारा जारी

19.03.2026/1835/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री इन्द्र सिंह ... जारी

यह है व्यवस्था परिवर्तन और मैं इसकी सच्चाई बता रहा हूं। मैं उन लोगों के नाम भी बता सकता हूं जिन्होंने 5000 रुपये दिए हैं और अपना मकान सैंक्शन करवाया है। उनको एक किस्त जारी कर दी गई लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिली है। आज वर्ष 2026 चल पड़ा है। आज वे अधिकारी बदल दिए गए हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदली।

मेरे साथी सदस्य सुख आश्रय योजना की बात कर रहे थे। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक परिवार में 2 बेटियां हैं, उनके माता-पिता नहीं रहे, वे मैलोरी से हैं उनको आज तक मकान नहीं मिला है। जब पिछली बार मैंने क्वेश्चन उठाया था तो डी0सी0 महोदय रातों-रात जाकर उनको 4-4 हजार रुपये की राशि देकर आ गए और कहा कि आपकी राशि जारी हो गई। आज उनके मकान बनते हैं जो औपचारिकताएं पूर्ण करके देते हैं लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं है, वह कैसे कागज भरेंगे जो लोग अनपढ़ है। सरकार को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आश्रय योजना का मतलब है कि उन लोगों की मदद करने के लिए स्वयं पटवारी व तहसीलदार को उनके पास जाना चाहिए तब जाकर उन्हें आश्रय मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, बुढ़ापा पेंशन वाले व अपंग लोग सुबह-सुबह मेरे पास आते हैं कि हमें 4-4 महीनों से पेंशन नहीं मिल रही है जबकि सरकार कह रही है कि हम सबको पेंशन दे रहे हैं लेकिन यह सच्चाई नहीं है।

अब मैं लोक निर्माण विभाग की बात करना चाहूंगा। एक चंडयाल-सयाल पुल है जिसका निर्माण वर्ष 2022 में हुआ था लेकिन उसकी एप्रोच रोड आज तक नहीं बनी है। एक बदुआ पुल है जोकि पैडी के पास है वह भी अधूरा पड़ा है। उसमें स्लैब पड़ा हुआ है, लेकिन आगे कोई काम नहीं हुआ।

शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, हमारे एक स्कूल चैहड़ी में साइंस लैब पर वर्ष 2022 में का स्लैब पड़ा था। उसकी खिड़कियां और दरवाजे भी सड़ गए हैं लेकिन आज तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ। माननीय जय राम ठाकुर जी ने 10 लाख रुपये ने स्कूल के ग्राउंड

19.03.2026/1835/टी0सी0वी0/एच0के0-2

बनाने के लिए दिए थे लेकिन वह पैसा आज तक नहीं लगा। ...(व्यवधान) शिक्षा मंत्री जी मैं आपको बता रहा हूं, आपने जो करना है, वह करें जो नहीं करना है न करें। आपने भंगरोटू में सी0बी0एस0ई0 स्कूल खोल दिया उसमें गर्ल और बॉय को एक साथ डाल दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। इन स्कूलों को अलग-अलग कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आप भाजपा के विधायक के साथ अन्याय कर रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग में कई कल्वटर्स बने हैं लेकिन आज तक इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। मैं उन सड़कों के नाम पढ़ना चाहूंगा जो खराब पड़ी हैं यानी उनकी दशा बहुत खराब है। मेरे चुनाव क्षेत्र मे लगभग 18 सड़कें हैं जिनमें टांवां कुम्मी सड़क,भियूरा स्टोह दौहल सड़क,- रत्ती ढागू सड़क, बैहना रोपा बाड़ाधार हरिजन बस्ती सड़क, बैहना सुरनी नाला बाड़ाधार सड़क, टिक्कर मलवाणा मनसा माता मन्दिर सड़क, घट्टा छपडोहल बह सिंहन चण्डयाल सड़क। यहां लोक निर्माण निर्माण मंत्री जी ने घट्टा छपडोहल बह सिंहन चण्डयाल सड़क के संदर्भ में जबाव दिया है कि इस सड़क पर गाड़ियां चल पड़ी है। मैं हररोज इस सड़क पर सैर करने के लिए जाता हूं। लेकिन यह सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। जिन अधिकारियों ने मंत्री जी को यह सूचना दी है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा लुणापानी से हवेली माण्डल सड़क, बगला बड़सू चकराहड़ी सड़क, चक्कर मोड से गड़सौल ओटा सड़क, जीरो प्वांइट हनुमान मन्दिर से बटाहण सड़क, गम्मर पुल से पतरौण कोठीगैहरी सड़क,

एन0 एस0 द्वारा जारी

19-3-2026/1840/NS-HK/1

श्री इन्द्र सिंह------जारी

पतरौण हनुमान मन्दिर से कोठी सरध्वार दुर्गापुर सड़क, खान्धी मोड़ से छज्जवाण खाबू सड़क, मज्याहली से सुक्का रियूर कोट सड़क, धार से चहड़ी बडाणू सिध्याणी सड़कें मेरे क्षेत्र में हैं जिनकी दशा दयनीय है। मेरे कहने का मतलब है कि ये 28 सड़कें ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं और वहां पर कोई गाड़ी नहीं चलती है। बड़ी गाड़ियां तो छोड़ ही दो वहां पर छोटी गाड़ियां भी नहीं चलती हैं। अब मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के विभाग की बात करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री लोक भवन, लेदा में माननीय जय राम ठाकुर जी ने दिया। वहां पर भवन बन गया है लेकिन इस भवन की फरनिशिंग के लिए 10 लाख रुपये की जरूरत है। मैंने यह राशि सरकार से वर्ष 2023 से लेकर वर्ष 2026 तक लगातार मांगी लेकिन इस सरकार से 10 लाख रुपये नहीं मिल रहे हैं। यह भवन शराबियों और चिट्टा लेने वालों का अड्डा बना हुआ है। इस भवन की वहां पर ऐसी दशा है। वहां से वर्तमान सरकार के ए0पी0एम0सी0 के चेयरमैन गुलेरिया जी भी हैं लेकिन उनको 10 लाख रुपये लाने की हिम्मत नहीं है। वे ढींगे तो बहुत मारते हैं। मेरे क्षेत्र में वेटरनरी पी0जी0आई0 भवन, भंगरोटू में बन रहा है। उसकी भी खिड़कियों की लकड़ी सड़ गई है। उसका वर्ष 2022 में स्लैब पड़ा था लेकिन उसके बाद वहां पर एक भी पत्थर और सीमेंट का कट्टा नहीं लगा। मेरे मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पी0जी0आई0 भवन का संज्ञान लें। आप यहां पर किसानों के हितों की बात करते हैं कि हम किसानों का गोबर खरीदेंगे। आप गोबर कहां से खरीदेंगे जब पशु ही ठीक नहीं होंगे? आप जब पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाएंगे तो गोबर कहां से खरीदेंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल बल्ह में बना है और आप इसके बारे में संज्ञान लें तथा इसके सुधार के लिए पैसा दिया जाए ताकि वहां पर लोगों के पशुओं को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। यह मेरा आपसे आग्रह है। इसी प्रकार से सेकड़ नाला का चैनलाइजेशन, बैहना नाला का चैनलाइजेशन होना है और इनके भी टेंडर हो गए हैं और कार्य अवार्ड हो गया है लेकिन उनमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में आई0टी0आई0, गागल के भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। प्रदेश का सबसे बड़ा आई0टी0आई0 संस्थान आज बल्ह में बन रहा है लेकिन इसका कार्य भी अधूरा पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में नगर परिषद् वार्ड, ढांगू और वार्ड डडौर के कवाड़ मार्केट में वर्ष 2023 में त्रासदी हुई थी और वहां पर लोक निर्माण विभाग की सड़क बह गई है। वहां पर बहुत इरोजन हुआ है और

इसका मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया है। वहां पर न तो बी0बी0एम0बी0 चिंता कर रहा है और न ही जल शक्ति विभाग के अधिकारी चिंता कर रहे हैं। वहां पर नगर परिषद् के अधिकारी भी इसकी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर इस वर्ष भी भारी बरसात हो गई तो वहां पर 20 से 25 घर नष्ट हो जाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसकी भी सरकार चिंता करे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त खेल मैदान कन्सा चौक में भी भूमि कटाव हो रहा है। मेरा इसके लिए भी सरकार से निवेदन रहेगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने आगे बजट के ऊपर चर्चा में भी बोलना होगा।

श्री इन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का मजाक न उड़ाएं। मेरे सच में 32 दांत हैं और मैंने कह दिया कि अगली बार भाजपा की 60 सीटें और कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें आएंगी। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांकः 19 मार्च, 2026 **सचिव।**